खण्ड-06 सत्र -06 (भाग-02) / अंक-64 बुधवार 16 जनवरी 2018 / 26 पौष, 1939 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

छठा सत्र

अधिकृत विवरण

(सत्र-06 (भाग-02) में अंक 63 से अंक 65 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन

सचिव

C. VELMURUGAN

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editing)

fo"k; lwph

सत्र–06 भाग (02) मंगलवार, 16 जनवरी, 2018/26 पौष, 1939 (शक) अंक–64

1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	3–16
3.	बधाई प्रस्ताव (नियम–114)	17–19
4.	विशेष उल्लेख (नियम–280)	20–41
5.	अल्पकालिक चर्चा (नियम–55)... जारी (सीलिंग से उत्पन्न मद्दों पर)	42–115
6.	प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण	116–117

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–06 भाग (02) मंगलवार, 16 जनवरी, 2018 / 26 पौष, 1939 (शक) अंक–64

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री महेन्द्र गोयल
7. श्री सुखवीर सिंह दलाल
8. श्री ऋतुराज गोविन्द
9. श्री संदीप कुमार
10. श्री रघुविन्द्र शौकीन
11. श्रीमती बंदना कुमारी
12. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
13. श्री राजेश गुप्ता
14. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
15. श्री सोमदत्त
16. सुश्री अलका लाम्बा
17. श्री आसिम अहमद खान
18. श्री विशेष रवि

19. श्री हजारी लाल चौहान
20. श्री शिव चरण गोयल
21. श्री गिरीश सोनी
22. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
23. श्री जरनैल सिंह
24. श्री राजेश ऋषि
25. श्री महेन्द्र यादव
26. श्री आदर्श शास्त्री
27. श्री कैलाश गहलोत
28. कर्नल देवेन्द्र सहरावत़
29. सुश्री भावना गौड़
30. श्री सुरेन्द्र सिंह
31. श्री विजेन्द्र गर्ग
32. श्री प्रवीण कुमार
33. श्री मदन लाल
34. श्री सोमनाथ भारती
35. श्रीमती प्रमिला टोकस
36. श्री नरेश यादव
37. श्री करतार सिंह तंवर
38. श्री अजय दत्त
39. श्री दिनेश मोहनिया
40. श्री सौरभ भारद्वाज
41. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
42. श्री सही राम
43. श्री नारायण दत्त शर्मा
44. श्री अमानतुल्लाह खान
45. श्री राजू धिंगान
46. श्री मनोज कुमार
47. श्री नितिन त्यागी
48. श्री ओम प्रकाश शर्मा
49. श्री एस.के. बग्गा
50. श्रीमती सरिता सिंह
51. मो. इशराक
52. श्री श्रीदत्त शर्मा
53. चौ. फतेह सिंह
54. श्री जगदीश प्रधान

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–06 भाग (02) मंगलवार, 16 जनवरी, 2018/26 पौष, 1939 (शक) अंक–64

lnu vijkgu 2-00 cts leosr gqvkA

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

अध्यक्ष महोदयः सभी माननीय सदस्यों का स्वागत है।

मुझे श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष से नियम–54 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण की सूचना प्राप्त हुई है। आज कार्यसूची में दो अल्पकालिक चर्चाएं सूचीबद्ध हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी...

अध्यक्ष महोदयः एक सैकिण्ड... कल शोर–शराबे में सदन का समय व्यर्थ हुआ है। सदन के समय के अधिकतम सदुपयोग के लिए कार्यसूची में सूचीबद्ध विषयों के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर विचार नहीं किया जा सकता। इसलिए उक्त सूचना को मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, एलओबी में...

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ...ये जो इतना महत्वपूर्ण मामला है दिल्ली के लोग मर रहे हैं सड़कों पर...

अध्यक्ष महोदयः नियम 114

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, देखिये...

अध्यक्ष महोदयः देखिये, विजेन्द्र जी...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप हर बार हमें क्यों मजबूर करते हैं...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं इस विषय को...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, मैंने जो रूलिंग दी है, मैंने जो रूलिंग दी है।

...(श्री कपिल मिश्रा बैनर लेकर नारेबाजी करते हुए सदन के वेल में आये।)

अध्यक्ष महोदयः आप अपने स्थान पर बैठिये कपिल जी।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप अपने स्थान पर बैठिये कपिल जी।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप अपने स्थान पर बैठिए। आप अपने स्थान पर बैठिए। आप अपने स्थान पर बैठिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आपसे कह रहा हूं आप अपने स्थान पर बैठिये।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप स्थान पर बैठिये।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप अपने स्थान पर बैठिये

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं आपसे... आप सदन में बैठिये।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप अपनी कुर्सी पर बैठिये।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप अपनी कुर्सी पर बैठिये।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं आपसे कह रहा हूं आप कुर्सी पर बैठिये। मार्शलस बाहर लेकर जायें ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बाहर लेकर जाये इसे।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः तेरे से पूछ के भेजेगें? ले जाइये उठाकर बाहर।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कैसे ले जायेगें!

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः लेकर जाइये।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः वो जा रहे हैं आप आराम से? आप देख रहे हैं, वो जा रहे हैं आराम से?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः वो जा रहे हैं आराम से? उनको खुद चले जाना चाहिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः उनको खुद चले जाना चाहिए। उनको खुद चले जाना चाहिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः ये कोई तरीका है?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी, इनको बाहर जाने दीजिये।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी, आप बाधा मत पहुंचाइये इसमें।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी, मैं वार्निंग दे रहा हूं आप बाधा मत पहुंचाइये। सिरसा जी, में वार्निंग दे रहा हूं। सिरसा जी, मैं वार्निंग दे रहा हूं आप बाधा मत पहुंचाइये। सिरसा जी, मे। आपको वार्निंग दे रहा हूं। सिरसा

जी, सिरसा जी, आप बाधा पहुंचा रहे हैं। आप कानूनी कार्रवाई में बाधा पहुंचा रहे हैं। आप सदन की कार्यवाही में में बाधा पहुंचा रहे हैं। आप सदन की कार्यवाही में अध्यक्ष के आदेश पर आप बाधा पहुंचा रहे हैं।

(मार्शल्स द्वारा माननीय सदस्य श्री कपिल मिश्रा को बलपूर्वक सदन से बाहर निकाला गया।)

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी को बाहर करें। सिरसा जी को बाहर करें मार्शलस, बाहर करें सिरसा को बाहर करिये सिरसा को। बाहर करिये इसको। तुरंत बाहर करिये। बाहर करिये, सिरसा को बाहर करिये।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप अध्यक्ष के आदेश में बाधा पहुंचा रहे हैं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप मार्शलस को रोक रहे हैं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सिरसा को बाहर करें।

... (व्यवधान)

(मार्शल्स द्वारा माननीय सदस्य श्री मनजिंदर सिंह सिरसा को सदन से बाहर निकाला गया।)

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्य बैठें माननीय सदस्य बैठें।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्य बैठें।

अध्यक्ष महोदयः सभी, संजीव झा जी, अपनी कुर्सी पर चलिये।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः राजेश, अपनी कुर्सी पर चलिये सब सब माननीय सदस्य चलें।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं... बैठ जाइये, बैठ जाइये आप। मैं रूलिंग दे रहा हूँ इस पर बैठिये। बैठ जाइये।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठिये, बैठिये, बैठ जाइये। प्लीज बैठ जाइये, बैठ जाइये प्लीज।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः राजेश जी, आप बैठते हैं, नहीं बैठते? आप बैठिए प्लीज।

... (व्यवधान)

अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नितिन जी, बैठिए प्लीज। नितिन जी आप बैठिए प्लीज। बैठिए–बैठिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः ये बैठिए प्लीज। राजेश जी, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं बैठ जाइए। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बैठ जाइए...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं तीसरी बार प्रार्थना कर रहा हूं बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः तमाशा, नितिन जी बैठिए। नितिन जी बैठिए प्लीज। मैं सदन के बीच में इस बात से बहुत आहत हुआ हूं। अध्यक्ष के आदेश में मार्शल्स के रास्ते को बाधा पहुंचाई सिरसा जी ने। मैं सारा वो...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः एक सैकेंड बैठ जाइए नितिन जी। आप चुप हो जाइए नितिन जी।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप चुप होते है, नहीं? मैं बार–बार कह रहा हूं चुप हो जाइए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः व्यवहार गलत था।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप अध्यक्ष पर टिप्पणी कर रहे है। आप अध्यक्ष पर बार–बार टिप्पणी कर रहे है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः हां बोलिए, जो मर्जी आए बोलिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं सिरसा जी के इस व्यवहार को...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं बैठें प्लीज।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः प्लीज बैठिए। मैं माननीय सदस्यों से...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः प्लीज बैठ जाइए। जगदीश जी बैठ जाइए। जगदीश जी बैठिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः प्लीज बैठ जाइए। ओम प्रकाश जी आप बैठ जाइए। मैं आपको वॉर्निंग दे रहा हूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठ जाइए आप। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं बैठ जाए। मेरे व्यवहार में कहां गलती थी, मुझे बताइए? मेरे व्यवहार में क्या गलती थी बताइए? बैठ जाइए आप। आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैंने अपने व्यवहार में क्या गलत शब्द बोला? आप बैठ जाइए बिल्कुल, मैंने कोई शब्द नहीं गलत बोला।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः ना, मैंने अपनी चेयर के अनुरूप बोला है। कोई गलत शब्द नहीं, आप बैठ जाए, कोई गलत शब्द मैंने नहीं बोला है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अजय दत्त जी, आप बैठते है नहीं बैठते?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, बैठते है नहीं बैठते?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठिए प्लीज। प्लीज बैठिए। बैठिए प्लीज बैठिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं सिरसा जी के इस व्यवहार से...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः ऋतुराज जी, ऋतुराज जी...

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, मेरा...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी दो मिनट बैठ जाइए। मैं कोई रूलिंग दे रहा हूं, प्लीज बैठ जाइए आप। आप बैठ जाइए प्लीज।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप बैठ जाइए प्लीज। आप बैठ जाइए प्लीज। आप गलत बयानबाजी कर रहे है। किसी ने नहीं मारा, किसी ने हाथ नहीं छोड़ा।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः वो स्वयं... बैठ जाइए आप। आप बैठ जाइए। आप तमाशा बना रहे है, आप बढ़ावा दे रहे हैं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अजय दत्त जी, बैठ जाइए आप। मैं संभालने के लिए बहुत हूं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं रूलिंग दे रहा हूं ये विषय सिरसा जी का...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हमारा ये कहना है अध्यक्ष जी ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी ने आज मेरे आदेश का पालन करने में मार्शल्स को बाधा पहुंचाई है। मैं यह विषय प्रिविलेज कमिटी को सौंप रहा हूं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः एक सैकेंड रूक जाइए, आप मत बोलिए। सोमदत्त जी, या तो आप चला लीजिए या मुझे चला लेने दीजिए। मैं बार–बार प्रार्थना कर रहा हूं, नहीं समझ रहे है आप लोग।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, आपके आदेश...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, मेरी बात सुनिए। आप इस बात पर कायम है कि उसको मारा गया मार्शल्स द्वारा? नहीं, स्टेटमेंट दीजिए आप।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, आप इस बात पर, मैं पूछ रहा हूं आपसे।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आपने अभी शब्द बोला कि उसको मारा गया मार्शल्स द्वारा।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हमने...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आपने बोला मारा गया।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं–नहीं, आपने अभी बोला मारा गया। आप अपने शब्द वापस लेते हैं? आपने बोला मारा गया। ओम प्रकाश जी ने बोला, मैंने दुर्व्यवहार किया।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः हां, आपने बोला अध्यक्ष पर उंगली उठाकर कि मैंने दुर्व्यवहार किया। आप इस कुर्सी के लायक नहीं है। आप अपनी कुर्सी के अनुरूप व्यवहार करें। आपने बोला है अभी।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आपने बोला है अभी। आपने बोला है अभी मुझे। आपने बोला कि आपने दुर्व्यवहार किया है, अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल कर रहे है।

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः आप शब्द जो बोल रहे है इसके अनुरूप नहीं है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः ठीक है। मैंने कौन सा शब्द बोला है?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः एक सैकेंड रूकिये।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः सदस्य के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः किसके साथ?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः जब मुझे एक बात बताइए अगर ये कहा जाता है अध्यक्ष की कुर्सी से कि कपिल मिश्रा जी आप बाहर चले जाएं। मार्शल्स को बुलाया, उसके बाद, उसके बाद मानना चाहिए और आप उसको बढ़ावा दे रहे है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः तीनों लोग खड़े होकर उसका रास्ता रोक रहे है माशल्स को।

श्री ओम प्रकाश शर्माः अमानवीय है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कोई अमानवीय नहीं है। जब वो जमीन पर लेट रहा है, जा नहीं रहा, ये सदन ऐसे नहीं चल सकता। जो मर्जी आए, कुर्सी पर खड़ा हो जाए, जो मर्जी आए जिसके लिए जो बोल दे। अमानवीय व्यवहार है! आज आपको अमानवीय व्यवहार याद आ रहा है...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठ जाइए प्लीज। मुझे...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अमानवीय व्यवहार हुआ।

अध्यक्ष महोदयः मुझे बड़ी पीड़ा होती है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अगर मान लीजिए अध्यक्ष की कुर्सी से...

अध्यक्ष महोदयः मैं अध्यक्ष की कुर्सी से जिस ढंग से सिरसा का व्यवहार था, उसको वहां से कुर्सी से हटकर उन्होंने मार्शल्स को रोका, उन्होंने मार्शल्स को रोका।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः ये इतना व्यवहार गलत था जो गैर कानूनी व्यवहार था। आप समर्थन कर रहे है!

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता: सर जमीन पे लग रहा था ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सर जमीन पे लग रहा, वो जमीन पर क्यों लेट रहे थे। आप कुर्सी पर खड़े हो जाएंगे, वो जमीन पे लेट जाएगा। आप चेयर पे, डेस्क पे खड़े हो जाएंगे!.

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता: अध्यक्ष जी, ये अमानवीय व्यवहार था ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, आप डेस्क पे खड़े होते है, ये अमानवीय व्यवहार नहीं, वो जमीन पे लेट गया वो अमानवीय व्यवहार नहीं? आपको हर बात अमानवीय व्यवहार दिखाई देता है!

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप बैठते हैं, नहीं बैठते? नहीं, आप बैठते है, नहीं बैठते? आप बैठते है नहीं बैठते अखिल जी, अखिल जी, त्रिपाठी जी आप बैठ रहे है नहीं?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नितिन जी बैठ जाइए प्लीज। मैं रूल नियम 114 के अंतर्गत...

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता: अध्यक्ष जी, मेरा ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नितिन त्यागी जी का मुझे...

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः सर 44 मौतें हो गई सड़क पे। मुख्यमंत्री जी खुद ट्वीट करके मान रहे है कि हमारी गलती है ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः चलिए।

बधाई प्रस्ताव (नियम–114)

श्री नितिन त्यागीः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 114 के अंतर्गत मेरे को बोलने का मौका दिया ... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः इस मामले को ... (व्यवधान)

श्री नितिन त्यागीः अभी कल की एक खबर है...

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः दिल्ली में लोगों की मौत हो रही है (व्यवधान)

श्री नितिन त्यागीः और बहुत ही हर्षित हो के मैं आप सबके सामने ये बात रखना चाहता हूं ... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः सदन के अंदर अगर इस बात पे चर्चा नहीं होती है अध्यक्ष जी, ... (व्यवधान)

श्री नितिन त्यागीः कि एल जी साहब ने ... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः शर्म की बात है सरकार के.... सरकार जवाब दें। ... (व्यवधान)

श्री नितिन त्यागीः 40 सेवाएं जिसमें की होम डिलीवरी, डोर स्टेप डिलीवरी सर्विसज के लिए ... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता: अध्यक्ष जी, ये गंभीर मामला है, 44 ... (व्यवधान)

श्री नितिन त्यागी: ओ.के. किया दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को।

... (व्यवधान)

श्री नितिन त्यागी: इसमें ऐसी सर्विसिस हैं जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाणपत्र, अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र, एसटी प्रमाणपत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाणपत्र, (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता: ... (व्यवधान)

श्री नितिन त्यागी: निलंबित जन्म आदेश, विलंब मृत्यु आदेश, लाल डोरा प्रमाणपत्र इस तरीके के 40 सुविधाएं जिनके लिए लोगों को सड़कों पर धक्के खाते घूमना पड़ता था। कभी कहीं पे एटेस्टेशन कराना है, कभी किसी खिड़की पे जाना है।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता: ... (व्यवधान)

श्री नितिन त्यागी: कभी किसी के हाथ जोड़ने है, किसी के पैर पड़ने है, एक छोटे–छोटे से कागज, छोटी–छोटी सी सेवाएं जो लोगों के लिए बहुत जरूरी होती हैं। कभी पेंशन के लिए जरूरी होती है, कभी एडमिशन के लिए जरूरी होती है, कभी नौकरी के लिए जरूरी होती हैं।

... (व्यवधान)

श्री नितिन त्यागी: कभी राशन कार्ड के लिए जरूरी होती हैं, कभी इलाज के लिए जरूरी होती हैं। कभी इसके बारे में सोचा नहीं गया और एक अहसान की तरह से हमेशा ये दी गई हैं चीजें। पहली बार एक सरकार

दिल्ली में ऐसी आई है कि लोगों को हक की तरह से ये चीजें मिलेंगी। ये सोच के बारे में देखिए! सोच के बारे में देखकर अचम्भित होंगे आप कि ये सेवाएं लोगों के घर तक पहुंचेंगी और आज देखिए ये छोटी–छोटी सी चीजें हैं, आय प्रमाणपत्र! आय प्रमाणपत्र कोई पैसे वाला नहीं बना रहा। आय प्रमाणपत्र वो बनवाते हैं जिनकी इन्कम बहुत कम होती है और ये दिल्ली सरकार हर उस आदमी के बारे में सोच रही है जो मजबूर है। इसके लिए मैं दिल्ली सरकार को बहुत–बहुत बधाई देना चाहूंगा। सीएम साहब को, उनके पूरे केबिनेट को बधाई देना चाहूंगा। ये, और एलजी साहब को भी बधाई देना चाहूंगा, ये जो सर्विसिज, डोर स्टेप सर्विस उन्होंने चालू करवाई है, इससे मुझे लगता है कि हर तबके में उत्साह बढ़ेगा, जो लोगों की परेशानी होती थी; चक्कर काटने की, गली–गली घूमने की, कभी विधायक के दफ्तर जा रहे हैं, कभी पार्षद के दफ्तर जा रहे हैं, कभी किसी से फोन करवा रहे हैं! ये सब बंद होगा। ये जो सड़ा हुआ गुड़ पॉलिटिशियन की कुर्सी के आसपास होता है और मक्खियॉ भिनभिनाती हैं, ये उसे हटाने का एक बहुत बड़ा कदम है और मुझे ऐसा लगता है कि जो है डिसैंटरलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये यहां से शुरू होता है और जनता तक ये सत्ता पहुंचती है, जनता को ये हक मिलता है कि ये जो चीजें उनको हक के हिसाब से मिलनी चाहिए, एहसान की तरह से न मिले और लोगों तक और उनके घर तक जो मजबूर होता है, आप खुद सोचिए वो कितनी मजदूरी करता है, वो आदमी बहुत कम पैसे कमाता है तब जाकर आय प्रमाणपत्र बनाना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदयः कन्कलूड करिए नितिन जी, कन्कलुड करिए, प्लीज।

श्री नितिन त्यागीः अब वो उसके घर पे वो आय प्रमाण–पत्र पहुंचे, वो सेवा उसके घर तक पहुंचे ये एक बहुत अच्छा कदम है दिल्ली सरकार

का और हम सराहना करते हैं और मैं कॉग्रेचुलेट करना चाहूंगा, बहुत ही साधुवाद देना चाहूंगा अरविन्द केजरीवाल जी और उनके पूरे केबिनेट का कि इस तरीके की सोच को आगे बढ़ाया उन्होंने। बहुत–बहुत धन्यवाद।

विशेष उल्लेख (नियम–280)

अध्यक्ष महोदयः 280, श्रीदत्त शर्मा जी।

श्री श्रीदत्त शर्माः माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आापने 280 के अंतर्गत बोलने का मुझे मौका दिया।

महोदय, मेरी विधान सभा में अब से लगभग 40 साल पहले एक डिसपैन्सरी होती थी और वो 30–35 साल बराबर काम करती रही। अब से 8–7 साल पहले उसकी जर्जर हालत होने के कारण उसको तोड़ दिया गया, लेकिन जब से लेके अब तक उसका दुबारा से निर्माण नहीं हो पाया है और मुझे जब भी विधान सभा में बोलने का मौका मिला, विधान सभा में भी बोला हूं। आदरणीय मंत्री जी के पास में कई बार जा चुका हूं। एक तरफ तो हमारी सरकार जगह ढूंढ रही है। एक तरफ सरकार के पास स्वास्थ्य विभाग की जगह होते हुए भी वहॉ पर डिस्पैंसरी का निर्माण नहीं हो रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से निवदेन है, माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं कि जल्दी से जल्दी इसका निर्माण कराया जाए, जिससे कि. वहां के लोगों को इसकी सुविधाएं मिल सके।

अध्यक्ष महोदयः अनिल कुमार बाजपेयी जी।

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः सर मैं आपका ध्यान गाँधी नगर में मार्किट की ओर दिलाना चाहता हूँ।

आदरणीय सर, यहां पर पार्किंग की एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे यहां मार्किट में है। पूरे देश से लोग और देश के जिले के हर हिस्से से लोग वहां पर शॉपिंग करने के लिए आते है। चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे तमिलनाडु हो। दिल्ली के भी काफी लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं, छोटे और बड़े वर्ग के सभी लोग। लेकिन सर, वहां पर पार्किंग की कोई भी सुविधा वहां पर अवेलेबल नहीं है। जो पार्किंग स्पेस ईडीएमसी ने अलॉट किया हुआ है वो सर मुश्किल से 100 या 150 मीटर है लेकिन सारी पार्किंग पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। माननीय जैन साहब यहां उपस्थित हैं। मैंने आपका भी कई बार ध्यान दिलाया था और पीडब्ल्युडी की रोड है सर वहां पे। पूरी पीडब्ल्यूडी की रोड पर, पूरी एंक्रोचमैंट है। माननीय लैफ्टीनैण्ट गवर्नर साहब जो हैं... अनिल बैजल साहब उन्होंने भी विजिट किया था और विजिट करने पर पूरा इलाका उन्होंने विजिट किया, मैं भी व्यक्तिगत रूप से उनसे मिला था, दस दिन के लिए केवल एंक्रोचमैंट केवल हटाई गई। उसके बाद जो पुश्ता रोड पे पूरी सर्विस रोड है, पूरी सर्विस रोड के ऊपर वहां पर कब्जा है, लोगों ने बड़े–बड़े गोदाम ओन रोड बना लिए हैं और जिससे वहां पर निकलने वाले लोगों को और जो व्यापारी आते हैं उनको काफी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।गाँधी नगर मेन रोड के ऊपर भी हमारी रोड है। उस रोड के ऊपर भी लोगों ने एंक्रोचमैंट किया हुआ है। मैंने कई बार अधिकारियों को भी ध्यान दिलाया लेकिन इसमें बिल्कुल सारा हाल बेहाल है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये आती है कि जब हम उनसे बात करते हैं वो कहते हैं कि एसडीएम,एसटीएफ करेगा ये। सबसे बड़ी दिक्कत गाँधी नगर में ये आ रही है, माननीय कैलाश गहलोत साहब भी यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने भी इस संबंध में काफी कोशिश की है। माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी हमने कहा है। क्योंकि हमारा जो एसडीएम ऑफिस है, वो सर, विवेक विहार में है लेकिन अभी कैलाश गहलोत साहब

से उस दिन भेंट हुई है, उन्होंने बताया है कि वो हम लोगों का वहां शिफ्ट हो गया है लेकिन मैं गहलोत साहब को कहूंगा कि आप डिप्टी कमिश्नर को और माननीय जैन साहब बैठे हैं, अगर आप पीडब्ल्यूडी के उच्च अधिकारियों को अगर आदेश दें तो वो सर, सारी सर्विस लाइन साफ हो जाएगी और अगर पार्किंग का है तो शास्त्री पार्क हमारे वहां बिल्कुल नजदीक का एरिया है, माननीय लैफ्टीनैण्ट गवर्नर साहब ने भी कहा था इसके लिए कि यहां पर शास्त्री पार्क में हमगाँधी नगर के व्यापारियों के लिए यहां पर पार्किंग बना देंगे। अगर सर, वहां पर एक पार्किंग बन जाती है तो गाँधी नगर के व्यापारियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे, क्योंकि आप गाँधी नगर से अधिक भलीभांति परिचित भी है और आपके संबंध भी हैं गाँधी नगर के मार्किट के लोगों से, मैं चाहूंगा आप इसका संज्ञान लेते हुए हम लोगों की कुछ मदद करें, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद, धन्यवाद। भावना गौड़ जी।

सुश्री भावना गौड़ः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान पालम विधान सभा क्षेत्र की जेजे कालोनी; सैक्टर–1 और सैक्टरी–7 की ओर दिलाना चाहती हूं जिसे दिल्ली सरकार ने अपनी जमीन पर बसाने के बाद में उसे सीधा–सीधा एमसीडी को हैंड ओवर कर दिया। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा पालम विधान सभा क्षेत्र में बसाई गई जेजे कालोनियों को दिल्ली नगर निगम के हैंड ओवर किया गया था। लेकिन लगभग 15 से 20 सालों में दिल्ली नगर निगम द्वारा इन कालोनियों में विकास की बात तो दूर, सही तरीके से रखरखाव अर्थात् मैंटिनेंस के काम भी वहां पर नहीं किए गए। इतना ही नहीं इन कालोनियों के पास स्थिति पार्कों पर अवैध कब्जे हो गए हैं, कुछ जगह नए शैडस डाल दिए गए है। इसीलिए उक्त जेजे कालोनी

सैक्टर–1 और जेजे कालोनी सैक्टर–7 के निवासी चाहते हैं कि उनकी कालोनियों को दिल्ली सरकार के हैंड ओवर कर दिया जाए ताकि वहां पर मैंटीनेंस के काम और विकास के काम हो पाएं।

अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि पालम विधान सभा की जेजे कालोनी सैक्टर–1 और सैक्टर–7 को दिल्ली सरकार के अधीन लिया जाए और आवश्यक कार्रवाई करवाने की कृपा करें ताकि इन कालोनियों में आवश्यक एवं नियमित रखरखाव के साथ–साथ यथासंभव अधिक से अधिक विकास कार्य किए जा सकें और नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें।

अध्यक्ष महोदय, ये केवल मेरी पालम का ही मामला नहीं है, हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनकी विधान सभाओं में रिसैटलमैंट कालोनियाँ हैं जिसे दिल्ली सरकार की जमीन के ऊपर बसाया गया और उसके बाद में उस पर दिल्ली सरकार ने अपना खर्च करके लोगों को बसाकर के वो कालोनियाँ सीधा–सीधा दिल्ली नगर निगम को हैंड ओवर कर दीं। पिछले 15–20 सालों से लोगों के बीच में वो मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाई हैं। लोग लगातार हमसे सम्पर्क बनाएं हुए हैं लेकिन जब तक ये कालोनियाँ सीधे–सीधे हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आतीं, तब तक हम इनमें कोई भी रख–रखाव का कार्य नहीं कर सकते, बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री प्रवीण कुमार जी।

श्री प्रवीण कुमारः माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, आज का जो इशू है मेरा, वो बहुत इम्पोर्टेण्ट है क्योंकि एक मेरे यहां एक पुश्तैनी पार्किंग बन रही है एमसीडी की, पुश्तैनी इसलिए

कि पिछले 8 साल से वो पार्किंग लगातार बन रही है और न जाने कितने कॉन्ट्रेक्टर चेंज हो गए और न जाने कितने जेई चेंज हो गए, एई चेंज हो गए, डीसी चेंज हो गए लेकिन आज तक वो पार्किंग बन के तैयार नहीं हुआ। 80 करोड़ की पार्किंग बननी थी लेकिन पिछले साल उसका 104 करोड़ रुपए, अब वो जो है 200 करोड़ रुपए का उसका बजट हो गया लेकिन उसके बावजूद भी वो पार्किंग बनके तैयार नहीं हुई है। अब यहां पे जनता ये जानना चाहती है कि वो पार्किंग अगर बनके तैयार नहीं है तो सारा पैसा जा कहाँ रहा है? पिछले आठ साल से वो पार्किंग बन रही है थ्री लेवल, मल्टीलेवल पार्किंग बन रही है तीन बेसमेंट हैं उसमें लेकिन उसके बावजूद भी पार्किंग अभी तक बन के तैयार नहीं हुई है। यहां तक दिल्ली सरकार एमसीडी को पैसा देती है, दिल्ली सरकार एमसीडी को पैसा देती है उनकी मैंटेनेन्स, उनकी सारी चीजों के लिए लेकिन उसके बावजूद यहां पर कमिश्नर आने को तैयार नहीं होते, कमिश्नर यहां पे, सौरभ भाई ने कल बहुत बढ़िया बात उठाई कि हम यहां पे मुद्दे तो उठा देते हैं लेकिन मुद्दों का सॉल्यूशन अगर एमसीडी के कमिश्नर को देना है तो एमसीडी के कमिश्नर को यहां पे तलब करना पड़ेगा। अदरवाइज यहां पे मुद्दे उठाने का, मुझे लगता है कि जब तक वो यहां पे आके जवाब नहीं देंगे, इन सारे मुद्दों का आउट कम नहीं है क्योंकि ये सदन उनके पैसे देता है। ये सदन यहां से पैसे पास होते हैं, तब उनकी तनख्वाह मिलती है, तब उनके पास ये काम करने के पैसे आते हैं। अगर ये सारा पैसा उनके भ्रष्टाचार में चला जा रहा है तो यहां से पैसे देने से कोई मतलब नहीं है, मुझे लगता है। और अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो यहां पे एमसीडी कमिश्नर एसडीएमसी के कमिश्नर को यहां पे तलब किया जाए और उनसे पूछा जाए कि पिछले 8 साल से जो पार्किंग यहां पे बन रही है, वो आठ साल के बावजूद तीन बार उसका बजट बढ़ चुका है लेकिन उसके बावजूद बनके तैयार क्यों नहीं हुई?

दूसरी चीज, एक तो जिस तरीके से डोर स्टेप डिलीवरी एक थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। डोर स्टेप डिलीवरी जो दिल्ली सरकार ने आज यहां पे शुरू की है, ये अभूतपूर्व स्टेप है अध्यक्ष महोदय। इसके लिए दिल्ली सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि

अध्यक्ष महोदयः वो हो गया विषय, आ गया अब। वो हो गया, हो गया प्लीज।

श्री प्रवीण कुमारः बीजेपी, कॉंग्रेस वाले तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि यहां पर इस तरीके से की कोई योजना लाई जा सकती है। बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः वो हो गया विषय। श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को लेकर के लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। सत्ता में आए हुए तीन वर्ष से अधिक हो गए लेकिन स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। जिसके कारण बसों की कमी के कारण प्राइवेट व्हीकल्स का ज्यादा सड़क पर उतरना और इस सारी स्थिति को निपटने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 1 नवम्बर, 2015 में सरकार को इस पूरी समस्या का समाधान करने के लिए एक आदेश दिया और सिर्फ आदेश नहीं दिया, बल्कि धन की भी व्यवस्था करके दी और एक एंवायरमेंट कम्पन्सेशन सेस, ये जो क्षतिपूर्ति जो ये सेस था, शुल्क, ये लगाया गया। जो बाहर से वाहन आते हैं और दिल्ली से बाहर से आने वाले वाहन जो लदे हुए हैं लोड्डिड हल्के वाहन है, उन पर 1400 रूपये पर एन्ट्री हल्के खाली वाहनों पर 700 रूपये और लदे हुए जो हैवी व्हीकल्स हैं, उन पर 2600 रूपये पर एन्ट्री और बिना लदे हुए वाहनों पर 1300 रूपये। तो ये पर एन्ट्री पर ये कम्पन्सेशन सेस लगाया गया और सुप्रीम

कोर्ट ने ये कहा कि ये पैसा दिल्ली सरकार दिल्ली में पॉल्यूशन को कम करने के लिए खर्च करे और हर तीन महीने में हमारे पास क्या, कितना पैसा आया और कैसे खर्च किया गया, उसका हिसाब भी अप्राइज कराए सुप्रीम कोर्ट को। बड़े दुःख की बात ये है कि इन दो वर्षों में लगभग 1200 से 1300 करोड़ से अधिक दिल्ली सरकार को प्राप्त हुआ। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि एक भी रूपया दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए खर्च नहीं किया गया। एक भी रूपया खर्च नहीं किया गया, पूरा प्रदूषण बढ़ता गया। पैसा जमा होता गया और स्थिति ये आई कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को खुला उल्लंघन हुआ दिल्ली में। हमारा साफ रूप से कहना है कि दिल्ली में बसें खरीदी जा सकती थी। कुछ इस तरह के प्यूरीफॉयर लगाए जा सकते थे। जिससे कि दिल्ली के पॉल्यूशन को... लेकिन ये सरकार दिल्ली के प्रदूषण को कन्ट्रोल करने में पूरी तरह विफल सिद्ध हुई है और उसके लिए कोई राजनीतिक इच्छाशक्ति भी सरकार की तरफ से दिखाई नहीं दी। जिसके कारण स्थिति ये बनी कि दिल्ली के अन्दर लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। मैं चाहूंगा इसके ऊपर अगर क्योंकि ये जनहित का एक बड़ा मामला है, लोगों की सांसों से जुड़ा हुआ मामला है। दिल्ली में प्रदूशित पानी है, दिल्ली में प्रदूशित हवा है। सांस लेने के लिए भी हम लोग मजबूर हैं प्रदूषण के साथ। इस पर मंत्री जी अगर बताएं कि वो प्रदूषण को लेकर के क्या कार्रवाई कर रहे हैं और विशेश रूप से एन्वायरन्मैंट कम्पन्सेशन सेस को लेकर के सरकार ने इन तमाम घटनाओं के बावजूद भी क्या कोई योजना बनाई है या फिर ये पैसा खर्च क्यों नहीं हुआ, अगर मंत्री जी इस पर बतायेंगे तो मुझे लगता है कि इसके बारे में पूरा सदन अवगत होगा और प्रदूषण जैसी बड़ी समस्या का समाधान होने की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद, श्री राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ताः अध्यक्ष जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद, आपने 280 के तहत सवाल उठाने का मौका दिया जो अपने विधानसभा में हमारे को दिक्कतें होती है, उसमें हम सवाल उठाते हैं और जहां तक मेरी जानकारी है इसमें मंत्री जी खड़े होकर जवाब भी नहीं देते। तो मैं लेकिन जो दिक्कत है, वो बताए देता हूं कि जैसे अभी हमारे बड़े भाई ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत है और मेरी विधानसभा वजीरपुर में पिछले 12 दिनों से एक ऐसा पार्ट है जिसके अन्दर पानी की बिल्कुल भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। जिसका एक जो कारण बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि अत्याधिक अमोनिया यमुना के अन्दर आया हुआ है। इसलिए उस पानी की सप्लाई नहीं करी जा सकती और आज के अखबार में भी ये आया है कि इस समस्या की वजह से दिल्ली में 30 परसेंट से 50 परसेंट आबादी बिना पानी के रह रही है जिसको बहुत दिक्कत हो रही है। मेरा पहला सवाल ये है कि जो इतना अमोनिया हरियाणा से आ रहा है, अभी तक हरियाणा सरकार ने इस पर क्या किया, क्या कार्रवाई हुई, ये सदन के आगे जरूर आना चाहिए क्योंकि जितने विधायक यहां बैठे हैं अगर उनकी 50 परसेंट आबादी इस समस्या से ग्रसित है तो जरा पता लगे कि हर साल ये अभी की कहानी नहीं है, ये लगातार कई सालों से हमारी सरकार से पहले जो सरकार थी, उसके टाइम पर भी ये होता रहा है। तो ये जरूर पता लग पाए कि दिल्ली के निवासियों को जितनी दिक्कत हो रही है या ये कोई सोची समझी रणनीति है इन्हें प्यासा मारने की कि प्रदूषण के नाम पर ये कहा जाए कि दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही। जबकि ये सारा का सारा अमोनिया यमुना से होते हुए दिल्ली के अन्दर आ रहा है।

दूसरा मेरा निवेदन ये है कि जब कभी भी ऐसी समस्या होती है एक तो गला खराब कर देते हैं आकर के इतना मत चिल्लवाया करो, बोल नहीं

पाते। तो जब कभी भी ऐसी कोई समस्या हो... तो जिस तरीके से टीपीडीडीएल जब दो घंटे भी लाइट काटता है तो उसकी मुनादी कराता है, एसएमएस देता है। समस्या ये है कि हम लोग अखबारों में निकाल रहे हैं जो जल बोर्ड ने करा, अब जिस आबादी को ये पानी नहीं मिल रहा है मोटे तौर पे जैसे मेरे यहां की झुग्गी की आबादी है, उसको जानकारी मिली ही नहीं पाती है, वो अखबार नहीं पढ़ती है। तो मेरा निवेदन इसके अन्दर ये है कि एसएमएस दिए जाएं, मुनादी करवाई जाए और हो सके तो जल बोर्ड एक ऐसी पीसी करे जिसको टीवी वाले कम से कम दिखाएं कि आखिर समस्या क्या है। लोगों को अभी तक 12 दिन हो गए है ये पता नहीं लग पा रहा है कि कार्यकर्त्ताओं के माध्यम से बताने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि ये मेरा निवेदन है बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद, श्री संजीव झा जी।

श्री संजीव झाः बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे 280 के तहत अपनी समस्या रखने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, यहां पर उर्जा मंत्री है, उनका ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे यहां बिजली की बहुत समस्याएं है और मैं बार–बार सदन में हमारे यहां जो अनइलैक्ट्रीफाई एरिया है, वहां के बिजली की समस्याओं को लेकर बार–बार सदन में सवाल उठाता रहा हूँ, हालांकि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मंत्री जी का कि उन्होंने अनइलैक्ट्रीफाइड को लेकर एक पालिसी बनाई और जिसके तहत ये कहा गया कि अब जो एरिया अनइलैक्ट्रीफाइड है, उसमे बिजली दिया जाएगा। पालिसी बने हुए कमोबेश आठ से दस महीने हो चुके हैं। अभी भी अनइलैक्ट्रीफाइड एरिया में बिजली कैसे पहुंचेगा, उसके लिए एनडीपीएल के पास कोई ठोस योजना नहीं है। चूंकि हमारे यहां एनडीटीडीपीएल है, उसका कोई ठोस योजना नहीं

है। पहले ये कहा गया कि जो भी अनइलैक्ट्रीफाइड एरिया में कंज्यूमर रहता है, उसको 7000 या 8000 के हिसाब से पर यूनिट के हिसाब से उसको एडवांस करना पड़ेगा, उसको चार्जिज देना पड़ेगा। हालांकि बहुत ज्यादा था फिर भी कंज्यूमर तैयार हो गया चूंकि पिछले कई वर्शों से वो लोग बिना बिजली के रह रहे थे। अब वो चार्जेज भी जमा कर दिया गया, चार्जेज जमा किए हुए भी लगभग छः महीने हो चुके हैं। जब हम एनडीटीडीपीएल को बुलाकर बोलते हैं कि भई कब तक बिजली लगेगा, तो कहता है कि डीईआरसी से पालिसी अप्रूव नहीं हुई है अभी। तो ये कमोबेश फिर वही बातें है जो पिछले दो साल से चलती आ रही हैं। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से ये निवेदन है कि एक बार डीईआरसी और जो एनडीटीडीपीएल के लोग हैं, उनको बुलाकर के बात करें ताकि इस पर कोई ठोस समाधान निकले। फरवरी का महीने है, अप्रैल से फिर गर्मी आ जाती है। हमने लोगों को आश्वासन दिया था चूंकि पालिसी छः महीने पहले बन चुकी थी, दिसंबर तक बिजली लग जाएगा। अगर इस गर्मी में बिजली नहीं दिया तो अराजकता की स्थिति आ जाएगी। इसके अलावा पाँच हजार कनेक्शन हमारे पूरे कांस्टिट्युएंसी में पेंडिंग हैं। तो इसीलिए इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें ताकि गर्मी आते–आते, चूंकि पहले ये था कि लोगों ने पैसे जमा नहीं किए थे, अब तो लोगों ने पैसे भी जमा कर दिए हैं। अब पैसा जमा करने का चूंकि बड़ा अमाउंट जमा किया, दो यूनिट से कम का किसी का कंजम्पशन नहीं है 17–17 हजार, 18–18 हजार जमा कर दिया गया है। हमने तो ये भी निवेदन किया था कि ये चार्जेज बहुत ज्यादा है, कम कर दिया जाए। लेकिन चलो इसी भी चार्जेज पर अगर कंज्यूमर ने पे कर दिया है, उसके बावजूद उसको प्रतीक्षा करना पड़ता है तो ये बात ठीक नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से उर्जा मंत्री से निवेदन करता हूं कि इस पर जल्द से जल्द से कार्रवाई करें ताकि गर्मी आते–आते उन कंज्यूमर को

जिनको आज तक बिजली नहीं मिली थी, बिजली मिल जाए। बहुत–बहुत धन्यवाद। इस पर कोई स्टेटमेंट आ जाए तो बड़ा अच्छा होगा।

अध्यक्ष महोदयः श्री राजेश ऋषि जी।

श्री राजेश ऋषिः अध्यक्ष जी, आज आपने मुझे 280 के अन्तर्गत बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

मेरा भी आज मुद्दा है पर्यावरण के विषय में ही क्योंकि वायु पॉल्यूशन बहुत जगह फैल चुका है और बहुत तेजी से दिल्ली के अन्दर फैलता है। जैसे–जैसे सर्दी नजदीक आती है, वैसे–वैसे पराली जलती है हरियाणा, पंजाब और तो और पाकिस्तान से भी इस तरफ इतनी हवाएं आ जाती है कि सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तक के सर्वे से ये पता चला है कि लगभग दस हजार के आसपास हर साल हमारे यहां मृत्यु होती है जो वायु पॉल्यूशन के द्वारा होने वाली बीमारियों से। अभी राजेश गुप्ता जी बता रहे थे जिस तरीके से पानी के अन्दर अमोनिया की मात्रा बढ़ रही है और स्थिति ऐसी हो गई है कि जगह जगह पानी नहीं मिल पा रहा कालोनियों में, बिल्कुल सही बात है। हमारे यहां भी ये ही स्थिति पैदा हो चुकी है।

अध्यक्ष जी, सबसे बड़ा कारण जो दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का है; गाड़ियों से और दूसरा जो ये कंस्ट्रक्शन अनॉथराइज कालोनियों के अन्दर हो रहा है। अन–प्लान्ड कालोनियां हैं जिसके अन्दर न तो कोई हरियाली है, न पेड़ लगते हैं, न पौधे लगते हैं और हमारी जो एमसीडी की सरकार है, एमसीडी में जो बैठे हुए लोग हैं वो केवल भ्रष्टाचार के कारण जगह जगह कंस्ट्रक्शन कराते जा रहे हैं, जगह जगह बेसमेंट खुद रहे हैं। स्थिति तो ऐसी हो गई है कि अगर छोटा सा भी भूकम्प आया तो दिल्ली के

अन्दर पता नहीं कितनी मौतें होंगी, उसको गिनने वाला कोई नहीं होगा, इतनी बुरी हालत होगी।

अध्यक्ष जी, खेती की जमीनों के ऊपर इस समय बहुत तेजी से काम चल रहा है। ये दैनिक जागरण ने छापा है 'खेती की जमीन पर अवैध निर्माण की फसल।' ये बिल्कुल फसल पैदा हो रही है और इस फसल की कमाई कर रही है एमसीडी के सारे अधिकारी और उनके पार्शद। उन्होंने साथ में बहुत अच्छा एक तरीका भी दिया है कि क्यों ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है। 'मिलता है निर्माण करने वाले को बल।' ये बहुत बड़ी चीज लिखी है उन्होंने। देखिए हैरानी तो इस बात की है कि 2011 में लक्ष्मी नगर... लक्ष्मी नगर के अन्दर एक इमारत गिरी जिसमें 70 लोगों की मौत हुई। लेकिन किसी भी इंसान के ऊपर कोई केस नहीं हुआ, न ही कोई गिरफ्तार हुआ इसके कारण एमसीडी वाले खुल्लम–खुल्ला इस समय हर जगह कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं और डट के लूट मची हुई है।

दूसरा कारण हमारे यहां पर है वायु पॉल्यूशन, वायु पॉल्यूशन जो है मैक्सिमम हमारे दिल्ली के अन्दर ऑटोमोबाइल से होता है जिसके बारे में अभी चर्चा चल रही थी। ये वायु पॉल्यूशन जो है, ओवर लोडिंग डीजल की जो ओवर लोडिंग गाड़ियां जो हमारे दिल्ली के अन्दर आती है, उसके कारण होता है। जो ओवर लोडिंग गाड़ियों में क्या होता है कि जब कोई भी चीज ओवर लोड होगी तो उसको जोर लगाना पड़ेगा। जब गाड़ी में ओवर लोड होता है तो उसके कारण वहां धुंआ भर जाता है। वायु से प्रदूषण बढ़ता है। इन वाहनों की ओवर लोडिंग से राष्ट्र की बहुमूल्य सम्पत्ति को नुकसान हो रहा है जैसे कि सड़के जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, एक्सिडेंट होते हैं और ओवर लोडिंग के कारण भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। भ्रष्टाचार बढ़ने का कारण ये है कि जो ओवर लोडिंग गाड़ियां आती हैं, उनको वहां पर

बैठे अधिकारी 2500 से लेकर 4000 रूपये अपने अकाउंटों में ट्रांसफर कराते हैं पूरे दूसरे शहरों में। ये वहाँ की एक संस्था ने मुझे बताया कि हमारे यहां पर जो ट्रक मालिक हैं, वो गाड़ियां बुक करके जैसे हमारे यहां रोड़ी आती हैं, गिट्टी आती है, ईंट आती है, तो वो लोग ट्रक मंगाते हैं। उसमें लोड करके भेजते हैं। चालान होता है ट्रक मालिक का और माल वाले का नहीं होता। उनका ये कहना है कि अगर माल क्या, अभी आप चालान करना शुरू कर दें, माल मालिक का भी तो ये ओवर लोडिंग की समस्या का समाधान हो जाएगा क्योंकि वो ओवर लोड करके गाड़ियों को भेजते हैं और वो रिश्वत जो देनी पड़ती है, वो ट्रक मालिकों को देनी पड़ती है, अपने ट्रक को छुड़ाने के लिए। मेरी आपसे ये ही विनती है कि ओवर लोडिंग जो हमारे दिल्ली के अन्दर आ रही है, इसको रोका जाए क्योंकि और स्टेट्स के अन्दर ओवर लोडिंग को रोक दिया गया है जिसके कारण उनके यहां पॉल्यूशन नहीं है। जब ओवर लोडिड गाड़ी आएंगी तो निश्चित ही धुंआ ज्यादा होगा। गाड़ियों के ऊपर लोड ज्यादा पड़ेगा। मेरी आपसे ये ही विनती है कि इसको रोकने के लिए मंत्री जी को बोलें कि ओवर लोडिंग गाड़ियां दिल्ली के अन्दर प्रवेश न करें। बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद धन्यवाद। शरद कुमार जी, नहीं हैं। सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद की आपने मुझे 280 के अन्तर्गत मेरी बात रखने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, एसडीएमसी के अन्दर और बाकी जो दोनों एमसीडी हैं उनके अन्दर भी ये ही हालत है। क्षेत्र के अन्दर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम पे रैम्पैण्ट करप्शन चल रहा है। जब माननीय मोदी जी ने नई ऊर्जा,

नई उड़ान, नई ऊर्जा, नई उड़ान, काउंसलर्स को ले के आए थे, तो लगा था कि क्षेत्र के अन्दर जो ये कंस्टिट्यूएंसी के अन्दर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के नाम पे जो करप्शन चल रहा है, वो रूक जाएगा। लेकिन आज हालत ये है कि कई गुना ये काम बढ़ गया है। बिल्डिंगों के अन्दर इल्लीगली तरीके से मैट्स अपॉइंटेड हैं। जब मैंने ये पता करने का प्रयास किया कि कमिश्नर से तो कमिश्नर ने मुझे कहा कि अथॉराइज्ड मैट्स ही नहीं हैं। जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जईज ने मेट्स रखे हुए हैं, वो अथॉराइज्ड नहीं हैं, वो किसी और डिपार्टमेंट के अन्तर्गत काम करता है और यहां पे इल्लीगली उनको रखा गया है। डेकोरेटिव तरीके से वहां पे कम्पलेंट होता है और कम्पलेंट के नाम पे थोड़ा सा वहाँ पे डेमोलिशन करते हैं और उसके बाद पैसे का व्यापार चलता है और फिर वो बिल्डिंग बन जाती है। मेरे साथी जरनैल सिंह ने इस बात पे रिट भी फाइल किया हुआ है हाई कोर्ट के अन्दर और रिट के बाद जनरैल सिंह जी का एमसीडी के अधिकारी खूब पीछा कर रहे हैं कि भई माफ कर दो, जो जो कर सकते हो, वो कर दो।

अध्यक्ष महोदय, दुःख की बात ये है कि एसडीएमसी का करप्शन जो हमारे पीडब्ल्युडी रोड्स हैं, उसके ऊपर भी एंक्रोचमैंट करा रहा है और गालियाँ हमें पड़ रही हैं क्योंकि पीडब्ल्युडी रोड्स हमारे अन्दर पड़ती हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि पीडब्ल्युडी रोड जो हमारे अन्दर पड़ती हैं, वो उसके ऊपर जो एंक्रोचमैंट है; हॉकर्स के द्वारा, तहबाजारी के द्वारा जो इल्लीगल हॉकर्स वहां बैठे हुए हैं, तो क्या उसपे पीडब्ल्युडी का कोई अधिकार है हटाने का, कि नहीं है? क्योंकि पीडब्ल्युडी दिल्ली सरकार के अन्दर होने के नाते क्षेत्र की जनता कहती है कि भई ये तो कम से कम आपके पास है, इसको तो हटा दो।

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से की पीडब्ल्युडी हमारे पास है, उसके बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। कितनी बिल्डिंग्स पिछले तीन साल में बुक हुईं, मैंने पूछने का प्रयास किया, मुझे नहीं बताया गया। बुक होने के बाद क्या कार्रवाई हुई, ये भी नहीं बताया गया। अब जब वो बिल्डिंग्स बुक हुई थी, वो सारी की सारी बिल्डिंग्स आज बनकर तैयार हैं। तो ऐसी क्या प्रक्रिया हो गई? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब तक बिल्डिंग बाय लॉज के अन्दर, जब तक डीएमसी एक्ट के अन्दर उन रूल्स का मोडिफिकेशन नहीं होगा, अमेंडमैंट नहीं होगा जिसके तहत ये करप्शन चलता है, तब तक ये चलता रहेगा अध्यक्ष महोदय। आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये पीडब्ल्युडी के रोड्स हैं, उसके ऊपर आप एक बार अगर स्टेटमेंट दें तो बड़ा अच्छा रहेगा और दूसरा अगर कमिश्नर से अगर आप एश्योरेंस लें कि भई जो मेरा कम्पलेंट्स हैं, जो मेरे क्षेत्र के अन्दर है, उसपे वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः माननीय मंत्री जी शायद उत्तर देना चाहते हैं कुछ।

लोक निर्माण मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सोमनाथ भारती जी ने जो विषय उठाया है, पहले तो मैं क्लीयर कर दूं पीडब्ल्युडी रोड्स के ऊपर भी अगर कोई बिल्डिंग बनती है वो सारी बिल्डिंग एक्टिविटीज एमसीडीज के हाथ में है। दिल्ली सरकार के पास या पीडब्ल्युडी के पास भी कोई भी बिल्डिंग एक्टिविटी नहीं है। ये बिल्कुल बात सही उठाई है इन्होंने कि बदनामी तो होती है कि भई पीडब्ल्युडी की रोड है और यहां पर भी पैसे लेने आ गये हैं। तो पैसे लेने तो वही आते है जिनके पास बिल्डिंग एक्टिविटी है और बहुत ही ये दुःखद है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना दिया गया है और इंडस्ट्री बनाने के साथ साथ पिछले 20–30 सालों

से इन सब लोगों ने जो भी कॉरपोरेशंस में रहे हैं, इन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि जिसके बारे में बात करते हुए चिल्लाना चालू कर देते हैं। सबसे पहले तो ये चिल्लाते हैं रिश्वत नहीं है जी, करप्शन तो है ही नहीं जी, ये तो सेवा है, थोड़ी सी सेवा करते हैं और जैसे अभी इस साल तो ज्यादातर साइकिल वाले ही बने हैं सारे। पाँच साल बाद देखना, वो भी मर्सिडिज में ही होंगे सारे के सारे। तो अच्छा, अच्छा, वो मर्सिडिज वाले चिल्ला रहे हैं। अब ये कमेन्ट मार रहे हैं। मुझे पता नहीं था सर, आप भी थे पहले इसमें। चिंता मत करो। इनको पता है कि वहां पे बैठ के क्या किया इन्होंने... क्या खेल खेले हैं। अब मैं, ये छेड़ रहे हैं फिर सुनने की भी हिम्मत नहीं होती है। ये बोलना पड़ेगा। एमसीडी के अन्दर।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अब ये मंत्री जी सीधा जवाब दे रहे हैं।

लोक निर्माण मंत्रीः हां, बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ जी ने जो...

लोक निर्माण मंत्रीः सोमनाथ जी की बात का जवाब दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ भारती जी।

लोक निर्माण मंत्रीः उन्होंने मुद्दा उठाया, सोमनाथ भारती जी ने।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः उस पर भी जवाब दिलवा देते।

अध्यक्ष महोदयः ये उनकी इच्छा है, वो दें या न दें। मैं उनको कह नहीं सकता देने के लिए।

लोक निर्माण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, बिल्डिंग इण्डस्ट्रीज को, बिल्डिंग के अन्दर जो नक्शे पास होते हैं, बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, इस सदन के

अन्दर 70 सदस्य हैं सभी सदस्यों को पता है उसके इलाके में क्या रेट चल रहा है। मुझे पता है मेरे इलाके में 200 गज का मकान बनाने के दो लाख रुपये पर लैण्टर लिए जाते हैं। 100 परसेंट लेते हैं, हर एक आदमी से लेते हैं, एक को भी नहीं छोड़ते।

... (व्यवधान)

लोक निर्माण मंत्रीः सर जी, एमसीडी वाले लेते हैं कॉरपोरेट लेते हैं आपके एमसीडी के और

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं।

लोक निर्माण मंत्रीः लेने वाले हैं विजेन्द्र गुप्ता जी के साथी।

... (व्यवधान)

लोक निर्माण मंत्रीः जितने भी लोग हैं जो भी लोग हैं, रिश्वत खाने को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं और जब रिश्वत के बारे में बात की जाती है, वो चिल्लाना चालू कर देते हैं। अभी भी चिल्लाएंगे खुद चिल्लाएंगे, बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदयः चलिए।

लोक निर्माण मंत्रीः अब वो दो तो बोलना चालू हो गए, तीसरे भी बोल लेंगे। एक चीज बस और बताना चाहता हूं जो इन्होंने मुद्दा उठाया था मेट। एमसीडी के अन्दर मेट वाला सिस्टम हुआ करता था लगभग 15 साल पहले, 10 साल पहले होता था। उसको ऑफिशियली खत्म कर दिया गया है। मैं कमिश्नर से बुलाकर उनसे इंक्वायरी करूंगा कि आज भी ये

इल्लीगल मेट कैसे हैं और अगर उनको रखा गया है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है और इसके अन्दर क्या मिलीभगत है? धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः अभी मेरे पास समय है। दो और है श्री नरेश बाल्यान जी। नहीं हैं। मेरे पास। नहीं, कल वाला नहीं है। श्री सुखबीर सिंह दलाल जी। अनुपस्थित। श्री नरेश यादव जी। बस अब ये अन्तिम है, तीन बजे।

श्री नरेश यादवः धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे 280 के तहत बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी मेरे विधान सभा में रजोकरी गांव आता है जो एक पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर अध्यक्ष जी, पानी की जो व्यवस्था है वहां पर ट्यूबवेल और टैंकर से पानी की सप्लाई हो रही है। वहां पर एक यूजीआर और फिल्टर वाटर सप्लाई के लिए लाईन डलनी है जिसका काम आज तक, अभी तक कहीं भी ग्राउन्ड लेबल पर स्टार्ट नहीं हुआ है।

तो मैं आपके माध्यम से यहीं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यूजीआर का काम और जहां से भी ये पानी की लाईन आनी है, उस पानी की लाईन बिछाने का कार्य जल्द से जल्द किया जाए जिससे कि रजोकरी गांव को पानी की जो किल्लत हो रही है, वो दूर हो सके। क्योंकि रजोकरी गांव अध्यक्ष जी, जहां हम ट्यूबवेल भी करवाते हैं तो अगर हम पांच ट्यूबवेल करवाते हैं तो उसमें से दो ट्यूबवेल में जाके पानी निकलता है तो वहां पर पानी की बहुत किल्लत है और उनका भी अधिकार है कि वो भी फिल्टर पानी लें क्योंकि ट्यूबवेल का पानी जो है, वो पीने के लिए भी ठीक नहीं है और टैंकर से भी पूरा पानी नहीं मिल पाता। बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदयः श्री गुलाब सिंह जी। भाई ये अन्तिम है। अब हो गया प्लीज।

श्री गुलाब सिंहः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे 280 में बोलने का मौका दिया।

मैं माननीय उर्जा मंत्री का ध्यान चाहूंगा कि एक बार जरूर एक बहुत महत्वपूर्ण मैं आपके सामने बात रख रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर जितने भी गांव है सभी गांव में सात से आठ घंटे का लाईट कट चल रहा है जबकि सरकार का फरमान भी ये पीछे आया था, आदेश हुआ था कि पचास रूपये के हिसाब से पर घंटा कंज्यूमर को वापस लौटाएंगे। मुझे नहीं पता कि वो अप्रूवल हुआ है या नहीं हुआ है कैबिनेट से। उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है लेकिन अभी फसलों का समय है; गेहूं की फसल, सरसों की फसल खेतों में खड़ी है। गांव के अन्दर लाईट कट हो रहा है। वो अलग बात है लेकिन उसकी वजह से जो एग्रीकल्चर है सारा उसके उपर बहुत बड़ा इफेक्ट है। आठ–आठ घंटा का लाईट कट है। मैं पंचायतों में जा रहा हूँ। लोग बहुत ज्यादा इस बात को लेकर गुस्से में हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इसमें सीईओ साहब को बुलाया जाए। हमारी एक इन्डीविजुअल मीटिंग कराई जाए। माननीय मंत्री कैलाश गहलौत जी का क्षेत्र भी है। हम जाते हैं गांव के अन्दर और बहुत ज्यादा और इसके अन्दर एक लॉजिक दिया जाता है जी कि गांव के अन्दर चोरी बहुत ज्यादा है बिजली की। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर कनेक्शन पर मैंने बड़ा डीपली इसके ऊपर अध्ययन किया है। पूरी दिल्ली के अन्दर करीबन–करीबन दस करोड़ रूपये की बिजली की खपत होती है कृषि के लिए। जिसके अन्दर करीबन छः करोड़ रूपये के आसपास फार्मर जो है, वो बिल देते भी है। चार–पांच करोड़ रूपये की इसमें कोई दो राय

नहीं है जब वो पूरा का पूरा फार्मर जो है, अगर बिजली का बिल भरके अगर वो एक एकड़ गेहूँ उगायेगा तो उसके घर में एक कौड़ी पैसा नहीं जाएगा। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री साहब से भी और माननीय उर्जा मंत्री से भी कहा था कि अगर हम करीबन 1600 करोड़ रूपये की सब्सिडी डोमेस्टिक कनेक्शन में दे रहे हैं तो एग्रीकल्चर कनेक्शन में अगर हम कुछ या तो रेट फिक्स कर दें। जैसे हरियाणा गवर्नमैण्ट में पिछली सरकार ने किया था। इसी तरह से जो एग्रीकल्चर कनेक्शन है। उसके ऊपर चार सौ, पांच सौ रूपये प्रतिमाह अगर एक कनेक्शन के ऊपर फिक्स कर दें तो ये जो फार्मर हैं। जो मजबूरन कुछ थोड़ी बहुत चोरी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि हम करें। वो फिक्स कनेक्शन अगर उनका दे दिया जाये, फिक्स रेट कर दिया जाए, उसको देने में तैयार हैं।

दूसरा, ये है कि अगर ये पीनट्स हैं। थोड़ी सी सब्सिडी उनको दे दी जाये तो दिल्ली के किसानों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी वरना ये हालत है कि दो–दो एकड़ के किसान के ऊपर पाँच–पाँच, चार–चार लाख रूपये के केस बनाये गये हैं चोरी के। आप सोचिए वो आत्महत्या न करे या फिर वो और किसी गलत तरह के स्टेप न उठाये, उसके सामने कोई रास्ता नहीं बचता। ये हालत मैं दिल्ली के किसानों को रख रहा हूं आपके सामने। और कोई एक नहीं, मैं ऐसे पचासों बिल लाके रख सकता हूं। चार–चार, पांच–पांच लाख रूपये के एक एकड़ के किसान के ऊपर चोरी के, छापे के रख दिए उसके घर पर और उसको नींद नहीं आ रही है वो करे क्या! तो मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जो बिजली का कट हो रहा है, इसको थोड़ा सा गम्भीरता से लीजिए। बहुत–बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं अब सरिता जी। अब नहीं प्लीज। समय हो गया है। ऋतुराज जी प्लीज।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः हैं, बहुत जरूरी सब चीजें। आप 280 में लगाइए ना। कल आ जाएगा।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप 280 में आज लगाईए, कल आ जाएगा।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं केवल महिला होने के नाते सरिता सिंह का ले रहा हू। बस प्लीज बैठिए। सरिता जी बहुत दिनों में बोल रही है, सरिता जी का एक लेना है। पर ये सरिता जी, लिखित में नहीं आया मेरे पास आपका।

श्रीमती सरिता सिंहः मैंने दिया हुआ है 280 लेकिन वो लगा नहीं।

अध्यक्ष महोदयः चलिए, बोलिए। जल्दी बोलिए। पांच मिनट का समय है बस।

श्रीमती सरिता सिंहः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी क्षेत्र की एक बहुत ही इम्पाटैंण्ट समस्या यहां पर रखना चाहती हूं। मेरे यहां पर जितनी भी पीडब्ल्युडी की सड़कें हैं, वो आपके यहां की भी समस्या है और शायद बाकी विधान सभाओं में भी समस्या होगी कि वो लबालब भरी हुई हैं। उनकी सफाई व्यवस्था पिछली बार कमेटी ने यहां पर प्रस्तुत भी की थी, उनकी सफाई व्यवस्था के लिए जो प्राब्लम आ रही थी, पर उसमें कोई सुधार नहीं

हुआ है और इसमें दो–तीन कारण है। एक तो कहीं न कहीं पीडब्ल्युडी खुद नेगलिजैंण्ट है सफाई करने के लिए और दूसरा, जो पीछे की नालियां है जो पीडब्ल्युडी नालों में कनैक्ट हो रही हैं, मेरी उस दिन मंत्री जी से मीटिंग हुई थी कि ये तो रेन वाटर ड्रेन है, इसमें पानी आता कहां से हैं। यमुनापार की ये स्थिति है कि जितनी भी नालियां हैं, वो सब नालों में कनेक्टेड हैं और पीछे का जो गाद है, जो एमसीडी द्वारा साफ की जानी है, एमसीडी द्वारा चालान काटा जाना है, उनकी सफाई नहीं होती है। वहां पर घरों में भैस पाले जा रहे हैं और जब उनसे बात की जाए तो लिटरली वो कहते हैं कि हमने एक भैंस तो बस चालान काटने के लिए दिया हुआ है और पूरी एमसीडी की सेटिंग है। उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है जिस वजह से पीडब्लुडी के सारे नाले चॉक्ड हैं, बुरी तरह से और, हाँ, मैं ये आ रही हूं। और जब बात की गयी पीडब्ल्युडी के अधिकारियों से कि आप क्यों सफाई नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने ये बोला कि एमसीडी के जो अधिकारी हैं, वो हमें मना करते है कि हम एमसीडी के डम्प में आपका मलबा नहीं डालने देंगे, तो ये कोई सुझाव नहीं है। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इस पर कोई एक्शन तुरन्त लिया जाए। नहीं तो यमुनापार तो पूरी तरह से नालों से ओवर फ्लडेड होने वाला है। ये आपके यहां की भी समस्या है, मेरे यहां की भी समस्या है। मंत्री जी से मीटिंग हुई थी तो आप इस पर थोड़ा सा संज्ञान लेके करवाइए। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। कल शार्ट ड्यूरेशन का जो बीच में रूका था उसको कन्टीन्यू कर रहे हैं। श्री शिवचरण गोयल जी।

अल्पकालिक चर्चा (नियम – 55) चर्चा जारी...

श्री शिवचरण गोयलः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे इतने ज्वलंत मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। जैसे हमारे विपक्ष के नेता कल उठकर सदन से बाहर चलें गये। ये दिखाते हैं कि ये दिल्ली के प्रति कितने संवेदनशील है। आज पूरी दिल्ली सीलिंग के मुद्दे से बहुत परेशान है और काफी चर्चा सदन में हो भी चुकी है। मैं अपने क्षेत्र के बारे में आपको बताउगा। जो अभी लेटेस्ट चल रहा है। अभी वहां पर एक ट्रेड लाईसेन्स के नाम पर लूट हो रही है। वहां पर कैम्प खोले जा रहे हैं। 914 रूपये का एक डी0डी0 बन रहा है नार्थ एम0सी0डी0 के नाम पर और साथ में तीन हजार रूपये उपर से लिये जा रहे हैं। अब डी0डी0 तो 914 रूपये का और तीन हजार रूपये उपर से। उसमें भी एक रियायत है। यदि आप वहां के प्रतिनिधि से मिलेंगे तो उसमें तीन सौ रूपये की रियायत है। फिर 2700 लगेंगे आपके। और मेरे क्षेत्र में कम से कम भी 10000 दुकानें हैं। मोती नगर क्षेत्र अपने आप में एक हब है ट्रेड का। क्योंकि वहां पर मार्बल के व्यापारी, लक्कड़ के व्यापारी, फर्नीचर के व्यापारी। मोती नगर अपने आप में बहुत बड़ी मार्केट है। पूरी दिल्ली के व्यापारी मोती नगर में आते हैं। सारे बैंकर्स हैं वहां पर। कार के शो–रूम्स है वहां पर। सारा प्लास्टिक वहां से बिकता है क्योंकि हजारों व्यापारी को ये लाईसेन्स के नाम पर लूट हो रही है। अभी तीन हजार रूपये किसकी जेंब में जा रहें हैं। ये तो अभी लूट चल रही है सरेआम। वहां पर कैम्प लगे हुए हैं और धड़ल्ले से काम हो रहे हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा लास्ट ईयर 4 मार्च, 2016 को इसी कनवर्जन नाम के उपर हमारे यहां एक बहुत बड़ी मार्केट है फर्नीचर ब्लॉक। पूरा दिल्ली का, पूरे इण्डिया का फर्नीचर वहीं से जाता है। 4 मार्च, 2016 को वहां पर दो और शो–रूम सील कर दिये गये।

कनवर्जन के नाम पर और वो 27 दिन सील रहे। और वहां के व्यापारियों ने मुझे बताया कि हमने यहां पर करीब पचास लाख रूपये इकट्ठे किये और यहां पर आफिसरों को दिये, प्रतिनिधि को दिए, उसके बावजूद भी वो सील 27 दिन तक नहीं खुली। 28वें दिन वो मेरे पास आए, कहते हैं गोयल साहब, मैं हर जगह घूम चुका हूँ, लेकिन हमारी सीलिंग खुल नहीं रही। कृपया करके इसे खुलवाये। मैं उनको लेकर माननीय केजरीवाल जी के पास गया और नेक्स्ट डे वो दुकानें खुल गईं। मुझे पता लगा वहाँ के टेडर्स से कि ये दुकानें पैसे देने के बावजूद भी नहीं खुलीं, इसका कारण क्या है? कहता है अभी तो करोड़ों रुपये की डिमांड थी, अभी इस पैसे में क्या होगा। कहता है यहाँ पर 1100 शोरूम है यदि हम डराएंगे, धमकाएंगे तभी तो वो पैसे देंगे और आपने इसकी फ्री में खुलवा दी और हमारे यूडी डिपार्टमेंट ने उनसे पूरी फाइल मंगवाई कि आपने सील क्यों किया और बड़े मजे की बात है एमसीडी ने वो फाइल डीडीए में भेज दी जो मुझे जानकारी मिली। अभी तक तो यह नहीं पता लगा कि एमसीडी ने वो दुकानें सील क्यों की थीं और वो खुली क्यों? मैं आपसे चाहूँगा कि इसके ऊपर भी इंक्वायरी की जाए कि जो दो शोरूम 4 मार्च, 2016 को सील हुए थे, उसके पीछे मंशा क्या थी। आज पूरी दिल्ली परेशान है। हमारे मार्बल के व्यापारी, कल भी उन्होंने पूरा रोड पर शो किया था, सिविक सेंटर तक गए थे। जिन व्यापारियों के लिए हमने हर जगह रियायत दी, हर जगह इनके टैक्स कम किए, हर कदम पर इनके साथ खड़े थे, आज दिल्ली ठगी हुई है और टैक्स के नाम पर, जीएसटी के नाम पर, नोटबंदी के नाम पर, एफडीआई के नाम पर आज व्यापारी दिल्ली का बिल्कुल खाली हो चुका है। अभी हफ्ते पहले मेरा चांदनी चौक में कोई प्रोग्राम था और मैं वहाँ गया। उसके बाद मैंने कहा कि एक बारी मैं फतेहपुरी चौक पर चलता हूँ। फतेहपुरी चौक पर वहाँ ज्ञानी

जी की हट्टी है, मैं पुराना वहाँ जाता था। पूरा बाजार खाली पड़ा हुआ है जहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ पर खाली क्यों है बाजार? कहते हैं लोगों के पास काम ही नहीं है और इसके ऊपर सीलिंग की तलवार तो मुझे तो लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि लोगों के हाथ में कटोरा आ जाए और वो स्थिति जो अभी उत्तराखंड में हुई, हमारे एक पांडे नाम के भाई ने, व्यापारी ने आत्महत्या की। कहीं वो स्थिति दिल्ली में न आ जाए, इसके ऊपर एक बहुत ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो पूरे सदन से अपील करता हूँ कि हमें सभी को मिलकर गृह मंत्री के पास चलना चाहिए, ज्ञापन देना चाहिए कि यह जो दिल्ली में कार्रवाई चल रही है इसके ऊपर कोई सुनवाई हो। हम दिल्ली के व्यापारियों के लिए कुछ कर सके, क्योंकि हमारे एमपी हैं वो शांत बैठे हैं, हमारे काउंसलर है वो सोए हुए हैं, उनको लूटने से फुर्सत नहीं है। एक आम आदमी पार्टी आवाज उठा रही है, इसको मैं पूरे सदन से आह्वान करूँगा कि इसके ऊपर मिलकर कार्रवाई की जाए। बहुत–बहुत शुक्रिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः रितुराज जी।

श्री ऋतुराज गोविंदः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इतने इम्पोर्टेंट मसले पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। सीलिंग नाम का जो यह कहर है, इससे सारे के सारे छोटे व्यापारी डरे हुए हैं, रात को उनको नींद नहीं आती है। पूरी दिल्ली के अंदर सीलिंग के नाम पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, सीलिंग के नाम पर एक हजार करोड़ से ज्यादा रुपया इकट्ठा किया गया, नगर निगम ने आज तक उसका हिसाब नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, छोटे–छोटे व्यापारियों को डराया जा रहा है, सीलिंग के ऐसे–ऐसे इंस्पेक्टर बाजार में घूम रहे हैं फर्जी इंस्पेक्टर घूम रहे

हैं व्यापारियों को कहते हैं कि इतना पैसा दे दो, नहीं तो तुम्हारी दुकान सील करवा देंगे। ऐसा भय और ऐसा माहौल पूरे क्षेत्र के अंदर बना हुआ है। मैं एक ऐसे क्षेत्र को रिप्रजेंट करता हूँ जहाँ पर छोटे व्यापारी रहते हैं। संयोग से देश के अंदर एक ऐसी सरकार चल रही है, जिसका टारगेट है कि किसी भी तरीके से छोटे व्यापारियों को खत्म करो। दो तरह की बात है अध्यक्ष महोदय, एक सरकार चंद उद्योगपतियों के, चंद कारपोरेट्स के हाथ में खेल रही है। उनका टारगेट है किसी भी तरीके से छोटे व्यापारियों को खत्म किया जाए। पहले इन्होंने नोटबंदी किया, फिर जीएसटी किया, उसके बाद यह सीलिंग हो रही है, अब 100 परसेंट एफडीआई आ रहा है रिटेल में। इनका ओवरऑल एजेंडा यही है कि किसी भी तरीके से छोटे व्यापारियों को खत्म किया जाए ताकि बड़े–बड़े उद्योगपतियों के बड़े–बड़े शॉपिंग मॉल खुलेंगे और वहाँ पर उनको लाखों करोड़ रुपये का फायदा होगा। ये लोग जब सत्ता में आए थे, अध्यक्ष महोदय, तो कहते थे कि दो करोड़ आदमी को रोजगार देंगे। रोजगार तो दिया किसी को नहीं, लेकिन नोटबंदी से लेकर के सीलिंग तक में लाखों नौजवानों का रोजगार चला जरूर गया है और यह सीलिंग का तो ऐसा कहर है कि जिसके नाम पर लाखों रुपये का भ्रष्टाचार हो रहा है और हर व्यापारी आज दिल्ली का डरा हुआ है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ सत्ता में बैठे हुए लोगों से, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, एमसीडी के लोगों से कि किसी भी तरीके से इस सीलिंग को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह सीलिंग रुकना चाहिए और यह छोटे–छोटे व्यापारियों को जो परेशान करने का आपने ठेका उठा रखा है इसको बंद करें। आज तक देश के अंदर में किसानों की समस्या सुनते थे, किसान आमहत्या करते थे लेकिन लाखों रुपये देने के बाद एक छोटा व्यापारी का, फिर भी अगर दुकान सील कर दिया जाए तो एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसान तो आपसे संभल नहीं

रहा है लेकिन अब व्यापारी भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हो, ऐसा माहौल बना रही है सरकार। तो आपके माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ तबियत थोड़ी नासाज है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आपने मुझे मौका दिया इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का, इसके लिए मैं तहेदिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ।

अध्यक्ष महोदयः सरिता सिंह जी।

श्रीमती सरिता सिंहः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक ऐसे विषय पर बोलने का मौका दिया है, जिस विषय से मेरी पूरी विधान सभा के जितने व्यापारी हैं चाहे वो छोटे, चाहे बड़े वो सब त्रस्त हैं, सब दुःखी हैं, सब आहत हैं, सब खौफ में जी रहे हैं। यहाँ पर माननीय मंत्री गोपाल जी बैठे हैं। खुद आप हमारे यहाँ पर कई सारे छोटे–छोटे बाजार हैं जैसे मेरी विधान सभा में बाबरपुर रोड है वहाँ पर पूरा मार्किट लगता है, रिटेल मार्किट है जैसे रितुराज जी ने बोला, रिटेल में अब पूरा 100 परसेंट एफडीआई आने वाला है। यह सेकेंड स्टेप है अभी तो वो पहले सीलिंग से ही डर रहे हैं। पूरा मंडोली रोड है, लोनी रोड है, टिम्बर मार्किट एसोसिएशन है तो पिछले इसी सदन में मैंने तीन बार चाहे 280 के माध्यम से हो या अलग–अलग मोड से मैंने अपनी इस बात को रखा है कि कन्वर्जन और पार्किंग जो बिल्कुल नाजायज तरीके से व्यापारियों से लिया जा रहा है वो एमसीडी का बिल्कुल तुगलकी फरमान है। मैं अभी अपनी बातें रखूँगी, उससे पहले मैं यह मार्किट एसोसिएशन का लैटर है जो आपके बीच में पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि यह उनकी आवाज है जो हम यहाँ पर उठा रहे हैं। यह उनका दर्द है जो हम यहाँ पर उठा रहे हैं और यह चिट्ठी 2015 की है, 2016, 2017, 2018 में भी कई ऐसी चिट्ठियाँ आपके ऑफिस, मेरे दफ्तर, सब के पास पड़ी होंगी जो लगातार व्यापारी हमारे पास आ रहे हैं और

यह कह रहे हैं कि क्या हमारा जुर्म है कि हम व्यापार कर रहे हैं। क्या हमने अपराध कर दिया है कि हम व्यापार कर रहे हैं और हममें से सब लोग सोचें कि अगर ये व्यापारी व्यापार करना बंद कर दें तो शायद छोटी–छोटी चीजें आटा, नमक, चीनी, चावल, कपड़े हम लेने के लिए बिल्कुल परेशान हो जाएँगे। अगर इन व्यापारियों ने अपना धंधा बंद कर दिया तो, तो यह कन्वर्जन, पार्किंग, सीलिंग से केवल व्यापारी ही नहीं, उनके यहाँ काम करने वाले मजदूर ही नहीं, इससे हम भी इफेक्टेड हैं। मैं वो लैटर पढ़ना चाहूँगी अवैध कन्वर्जन, पार्किंग चार्ज की जबरन वसूली और सीलिंग करने हेतु प्रार्थना–पत्र। उनका नंबर 1 प्वाइंट है कि सन् 2006 में एमसीडी के अधिकारियों ने हम सब दुकानदारों से कहा कि हम अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन करवा लें, वरना आपकी दुकानों को सील कर दिया जाएगा। हम सब ने डर के मारे एक–एक हजार रुपये एमसीडी में जमा करवा कर अपनी दुकानों का रजिस्ट्रेशन करवा लिया। फिर हमसे बोलने लगे कन्वर्जन चार्ज भरो नहीं तो तुम्हारी दुकान, पहले तो दुकान का रजिस्ट्रेशन करवाओ, फिर दूसरे पर हमसे बोलने लगे कि दुकान का कन्वर्जन चार्जेज भरो नहीं तो दुकान को सील कर दिया जाएगा। सो हम कन्वर्जन चार्ज भी भरने लगे और अब हम पर पार्किंग चार्ज का दबाव डाल रहे हैं। जब हमने एमसीडी के अधिकारियों से पूछा कि यह कन्वर्जन चार्ज कब तक भरना पड़ेगा तो कहने लगे आठ साल का एकमुश्त भर दो, फिर नहीं भरना पड़ेगा और यदि किस्तों में भरोगे तो दस साल तक ब्याज सहित भरना पड़ेगा। मगर अब बोल रहे हैं कि जीवनभर, जब पहले था कि दस साल तक भरेंगे क्योंकि किश्तों में भरना पड़ेगा, पर अब ये बोल रहे हैं कि जीवनभर भरो। कन्वर्जन चार्ज जो हम सब समझ पा रहे हैं वो यह है कि अगर हम कोई प्रोपर्टी या कोई दुकान, जिसको हम रेजिडेंशियल से कमर्शियल यूज में लाते हैं तो उसका एक पर्टीक्यूलर अमाउंट कन्वर्जन के उसमें दिया जाता है तो क्या

पूरी जिंदगी कोई दुकानदार कन्वर्जन चार्जेज देगा पर अब ये कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी आपको भरना पड़ेगा तो हम सब दुकानदार यह नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कैसा चार्ज है जो जीवनभर देना पड़ेगा तो हम सब इस चार्ज को भरने में असमर्थ हैं। उनका ये कहना है कि हम बिजली के बिल कमर्शियल व पानी के बिल कमर्शियल हाउस टैक्स, सेल्स टैक्स व इनकम टैक्स हम नियम से भरते आ रहे हैं और हमें भरना भी चाहिए वो खुद मानते हैं कि उन्हें भरना चाहिए क्योंकि इससे हमारा देश आगे तरक्की करता है। खुद व्यापारी यह मान रहे हैं कि अगर हम टैक्स नहीं भरेंगे तो सरकार के पास अगर रेवेन्यू नहीं आएगा तो देश के बाकी काम रूक जाएंगे। मगर कन्वर्जन चार्ज कम तुगलकी फरमान ज्यादा नजर आता है इसलिए हम सब बेफिजूल की उगाही को भरने में असमर्थ हैं। 1960 से पहले हमारा रोड मैं ये बात कह रही हूं शिवाजी मार्किट ये शिवाजी पार्क शॉपकीपर एसोसिएशन का लेटर है 1960 से पहले हमारा रोड एमसीडी के दस्तावेजों में कमर्शियल रोड है और रोहताश नगर, शिवाजी पार्क व बाबरपुर रोड के नाम से दर्ज है और हमारे रोड पर बिजली के कमर्शियल मीटर लगे हुए हैं। सन् 1960 में जब कलकत्ता बिजली बोर्ड हुआ करता था और थ्री फेज के कनेक्शन लगे हैं और आटा मिल का लाइसेंस भी 1960 का सरकार ने ही दिया हुआ है। यह सब कमर्शियल रोड पर ही लगते हैं और 1954 के गजट पर रोड कमर्शियल एक्टिविटी होती थी और गजट में इस रोड का नाम कमर्शियल के उसमें एमसीडी के उसमें लिखा हुआ है। यह है कि हमने समय समय पर यह सभी दस्तावेज एमसीडी व ईडीएमसी को दिये हैं मगर वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। हम सब दुकानदार बड़े ही, यह लाइन नोट करने वाली है कि हमारे देश के व्यापारी, दिल्ली के व्यापारी, यमुनापार के व्यापारी कितने डर से जी रहे हैं। हम सब दुकानदार डर और भय के साथ में अपना जीवन जी रहे हैं पता नहीं कब एमसीडी हमारी

दुकान सील कर दे और हमें बेरोजगार कर दे ये अभी 2017 का लेटर है मैं इसका लास्ट पाइंट पढ़ूंगी कन्वर्जन चार्जेज होते हैं और पार्किंग होते हैं हम सब ये जानते हैं कि यमुनापार में स्पेशली आपकी विधानसभा, मेरी विधानसभा, बाबरपुर विधानसभा हमारे पास पार्किंग की कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर हम व्यापारियों को पार्किंग दें जहां पर एमसीडी व्यापारियों को पार्किंग दे सके। व्यापारियों का बिल्कुल जायज सवाल है कि जब आप हमें पार्किंग दे ही नहीं सकते तो आप हमसे पार्किंग शुल्क ले क्यों रहे हैं। जो फेसिलिटी हम जनता को नहीं दे सकते उस फेसिलिटी का टैक्स हम जनता से कैसे ले सकते हैं। अब एमसीडी पार्किंग चार्ज भी जबरन वसूल रही है। वो भी 80 परसेंट ब्याज लगाकर। न देने पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग करके, लाठी चार्ज करवाकर व्यापारियों को घसीटकर गाड़ी में डाला जाता है उनकी दुकानों को सील किया जाता है ये हो रहा है दिल्ली के व्यापारियों के साथ में ये खुद दिल्ली का व्यापारी बोल रहा है। ऐसा क्या अपराध कर दिया दिल्ली के व्यापारी ने।

अध्यक्ष महोदयः कन्क्ल्यूड करिये अब कन्क्ल्यूड करिये सरिता जी प्लीज कन्क्ल्यूड करिये।

श्रीमती सरिता सिंहः आज अगर आप ये हम सबके साथ ये है। हम अगर आफिस में जाते हैं तो सबसे ज्यादा अगर आज हमारी दुकानों में कोई आ रहा है तो वो दिल्ली के व्यापारी स्पेशली मेरे यहां पर हर रोज व्यापारी आते हैं कि मैडम हमनें क्या गुनाह कर दिया क्या हम दुकान बंद कर दें अपनी। क्या हम रोजगार बंद कर दें। कई बार ईडीएमसी के मेयर से मीटिंग हुई, कमिश्नर से मीटिंग हुई और बिल्कुल सौरभ भाई ने कल कहा कि हम ये मुद्दा विधानसभा में उठाते ही रह जाएंगे इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है मैं ये रिक्वेस्ट करती हूं कि एमसीडी के

कमिश्नर को यहां तलब करना चाहिए। उनसे जवाब मांगना चाहिए कि इस पर क्या कन्क्ल्यूजन निकलेगा और हम सबको गोयल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हम सबको मिलकर केन्द्रीय मंत्री के पास जाना चाहिए व्यापारियों की आवाज बनकर क्योंकि आज दिल्ली का व्यापारी बहुत आहत है। सीलिंग की तलवार उनके गले में लटक रही है। एक कहावत है कि मरता क्या न करता तो आज ये वही स्थिति उनके साथ आ गई है कि व्यापारी खून के आंसू रो रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स थोपा जा रहा है। कई दुकानदारों की तो बोनी तक नहीं हो पाती पर शाम में जब वो अपनी दुकान बंद करते हैं तो उनके दिमाग में यही चिंता होती है कि ये टैक्स जमा करना है।

अध्यक्ष महोदयः हो गया अब कन्क्ल्यूड करिये सरिता जी प्लीज।

श्रीमती सरिता सिंहः हमारी दिल्ली के व्यापारी बहुत दुखी हैं। मेरी विधानसभा में मंडोली रोड, लोनी रोड, अशोक नगर, बाबरपुर, रोहताश नगर, शिवाजी पार्क सारे मार्किट एसोसिएशन वाले बहुत परेशान है और मैं बस यही कहना चाहती हूं कि अगर इस पर कोई कानून नहीं बना, इस पर कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो फिर अगर जनता व्यापारी अराजक होते हैं तो फिर ये आरोप न लगाया जाए कि इस पर कुछ काम नहीं किया गया था क्योंकि अल्टीमेटली हम जितने भी विधायक यहां बैठे हैं हम सब जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अगर हमारी जनता अगर दुखी होगी, अगर व्यापारी दुखी होंगे तो हम उनके साथ उनके आंदोलन में खड़े होंगे जय हिन्द जय भारत।

अध्यक्ष महोदयः जरनैल जी।

श्री जरनैल सिंहः बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। बहुत ही गंभीर मामले पर आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, सिचुएशन जब ऐसी

बन जाए कि देश की सर्वोच्च अदालत ये खुद कहे, ये आज का अखबार है अध्यक्ष जी टाइम्स आफ इंडिया अखबार का नाम है और इस अखबार में साफ लिखा है ***"corporation failed to do their duties: Supreme Court."*** और लगभग सभी अखबारों में इस तरीके के आज बयान आये हैं। अध्यक्ष जी, दिल्ली सरकार को एमसीडी के सदन में एक प्रतिनिधि के तौर पर मेरे को जाने का मौका मिलता है तो कुछ ऐसे आंकड़े कुछ ऐसी जानकारी इस सदन के सामने रखना चाहूंगा जो लगभग सभी साथियों ने आज पूछी है। अध्यक्ष जी, दो दिल्ली की बड़ी दिक्कतें बन चुकी हैं आज की डेट में एक एमसीडी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार दूसरा सीलिंग से होने वाला कहर। कुछ दिन पहले एमसीडी के कमिश्नर से कुछ सवाल पूछे गये जो कि एमसीडी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट से ही संबंधित थे। उन सवालों में पूछा गया जी पिछले 4 सालों के अंदर दिल्ली में कितनी बिल्डिंगें आपने बुक की हैं। तो ये उसका जवाब आया अध्यक्ष जी आंकड़े भी पढ़ देता हूं। एक साल के आंकड़े थे जी कुल संख्या 4684 ये सिर्फ में एसडीएमसी की बात कर रहा हूं 4684 बिल्डिंगों को बुक किया गया आप ध्यान रखियेगा अध्यक्ष जी हर बिल्डिंग से पैसा जाता है कि भ्रष्टाचार करने वालों के हौंसले कितने बुलंद है उस चीज का ये जीता जागता ये प्रमाण है 4684 बिल्डिंगों को बुक किया जाता है पूछा जी इनके ऊपर क्या कार्यवाही होती है तो उसका जवाब आया जी 2100 को डिमोलिस कर दिया 505 को सील कर दिया जैसे एफआईआर होती है तो आगे एक्शन होता है उसके आगे ये दो एक्शन हुए। बाकी जो बच जाता है 2079 बिल्डिंगें उनको कितने पैसे लेकर छोड़ा क्या सेटिंग करके छोड़ा उसका जिक्र ही नहीं है सबसे बड़ा लैक तो ये आ गया अध्यक्ष जी। हर साल के अंदर हजारों बिल्डिंगें ऐसी दे दी जिनका दोबारा पूछने पर बोला जी जब ये मान लिया कि कार्यवाही हुई नहीं, क्यों कार्यवाही नहीं हुई इसका जवाब अभी तक नहीं दिया। दस

लोगों की बिल्डिंगें बुक करते हो पांच पर कार्यवाही करते हो पांच पर नही करते तो उनकी क्या वजह है पहली कमी है यहां पर है। उसके बाद कोई बिल्डिंग अगर आप डिमोलिश करते हो या सील करते हो वो दोबारा न बने उसकी जिम्मेवारी किसकी होती है तो ये मानते हैं जी उसकी जिम्मेवारी बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जीई और एई की होती है। जब पूछा गया कि इन बिल्डिंगों की आज की डेट में क्या स्थिति है तो बड़ी ही हंसी आ रही है मेरे को पढ़कर कि कमिश्नर साहब कह रहे हैं ये जानकारी विभाग के पास उपलब्ध ही नहीं है। अब पूछा गया कि अगर बिल्डिंग बन जाती है तो जेई पर क्या कार्यवाही होती है तो इसमें अच्छा खासा लिखा है अगर तोड़फोड के बाद पुनः संपत्ति का अवैध निर्माण किया जाता है तो भवन विभाग डीएमसी एक्ट 1957 के तहत बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जेई पर कार्यवाही की जाती है। अब एक्ट में तो प्रावधान है। अगर अनाथराइज बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट का जेई भी सस्पेंड होता है और पिछले कुछ सालों में देखते देखते पूरी दिल्ली बन भी गई पर पूछा जी जब यह पूरी दिल्ली बन भी गई अनाथराइज।

अध्यक्ष महोदयः जरनैल जी, सीलिंग ड्राइव पर जो विषय चल रहा है न।

श्री जरनैल सिंहः मैं उसी पर आ रहा हूं अध्यक्ष जी वो भी बिल्डिंग डिपार्टमेंट है ये भी बिल्डिंग डिपार्टमेंट है। मैं इसके बाद सीलिंग डिपार्टमेंट में उस पर भी 9 सवाल लगाये थे एसडीएमसी कमिश्नर से।

अध्यक्ष महोदयः हां उस पर आ जाइए, प्लीज उस पर आ जाइए।

श्री जरनैल सिंहः मैं उसका जवाब दे रहा हूं उसका भी पूरा आ रहा हूं अध्यक्ष जी। अब ये अध्यक्ष जी मैं इसलिए चाह रहा हूं कि एसडीएमसी

कमिश्नर ने ये लिखकर दे दिया कि सदन के विभाग के संज्ञान में ऐसा कोई मामला आया ही नहीं कि दिल्ली में एक भी अनऑथराइज बिल्डिंग बन गई है। अब पहले तो इन सवालों के जवाब ही नहीं आ रहे थे। मामला फिर एलजी साहब के पास रेफर किया गया एलजी साहब के पास से भी जवाब नहीं भिजवाए गए तो मजबूरन हाईकोर्ट में रिट लगाई है और हाईकोर्ट के जज ने व एमसीडी की तरफ से बहुत सारे वकील आए थे उनको लताड़ा कि तुम तो आज मेरे को बड़े दिनों बाद दर्शन हुए तुम में से तो कोई आता ही नहीं दो सवाल इसमें और एड करके काउंटर एफिडेविट मेरी तरफ से आप एड करो ये हाईकोर्ट में जज साहब ने बोला। उसके बाद अब हम सीलिंग की बात करते हैं तो कल से ये खबर बड़ी चर्चा में है कि 1000 करोड़ आपने सीलिंग ये कन्वर्जन चार्जेज, रजिस्ट्रेशन चार्जेज, पार्किंग चार्जेज के नाम पर इक्ट्ठा किया। 1000 करोड़ जो आपने इक्ट्ठा किया तो मैंने यही पूछा था उसको आपने कहां खर्च किया। 2006–07 के दौरान ये 1000 करोड़ इक्ट्ठा किया गया था और जवाब में ये आया जी सिर्फ 58.32 करोड़ रुपये इसमें से खर्च किया गया है। साढ़े नौ सौ करोड़ का आज भी ये ऑनरिकार्ड एमसीडी कमिश्नर का जवाब है।/320/ साढे नौ सौ करोड का आज भी कोई हिसाब नहीं जी साढे नौ सौ करोड़ कहां गया। इससे सिर्फ चार पार्किंग बनाएंगे ये अध्यक्ष जी पूरी दिल्ली के अदर। कालका जी, राजौरी गार्डन और दो जगह और ये पार्किग बनी है जिसका अभी तक कम्पलीट हुई है। साढ़ नौ सो करोड का एमसीडी के पास अभी तक अध्यक्ष जी कोई हिसाब–किताब नहीं है। उसके बाद अध्यक्ष जी जैसे सरिता बहन बताया मैं भी तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र को रिप्रजेंट करता हूं जहां पर बहुत बडी पश्चिम दिल्ली की मार्किट है। इस मार्किट में बोला गया व्यापारी को बोला गया था कि या तो फोर एग्जाम्पल 100 रूपये आप 10 साल तक दीजिए नही तो 800/–रूपये एक मुस्त दे दीजिए। मतलब

आठ साल का एक मुस्त दे दीजिए। तो जिनको समझ आया उन्होंने आठ सौ रूपये एक साथ दे दिए। जिनको नही समझ आया उन्होंने कहा कि दस साल तक सौ–सौ रूपये दे देगें। अब दस साल पूरे होने के बाद ग्यारहवें साल में एमसीडी ये कह रही है कि हमारा वार्षिक शुल्क की कोई सीमा तय नहीं है। ये आपको सारी जिंदगी देना पड़ेगा। अब इसमें अगर ऐसी ट्रांसपैरेंसी रखी होती कि सारी जिंदगी देना पडेगा। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं हर आदमी आठ सौ रूपये एक बार में देता। कोई सौ रूपये सारी जिंदगी ना देता। ये तो सबको कैल्कूलेशन समझ में आती है। पर कोई रिकार्ड नहीं है सरासर चीटिंग की गई है दिल्ली के व्यपारियों के साथ। पहले आठ सौ रूपये मांगे गए एक मुश्त देने के लिए और बोला गया कि दस साल तक देने हैं। और अब व्यापारियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं ग्यारहवें साल में कि ये फिर से पैसा दो नही ंतो आपकी बिल्डिंग टूट जाएगी। तो ये जबरदस्त वसूली एक शोषण ऊगाही हो रही है सीलिंग के नाम पर। प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि जी मैं गरीबों के साथ हूं। मैने गरीबी को बड़ी नजदीकी से देखा है। मैं गरीब के बारे में पहले सोचता हूं। तो मैं सोच रहा था कि गरीब है कौन। तो वो गरीब मिल गया अध्यक्ष जी ये बड़ी खुशी की बात है। गरीब की स्पैलिंग होती है जीएआईआरबी। यही होती है ना जी। तो ये गरीब है जी। जीऐ से गौतम अडानी, आरआई से रिलांएस इण्डस्ट्रीज और बी से बाबा रामदेव। इनके अलावा और गरीब दिखता जी नहीं। इस गरीब के लिए प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। चाहे एफडीआई आ रही है, चाहे नोट बंदी हो रही है, चाहे जीएसटी आ रही है। इस गरीब के बारे में कोई नहीं सोच रहा जो देश में मर रहा है। इन गरीबों के बारे में सोच रहे हैं गौतम अडानी, रिलाइंस इण्डस्ट्री और बाबा रामदेव। तो अध्यक्ष जी, मैसेज बिल्कुल साफ है। एसडीएमसी कमिश्नर को तलब करके ये पूछा जाए कि क्योंकि चीजें अब काफी हद तक आन रिकार्ड

आ चुकी है और जवाब इनके पास है नहीं। आज भी एमसीडी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी मेरे से कह रहे थे जी मैने मिलना है। मैने कहा जी यहां आ जाओ विधान सभा में बैठा हूं। फिर आके मेरे पूछ रहे हैं जी इसका क्या करना है। मैने कहा कि इसका जवाब देना है और कुछ नहीं करना है। तो सरासर इनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। पूरी दिल्ली पहले तो अनऑथोराईज्ड बनने दी। जैसे कि जेल होगी अध्यक्ष जी। अब कोर्ट में मैटर गया तो अब वो सिकंजा कसना शुरू हुआ है तो अब परेशानी हो रही है कि एक्ट के हिसाब से तो एक भी अनऑथोराइज्ड बिल्डिंग बनेगी तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जेई को उसका जिम्मेवार होना चाहिए। और जब तक देश के अंदर ये कानून नहीं बनता चाहे ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट है चाहे ये कोई भी विभाग है उस विभाग का जो अधिकारी जिम्मेदार है अगर उसके क्षेत्र में कोई लापरवाही होती है तो उसके ऊपर जब तक शिकंजा नहीं कसा जाएगा ये सुधार होने वाला नहीं है। मैं अपने साथियों की इस बात के साथ पूरी तरह सहमत हूं कि यहां पर एसडीएमसी कमिश्नर को बुलाया जाए और इन चीजों के जवाब उससे पूछे जाएं। आपने इतने गम्भीर मामले पर मेरे को बोलना का समय दिया उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद–धन्यवाद श्री ओम प्रकाश जी।

श्री ओम प्रकाशः धन्यवाद अध्यक्ष जी, सीलिंग आज पूरी दिल्ली में जो सीलिंग की तलवार लटकी हुई है। सदन में सभी सदस्य अपने–अपने क्षेत्र में जो इससे पीडित लोग हैं उनके विषय में अपना–अपना दर्द बोल रहे हैं। सारी बात सुनकर मुझे यह अहसास होता है कि सीलिंग के विषय में जो नियम हैं उसकी जानकारी व्यापारी और चुने हुए लोगों को उतनी है जितनी होनी चाहिए। और जानकारी के अभाव में बहुत सी चिंता अभी जरनैल सिंह जी ने व्यक्त की हैं। हम भी उससे सहमत हैं। जो लोग भ्रष्टाचार

और भ्रष्टाचारी हैं यदि उन भ्रष्टाचारियों के सह पर अनऑथोराइज्ड कन्सट्रेक्शन होती है तो निश्चित रूप से उनके ऊपर जो कानून सम्बद्ध है वो कार्यवाही होनी चाहिए। मुझे लगता है नहीं इसमें कोई भी आदमी इससे अपनी सहमति ना जताता हो। लेकिन इसके साथ–साथ कल भाजपा पक्ष की तरफ से 54 में एक नोटिस जो आपके सम्मुख हमने किया था। दिल्ली की जो 351 जो सडकें हैं म्यूनिसिपल कार्पोरेशन की तरफ से दिल्ली सरकार को नोटिफाई करने के लिए जो सडकों का एक ब्यौरा भेजा गया और बार–बार उस विषय में दिल्ली सरकार से जो पत्र व्यवहार हो रहा है। पन्द्रह में, सोलह में, सत्रह में तो लगातार पिछले तीन साल से ये कहा जा रहा है जब से ये सरकार है कि भई उनके ऊपर आप अपना जो भी फैसला लेना है लें। तो कम से कम एक बहुत बडा हिस्सा जो 351 सड़कों पर जो व्यापारी अपना काम काज करते हैं उनको तो कुछ ना कुछ रिलीफ मिले। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसा क्या कारण है कि ये सरकार या आप उस मुद्दे पर कोई स्पष्ट किसी प्रकार का कोई निर्देश या दिल्ली सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह कहना चाहता हूं कि म्यूनिसिपल कार्पोरेशन की तरफ से जो 351 सडकों को नोटिफाई करने का जो बार–बार रिमांडर दिया जा रहा है कश्प्या करके जल्दी से जल्दी उसके ऊपर कार्यवाही करें।

अध्यक्ष महोदयः जगदीप जी प्लीज इसको। मंत्री जी जवाब देगें ना बाद में। आपकी बारी आएगी बोलने की।

श्री ओम प्रकाशः यदि मैं ये समझता हूं कि 351 सड़कें और ये कोई बहुत बडी बात नहीं है कल भी हम कह रहे थे आज भी कह रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों इसके ऊपर इतना वाद विवाद हुआ। सदन का बहुत सा समय भी गडबड हुआ। तो कुछ चीजें ऐसी है जिसमें पक्ष हो या विपक्ष

हो सभी लोग एक मत हैं और दिल्ली में जो सीलिग है । सीलिंग से दिल्ली के लोगों को निजात मिलनी चाहिए । मैं समझता हूं इसमें हर आदमी सहमत है। अब ये बात अलग है कि उसका श्रेय कौन लेना चाहता है। तो श्रेय आप सरकार में तो आप को ही मिलेगा हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हमारा कहना ये है कि एक डैमोक्रेटिक सेटअप में सरकार जो काम करती है उसमें कहीं ना कहीं थोडा बहुत जो पक्ष विपक्ष का भी होता है तो कम से कम उतना स्पेश हमारे लिए रखें और मेरा केवल इस विषय में यही कहना है कि विषय में यदि अध्यक्ष जी ठीक समझे तो तथ्यों की जानकारी और ये सीलिंग का जो मामला है। कौन–कौन लोग इससे इफैक्टिड है क्यों इफेक्टिड हैं, क्यों इनसे बचा जा सकता है। इसके लिए यदि आप ठीक समझते हैं तो दिल्ली के हम जो सभी अपने विधायक है या और जो दूसरी वो है पहले विधायकों का और फिर बाद में औरों को इससे शिक्षित करें जिससे लोगों को समझ में आए कि आज होता क्या है और मुझे भी यह कहने में संकोच नहीं है। किसी भी दुकान पर जाकर कोई आदमी खड़ा हो जाता है इन्सपैक्टर अभी देखा हमारे विश्वास नगर में। महिला इन्सपैक्टर बनकर चली गई। कई जगह से पैसे ले आई। उस आदमी को समझ में ये ही नहीं आता कि...

अध्यक्ष महोदयः अरैस्ट हो गई वो अरेस्ट हो गई। तीन महिलाएं है नकली बनकर के आई। अरैस्ट करवाई गई है।

श्री ओम प्रकाशः मेरे क्षेत्र में जो महिलांए हैं। हालांकि वो अरैस्ट हुई। लेकिन इस तरह का जो मामला जो सबसे बडी दिक्कत जो मैं समझ पा रहा हूं जो व्यापारी वर्ग है या जो लोग हैं उनको पूरा इस सिस्टम का इस चीज का ज्ञान नहीं है। उनको इसलिए कोई भी आदमी वहां पर जाकर जब वहां खड़ा होता है और खड़ा होकर उल्टा सीधा बोलता है तो आदमी

घबरा जाता है और कहता है कि मेरे किसी ना किसी कोई चीज में कमी होगी। तो उसका अधिकार क्या है उसकी डयूटी क्या है। उसके काम में क्या कमी है। यदि उसको समझ में आए इसके लिए हम सदन की और से कम से कम और नहीं तो 70 या 69 हम जो लोग हैं इन सब लोगों को प्रोपर चीज समझ में आए। हम अपने–अपने एरिये में इसके बारे में लोगों को शिक्षित करें। और मैं ये समझा हूं कि हम ये करेंगे एक बहुत बडा काम होगा। और इसके साथ–साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि 351 जो सड़कें हैं जिनका मामला पैन्डिग पडा हुआ है कश्पया करके तुरन्त प्रभाव से उनको नोटिफाई करें जिससे दिल्ली की जनता को इससे निजात मिल सके। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः भावना गौड जी।

सुश्री भावना गौड़: शुक्रिया अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय बड़ा गंभीर विषय इसे मैं विशेष तौर पे एक कवि की दो पंक्तियां सुनाकर के फिर शुरू करूंगी। शहर बसाकर अब सकून के लिए गांव ढूंढ़ते हैं, शहर बसाकर अब सुकून के लिए गांव ढूंढ़ते हैं बड़े अजीब हैं ये लोग हाथ में कुल्हाड़ी लिये छांव ढूंढ़ते हैं। देखिये स्वाभाविक तौर पे इतना गंभीर मुद्दा और कल जिस तरह से विपक्ष ने हाउस को नहीं चलने दिया तो गंभीरता हमारी तरफ से है या इनकी तरफ से, ये दिल्ली का प्रत्येक नागरिक जान रहा है। अध्यक्ष महोदय पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की सभी मार्किटस के अंदर बीजेपी शासित एमसीडी द्वारा जो सीलिंग की जा रही है पूरी दिल्ली के अदंर एक दहशत का माहौल है। सभी व्यापारी भय के वातावरण के अंदर जी रहे हैं। वो छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो उसका व्यापार कब उसके हाथ से निकल जाएगा, छूट जाएगा इसकी लगातार उसको चिंता सता रही है। दिल्ली के छत्तरपुर मार्किट में खान मार्किट में, डिफेंस कालोनी

में, मैहरचंद मार्किट में और दिल्ली की विभिन्न इलाकों की मार्किटस के अंदर लगातार व्यापारी केवल एक ही नारे को लेकर के एक ही नारा एक ही आवाज गूंज रही है, जन–जन की है यही पुकार बंद करो ये अत्याचार। स्वाभाविक तौर पे ये अत्याचार है। किसी की रोज़ीरोटी के उपर लात मारना ये इस तरीके से उसको सील कर देना उसका परिवार कैसे चलेगा किस तरह से कमाई उसके घर के अंदर आएगी इस तरह की एक असमंज का माहौल दिल्ली के व्यापारियों के बीच में विद्यमान है ।

अध्यक्ष महोदय, मैहरचंद मार्किट के अंदर लगभग ड़ेढ़ सौ की संख्या में दुकानें हैं। 135 दुकानें वहां पर सील कर दी गई हैं इसके अंदर दो बैंक भी ऐसे हैं जो सीलिंग की चपेट के अंदर आये हैं। मैहरचंद मार्किट के अध्यक्ष हैं अशोक सलूजा जी उन्होंने बताया कि 2006 के अंदर सीपीडब्लूडी ने रिडवलपमेंट प्लान जो है वो दिल्ली नगर निगम को सौंप दिया था। दस साल बाद के अंदर भी दिल्ली नगर निगम ने आज तक उस नक्शे को पास करके नहीं दिया। 38.69 मीटर की दुकानें उनको प्रोवाईड की गई, सरकार के द्वारा एलाट की गई और उनका प्लाट आज भी उतनी ही जगह पर बनाया गया हुआ है। कोई घेरा–घारी नहीं की गई। अगर उस प्रोपर्टी के साथ अपने उस जमीन के साथ में किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया गया तो उनकी प्रोपर्टी को सील क्यों किया गया ये अपने आप में एक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय, खान मार्किट के अंदर भी लोगों की दुकानों को सील किया गया, उनका एक वीडियो जो वाट्सऐप के उपर वायरल हुआ हमारे एक सिख परिवार के व्यक्ति ने बताया कि एक करोड़ रूपये का कंवर्जन चार्ज आलरेडी उन्होंने एमसीडी को जमा करवाया हुआ है लेकिन एमसीडी के अधिकारी पुलिस दस्ते के साथ में जब उन दुकानों को सील करने के

लिए आये तो केवल वहां के व्यापारी अपना रोना के साथ में रोते रहे लेकिन ना तो निगम के अधिकारियों ने उनकी बात सुनी और ना ही दिल्ली पुलिस के विभाग के लोगों ने। अध्यक्ष महोदय, खान मार्किट के अंदर एक दुकान है नव्या इंपोरियम करके व्यक्तिगत तौर पे मेरे जानकार हैं उनकी दुकान को भी इसी तरह से सील कर दिया गया। व्यक्तिगत तौर पे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि भावना जी इस दुकान को दूसरी जगह ले जाने में, दूसरी जगह बदलनें में लगभग आठ से दस लाख रूपये का मेरा खर्चा होने वाला है और इस तरह का भारी बोझ जो व्यापारियों के उपर पड़ा है क्योंकि व्यापार चलाना ये उनकी मजबूरी है परिवार को पालना उनकी अपनी एक नैतिक जिम्मेवारी है लेकिन व्यापार अगर तबाह हो जाएगा तो स्वाभाविक तौर पे परिवारों को और उनके बालकों को तबाह होते हुए देर नहीं लगेगी। अध्यक्ष महोदय, उनका ये प्रश्न भी स्वाभाविक है कि जब प्रोपर्टी के साथ में छेड़–छाड़ नहीं हुई है, प्रोपर्टी को आगे तक नहीं बढ़ाया गया, अगर उनकी उपर वाली जगह को सील किया गया जहां पर केवल उनका सामान रखा था या एसी रखा था तो उन जगह को सील करने से दिल्ली नगर निगम को क्या मिला ये अपने आप में ही एक सवाल है। अध्यक्ष महोदय 2006 से लेकर के 2018 तक अगर दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को ये लगता है कि इन प्रोपर्टियों को किसी तरह से दुकानदारों ने आगे बढ़ाया है उनके साथ छेड़–छाड़ी की है तो मुझे समझ में नहीं आता अपने आप में सवाल है कि इस दस साल के अंदर निगम के अधिकारी कहां थे? क्या उनकी जिम्मेवारी तय नहीं है और अगर उनकी जिम्मेवारी तय है तो वो आज कहां पर हैं उनसे सवाल क्यों नहीं किया जाता और स्वाभाविक तौर पे ऐसे अधिकारी जो कंवर्जन चार्ज के नाम के उपर कंवर्जन चार्ज नहीं वसूल करते अपने आप में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं ऐसे अधिकारियों के उपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। पिछले दस साल के अंदर

एक हजार करोड़ रूपया दिल्ली नगर निगम ने वसूला है वो पैसा कहां है किसी द्वारा वसूला गया उस पैसे का कोई हिसाब–किताब नगर निगम के पास नहीं है और सूत्रों के अनुसार इस पैसे के लिए आज तक कोई एकांउट नहीं बनाया गया । पैसा कहां जमा है निगम के अधिकारियों से पूछें, निगम के कमीश्नर से पूछें, निगम के मेयर से पूछें तो आपको जवाब मिलेगा कि ये एक हजार करोड़ रूपया एमसीडी ने विकास के कार्यों के उपर खर्च किया।

अध्यक्ष महोदय, पिछले दो हफते के अंदर साउथ एमसीडी ने लगभग 17 करोड़ रूपये की वसूली कंवर्जन चार्ज के नाम से की है। अब सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कंवर्जन चार्ज है क्या ? जब हम किसी भी मार्किट के अंदर कोई भी सरकार निगम में बैठा हुआ कोई भी अधिकारी अपने आप में तब नियम को बना सकता है और लागू कर सकता है जब वो सुविधायें जनता को प्रोवाईड करवा रही हो एजेंसी। कंवर्जन चार्ज के नाम के उपर हमारी मार्किटस के अंदर टॉयलट बने हुए होने चाहिए। पार्किंग बनी हुई होनी चाहिए। निगम की तरफ से वो मूलभूत सुविधायें मार्किटस को मौहया करानी चाहिए तब वो अधिकारी है कंवर्जन चार्ज उन मार्किट में रहने वाले व्यापारियों से किसी भी प्रकार का चार्ज लेने के लिए उसको हम कंवर्जन चार्ज कहते हैं अपनी भाषा में लेकिन जाइए किसी भी मार्किट के अंदर कहीं भी टॉयलेटस नहीं हैं, कहीं भी सड़कें नहीं हैं पार्किंग अपने आप में दिल्ली की एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या बन गयी है जहां देखिये वहां पर जमा लगा है। तो किस बात का कंवर्जन चार्ज ले रहे हैं और कंवर्जन चार्ज खुद एमसीडी तय कर रही है कि तीन महीने तक कोई कंवर्जन चार्ज नहीं लिया जाएगा । अब जब निगम के अधिकारियों ने तय कर दिया तो वो कौन अधिकारी है जो जनता के पास जाकर के इस तरह की बात

करते हैं कि तीन महीने के बाद तो ये और बढ़ा कर के देना पड़ेगा यानि सीधा–सीधा भ्रष्टाचार में नगर निगम किस तरह से लिप्त है ये मामला देखने को मिलता है।

अध्यक्ष महोदय, मैट्रो के किराये बढ़ाये, बीजेपी अपनी जिद्द के उपर अड़ी रही, सदन हुआ सारे विधायकों ने मैट्रो के किराये ना बढ़ाये जायेंइ स पर चर्चा की लेकिन उसके बावजूद भी जिद्द में आकर के बीजेपी के द्वारा मैट्रो के किराये बढ़ाये गये। ठीक उसी प्रकार से आज भी बीजेपी अड़ी है मौहया सहूलतें मार्किटस को दें, व्यापारी को दें या ना दें लेकिन कंवर्जन चार्ज अपनी जिद्द में आकर के उन्हें वसूल करना है ये बीजेपी के द्वारा लगभग तय है। दिल्ली के लोंगों ने अध्यक्ष महोदय नोटबंदी को झेला, जीएसटी को झेला, सीलिंग को झेल रही है मुद्दा गंभीर है सदन भी गंभीर है अध्यक्ष महोदय व्यापारी परेशान है। छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो अभी कल मेरी मार्किट के पांच पटरी वाले छोटे दुकानदार मेरे पास आकर के मिले और उस समय हम उनके सामने बच्चे होते थे वो आज मेरी पिता के उम्र के हैं लेकिन उन्होंने बताया कि 15 साल से वो जिस ठीए के उपर बैठे हैं वहां नगर निगम के अधिकारियों ने आकर के उनका 3200–3200 रूपये का चालान काटा उन्हें कल कोर्ट में वो भुगत कर के आये हैं, तो किस बात की सजा नगर निगम उनको दे रहा है ये अपने आप में प्रश्न है । आज पटरी वाला परेशान है, व्यापारी परेशान है, छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, किस पैसे के रोने को दिल्ली नगर निगम रोता आया है आज तक समझ में नहीं आया। दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को लगभग तीन–तीन महीने से तनख्वाह नहीं मिली। 6, जनवरी को नार्थ एमसीडी की मेयर साहिबा एक आलीशान पांच सितारा होटल के अंदर दावत देने का प्रोग्राम करती हैं कहां से आ रहा है वो पैसा? कौन लोग हैं जो इस तरह

की दावत का अरेंजमेंट कर रहे हैं ? कौन लोग हैं जो इस तरह की दावतों में जा रहे हैं। ये अपने आप में अध्यक्ष महोदय एक प्रश्नचिन्ह है। मैं सीधा–सीधा नाम लूंगी एक केन्द्रीय मंत्री का आदरणीय विजय गोयल जी के उपर हाउस टैक्स का करोड़ो रूपये उनको हाउस टैक्स अदा करना था लेकिन यही दिल्ली नगर निगम के अधिकारी उन्होंने सीधा–सीधा इसे माफ कर दिया। अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्ष महोदयः आप कंक्लूड करिये भावना जी कंक्लूड करिये प्लीज़।

सुश्री भावना गौड़ जीः जी, मैं आदरणीय गोपाल राय जी की अध्यक्षता में 11 संसदीय कमेटी बनी है वो कमेटी दिल्ली के सदन से लेकर के और दिल्ली की सड़कों तक इस सीलिंग के मामले को लेकर के जाएगी । अध्यक्ष महोदय, हमारे भाई सौरभ भारद्वाज जी ने कल इसी सदन में एक प्रस्ताव रखा था स्वाभाविक तौर पे दिल्ली नगर निगम का विषय है और इस विषय की जवाबदेही सीधा–सीधा दिल्ली नगर निगम के उपर तय है। उन्हें यहां आकर के जवाब देना चाहिए और निवेदन है मेरा आपसे कि आप दिल्ली नगर निगम की तीनों कमीश्नर्स को यहां बुलायें और सीधा–सीधा जो सवाल हम विधायकों के दिमाग में है वो सवाल जो दिल्ली की जनता उनसे पूछना चाहती है उसके जवाब इस सदन में आकर के दें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ताः धन्यवाद, अध्यक्ष जी आपने सीलिंग के विषय में बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, पिछले साल एक पिक्चर बड़ी चर्चित हुई थी बाहुबली। उसके अंदर एक युवराज को जब राजा बनाने की बात आती

है तो ये होती है कि उसे बनाया जाएगा जो एक दुश्मन आता है उसको मार के गिरा देगा। वो दोनों युवराज जब उसे मारने के लिए जाते हैं तो एक युवराज के आगे उसी की जनता को सामने डाल दिया जाता है और वो उसे काट देता है। लेकिन जो दूसरा युवराज होता है वो जनता को देख के रूक जाता है। पर पिक्चर का जो संदेश था बड़ा साफ था जो हमारे शास्त्र में बार बार कहा गया है कि राजा सिर्फ वो नहीं होता जो राज करे, जो ट्वीट कर दे, अपरांस में कोई मर जाए तो। जो ट्वीट कर दे बंगलादेश में कुछ हो रहा है तो लेकिन देश की राजधानी के अंदर जिसके मुख्य प्रधानमंत्री हैं उसपे वो उसी एमसीडी से कुछ सवाल भी न पूछे कि इतने लोग तड़प रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, अखबारों में आ रहा है, टीवी पे आ रहा है, दिल्ली के सदन में दो दिन से चर्चा हो रही है, एमसीडी के सदनों में हंगामा हो रहा है, उस पे कोई ट्वीट नहीं, उसपे कोई बयान नहीं, और पूरी सरकार की तरफ से कोई नहीं। ये आज का दुर्भाग्य है कि आज पिक्चरों में जो बार बार दिखाया जाता है कि जो डाकू हैं वो आज बीहड़ में नहीं हैं बल्कि सदनों में पहुंच गये, क्योंकि हम भी चुन के आए। बड़ा दुख होता है कि जनता को विश्वास नहीं रहा, जनता कहती है जब हम चिल्लाते हैं तब तो कोई आता नहीं, जब चुनाव हैं तो तुम सब आ जाओगे और आज चिल्ला चिल्ला के दिल्ली की जनता और दिल्ली के विधायक ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये जो हो रहा है, ये जो डकैती हो रही है ये वसूली नहीं है, ये बिल्कुल भी वसूली नहीं है, ये डकैती है क्योंकि जब सामने वाले को आप बता भी नहीं रहे कि किस लिए ले रहे हो, उसके गले के उपर तलवार रख के कह रहे हो देना पड़ेगा, इतना दे नहीं तो तेरी दुकान बंद हो जाएगी और कितना देगा, क्यूं देगा उसका कोई हिसाब नहीं है, ये तो फिरौती है, डकैती है सीधे सीधे। ये जो बार बार प्राब्लम आती है दिल्ली के अंदर मास्टर प्लान बनें,

दिल्ली के लिए मास्टर प्लान बनें, हर देश में हर सिटी के लिए बनते हैं उस वक्त ये आबादी को ध्यान में रखते हुए करा जाता है कि भई इतनी आबादी है, इतने रोजगार की जरूरत होगी, इतने मंदिर चाहिएं, इतने हास्पिटल चाहिएं, इतने स्कूलस चाहिएं, उसे मास्टर प्लान कहते हैं । जरूरत के साथ में बार बार उनमें तबदीलियां भी करी गईं, क्योंकि जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़नी चाहिए उससे काफी तेजी से महानगरों की तरफ बढ़ी है जिसमें से दिल्ली प्रमुख रूप से दिल्ली का नाम लिया जा सकता है । उसमें बदलाव किए गए, उसके बावजूद कुछ कमियां हैं और उसी वजह से लोग एंक्रोचमेंट करते हैं – रोड़ों के उपर रेहड़ी–पटरी के रूप में वो रोजगार के लिए करते हैं और मकानों में भी करते हैं जो फर्नीचर बनाते हैं। इसके उपर जब देश की सर्वोच्च न्यायालयों में बातें चलीं तो उन्होंने कहा कि इसे रोकना चाहिए। एक बात निकाली गई कि ठीक है जी ये फाईन भर देंगे तो इन्हें पास कर दिया जाएगा। इतना फाईन इतना जिसे कनवर्जन चार्ज हम शब्द दे रहे हैं वो इतना ज्यादा है कि कुछ लोगों के लिए तो किराया देने के बराबर है। अभी मेरे भाई कल हम पीछे बैठके चर्चा कर रहे थे शरद चौहान जी मुझे बता रहे थे कि उनकी विधानसभा में 50 गज की दुकान है 5 हजार गज का प्लाट है एग्रीकल्चरल लैंड है और वो आके 5 हजार गज के प्लाट में कहते हैं भई इतना कनवर्जन चार्ज देदो और जब वो हाथ–पैर जोड़ता है कि नहीं बाउजी मेरी तो 50 गज की है मैं तो कुछ नहीं हूँ, खेती की जमीन से इतना गुजारा होता है उससे 2–4 लाख रूपये मिलता है 10 लाख का बनाते हैं तो लाख रूपये लेके उसे छोड़ देते हैं। ये टोटल करप्शन बढ़ाने का एक तरीका है कि किस तरीके से लोगों को लूटा जाए और सभी को परेशान किया जाए और उनके दिमाग में बात डाल दी जाए कि तुम तो सब चोर हो, लोगों के दिमाग में डाल दिया गया कि तुम सब चोर हो और तुम से लाख रूपये देके भी

तुम्हारे उपर उपकार किया जा रहा है। ऐसा ही कुछ मैं नया नया विधायक बना था मादीपुर विधानसभा के अंदर कुछ बड़े बड़े शो रूम सील करे गये, शो रूम्स थे कुछ, कुछ फैक्ट्रीज़ थे। मुझ पे फोन आया और मैं उन्हें करने के लिए मैंने डीसी साहब को फोन मिलाया, डीसी साहब का फोन लगा नहीं उस वक्त तो मैं जहां डीसी साहब बैठते थे उनके पास में गया तो वहां पे जो हमारे कुछ भाजपा के साथी वो भी आए हुए थे तो उन्होंने कहा कि तुम इनके लिए क्यों आ गये पहली बात तो ये कि ये एमसीडी का मुद्दा है, तुम्हारे पे थोड़ी कुछ कहने जा रहा है। मैंने कहा लेकिन लोग तो हमारे ही हैं कहते हैं तुम्हारे नहीं है वोटर थोड़े ही हैं तुम्हारे, फैक्ट्रियां ही तो है वोटर कहीं और के है क्यों चिन्ता करते हो। हर चीज वोट से जोड़ दी जाए अगर मेरे वोट नहीं हैं तो मरने दो, ये इनकी सोच है। और हमारी सोच थी कि हमारे पास कोई आ गया, कहीं से भी आ गया, कहीं से कोई आ गया तो उसकी बात सुनें, उसके लिए हम जो कर पाएं उसी के लिए तो विधायक हैं। विधायक एक विधानसभा के हैं लेकिन जनप्रतिनिधि जनता के हैं और जनता कनफाईंड नहीं है, दीवारों में नहीं बंधी हुई कि इसके बाहर का कोई आ गया तो मैं उसके लिए काम नहीं करूंगा। उनको करके खुलवाया गया, सेम कहानी हमारी सरकार की डीपीसीसी के द्वारा हुई कि पॉल्यूशन के नाम पे कुछ फैक्ट्रियां सील हुईं, उन लोगों ने गुहार लगाई, हम एन्वायर्नमेंट मिनिस्टर से मिले उसके बाद में इमरान भाई ने बड़ी मदद करी साथ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी मदद करी, उनसे 5 लाख रूपये की गारंटी मांगी गयी कि 5 लाख की गारंटी ले लो, अगर तुमने अबकी बार पॉल्यूशन के लिए जो तुम्हारे प्लांट लगने हैं, ढंग से नहीं चलाए तो इसे फॉरफिट कर लेंगे। एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई आदरणीय मंत्री जी उसमें बैठे, स्वास्थ्य मंत्री जी उसके अंदर बैठे क्योंकि सेक्रेटरी या उद्योगमंत्री वो थे और मुख्यमंत्री जी भी बैठे, तीनों मंत्री साथ में बैठे और जो कंसर्न

अथॉरिटीज़ थीं, उनको बुलाया गया और जो फेडरेशंस थी उनको बुलाया गया और उस 5 लाख रूपयों में वो भी मुख्यमंत्री जी ने कह के हटा दिया कि ठीक है 5 लाख हटा देते हैं, ये जो तुम में से जो कुछ बहुत छोटे उद्योगपति हैं, लेकिन अगर पॉल्यूशन करा तो तुम्हें बंद कर देंगे इसके अलावा चलाओ और वो फैक्ट्रियां अगले दिन से डिसील होनी शुरू हो गयी,

अध्यक्ष महोदयः कन्क्लूड करिए, प्लीज़ राजेश जी, कन्क्लूड करो।

श्री राजेश गुप्ताः मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पहले ऐसा लगता था कि ये जो फैक्ट्रियां सील हो रही हैं इनमें कुछ खामियां रह गयी, कुछ कमियां रह गयी, किसी के घमंड की वजह से हो रही है कोई ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन आज ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल सोची समझी साजिश है, ये छोटी छोटी फैक्ट्रियां सारी बंद हो जाएं और बड़ी बड़ी यह एफडीआई के रूप में बड़े बड़े शो रूम खुल जाएं और ये मैं नहीं कह रहा, ये आज के वितमंत्री जो उस वक्त बड़े बड़े आप क्लिपिंग देख सकते हैं, वीडियो दिख जाएंगी आपको? जो कहते थे कि अगर ये एफडीआई आ गयी तो हमारे जो व्यापारी हैं छोटे–छोटे, सारे मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, इनके बच्चों को नौकरी करनी पड़ेगी और कौन खोलेगा इन दुकानों को बड़ी बड़ी दुकानें आएंगी उसके जो मालिक होंगे वो अमरिकन होंगे, इंग्लैंड के लोग होंगे। ये 1 लाख करोड़ रूपये ले गये, कहां गये किसी को नहीं मालूम, कुछ भी बात बताते नहीं हैं। मुझे अपने जरनैल भाई ने बताया, मैं रोज एड देखता हूँ जी आजकल सबसे ज्यादा एड आती है और जिनके जो इनसे पहले गुरूजी थे जो बताते थे कि जिसकी सबसे ज्यादा एड होती है यानि कि उसके अंदर बहुत बड़ा जो प्रोफिट की मात्रा जो एड में दे रहा है यानि कि वो सामान ठीक नहीं है। उनकी मृत्यु हो गयी, हार्ट अटैक से हुई थी जो बहुत ज्यादा स्वदेशी के लिए चिल्लाया करते

थे, लेकिन आज बाबा रामदेव की एक एड आती है जो वो बार बार कहते हैं कि ये विदेशी जो हैं न विदेशी कंपनियां...

अध्यक्ष महोदयः राजेश जी, कंक्ल्यूड करिए प्लीज़ कन्क्लूड करिए अब कंक्ल्यूड करिए

श्री राजेश गुप्ताः मेरा ये कहना है अध्यक्ष जी कि जिस तरीके से सीलिंग का ये काम चल रहा है और अभी हमारे एक साथी ने बीजेपी के साथी ने कहा कि इसको रोकना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि हम सिर्फ यहां बातें न करें, ये हमारा साथ दें ये सिर्फ 4 है फिर भी हमारे साथ चलें, जहां कहीं भी सीलिंग आ रही है, इनके एमसीडी में बहुत साथी हैं, तीनों मेयर इनके हैं और भारत में सरकार इनकी है, या तो ये तरीके से सांविधानिक तरीके से वहां जाके फिर वहां हो आएं, और नहीं तो हमारे साथ में रोड़ पे आज जाएं और ये हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाएं कि एक भी सीलिंग नहीं होने देंगे, यहां पे इसका वचन दें हम इनके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः सोम दत्त जी

श्री सोम दत्तः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय मैं सदर बाजार विधानसभा को रिप्रेजेंट करता हूँ और सदर बाजार दिल्ली नहीं देश की सबसे पुरानी हिस्टोरिक मार्किट में से एक है बल्कि सबसे पुरानी मार्किट कहेंगे और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस सदन में ये बात अपनी कहना चाह रहा हूँ आपके सामने कि एमसीडी 2021 मास्टर प्लान 2021 के नियमों को वॉयलेट कर रही है, मैं बिल्कुल क्लियर आपकी जानकारी में 2 प्वाईंट्स बताना चाह रहा हूँ। मास्टर प्लान 2021 में साफ लिखा हुआ है कि 1962 से पहले की जो भी मार्किट्स हैं उनको बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा और

आज सदर बाजार जो ऐतिहासिक बाजार है, उसके अंदर सारे व्यापारियों को, सारी दुकानों को नोटिस सर्व किए जा रहे हैं, उनमें एक डर फैलाया जा रहा है सीलिंग का, ये मास्टर प्लान 2021 में नहीं लिखा हुआ था, ये बिल्कुल क्लियरली मेंशंड है कि 62 से पुरानी मार्किट को नहीं छेड़ा जाएगा पहली बात तो ये और दूसरा प्वाईंट ये कि ये भी मास्टर प्लान 2021 में लिखा है कि रजिस्ट्रेशन, कनवर्जन चार्ज और पार्किंग चार्ज केवल 10 साल के लिए वैलिड होगा और अब 10 साल का टर्म साल 2006–2007 से गुजर चुका है, अब किस बात के कनवर्जन और पार्किंग चार्ज क्लेक्ट किए जा रहे हैं। पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया था मास्टर प्लान 2021 लेकर आए थे, उसमें साफ लिखा हुआ था कि 10 साल केवल 10 साल के लिए ये वैलिड होगा और ये टर्म पूरा हो चुका है, व्यापारी हमारे पास आते हैं, वो वर्डिंग्स, वो नोट मास्टर प्लान 2021 की बुक लेकर आते हैं, दिखाते हैं कि वो उस दायरे में नहीं आते, लेकिन एमसीडी मनमाने तरीके से, मनमाने तरीके से पूरी खुली लूट पे उतारू, पूरे तरीके से सीलिंग ड्राइव पे उतारू है, उनके आदमी आते हैं, नोटिस देते हैं, अनाप शनाप पैसे बताते हैं और पैसे देके सैटिंग कर लेते हैं फिर कोई कुछ नहीं होता। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कमिशनर, एमसीडी उत्तरी दिल्ली नगर निगम को बुलाया जाए, उन्हें बताया जाए कि 2021 के मास्टर प्लान जो बना है उसका वॉयलेशन न किया जाए, ये सदन में वो आएं और इस मुद्दे पर बयान दें। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद धन्यवाद। एन डी शर्मा जी।

श्री नारायण दत्त शर्माः धन्यवाद अध्यक्ष जी आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है एक चीज है अध्यक्ष जी एक अच्छी सरकार जो होती है एक अच्छा जो मुखिया होता है उससे किसको डरना चाहिये भ्रष्टाचारियों को डरना चाहिये, चोरों को डरना चाहिये, लुटेरों को डरना चाहिए लेकिन आज देश

का व्यापरी डर रहा है दिल्ली के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर आज सिर्फ व्यापारी डर रहा है किसान आत्महत्या कर रहा है किसानों की आत्महत्या से पेट नहीं भरा तो व्यापारियों को भी आत्महत्या करवाना चाहती है ये मोदी सरकार। आम आदमी पार्टी को आज से तीन साल पहले एक महीना कम है तीन साल में इस दिल्ली की जनता ने चुना था मुझे लगता है कि बार बार वही दर्द, वही टीस है कि इस दिल्ली की जनता को किसी भी तरीका से तकलीफ दी जाये आम आदमी को रेहड़ी पटरी वाले को अब इस व्यापरी को तो आम आदमी पार्टी के सारे विधायक सभी जहां भी मार्किटों में सीलिंग हो हमें पता नहीं है कि किस तरीके से इसको ये ठीक करेगें लेकिन हम वहां जा के जनता के साथ में खड़े होगें और अपनी गिरफतारी देगें अगर ये सीलिंग बंद नहीं होती है या तो बीजेपी के साथी एक तरफ मेरी विधानसभा है मेरी विधानसभा के अंदर रोज जेसीबी और हथौड़ा आता है जी तोड़ने के लिये एक भी मकान बिना पैसे दिये नहीं बनता है वैसे 15 पंद्रह सौ गज की फैक्ट्री और बड़े बड़े स्टोर बन जाते हैं क्योंकि वो इनको रिश्वत दे सकते हैं गरीब आदमी दे नहीं सकता रोज मुझे वहां खड़ा रहना पड़ता है कई बार मुझे बहुत सारे काम छोड़ने पड़ते हैं तो मैं तो ये कह रहा हूं जी अगर इस तरीके से ठीक नहीं होगें तो सबको एक बार दोबारा से इस एमसीडी की सिलिंग के खिलाफ आंदोलन करना पडेगा और तीनों कमिशनरों को एक बार विधानसभा में बुला लीजिये कन्वर्जन चार्ज के नाम पर आपने सबसे पैसे ले लिये उसके बाद भी सीलिंग हो रही है लोगों को कब तक डराया जायेगा कब तक दिल्ली के लोगो ंसे बदला लिया जायेगा। मैं आप सभी सदस्यों की बातों से सहमत हूं तीनों कमेटी के एमसीडी के कमिशनरों को बुला के उनसे पूछा जाये और उनसे संज्ञान लिया जाये कि इसका क्या मतलब है जब आपने इनसे कनवर्जन चार्ज जमा करा लिया है उसके बाद भी क्यों सीलिंग हो रही है। जय हिंद जय भारत।

अध्यक्ष महोदयः एस के बग्गा जी।

श्री एस के बग्गाः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने सीलिंग के मुददे पर मुझे बोलने का मौका दिया अभी पूरी दिल्ली के व्यापारी और जमना पार में कृष्णा नगर विधानसभा से आता हूं मेरे यहां पर जगत पुरी मार्किट है कृष्णा नगर है, गीता कालोनी है और लोग इतने भयभीत हैं इस नाम से कब सीलिंग वाले आ जायें । वे कहते थे गब्बर आयेगा एमसीडी वाले आयेगें और सीलिंग करेगें ये जितना भी डर इनमें फैला रखा है पैसा लेने के बाद भी ये लोगों को तंग कर रहे हैं अभी 15 दिन पहले की बात है हमारे जमना पार के विधायक अनिल वाजपेयी जी, नीतिन त्यागी जी, राजू धिंगान जी, मनोज कुमार जी और मैं भी और हमारे सारे निगम पार्षद कमीशनर साहब से मिलने गये तो पहले तो वो कहते मेरे पास टाईम बहुत कम है जल्दी मेरे से बात करो बड़ी शर्म की बात है कि टाईम देने के बाद कमीशनर साहब कहते हैं मेरे पास टाईम नहीं है पूरा बर्निंग ईशू था ये। मैंने पूछा कमिशनर साहब से क्या आप नोटिस देते हैं किसी को कहते हैं नहीं मैंने कहा नोटिस देना एपेक्स कोर्ट की जजमेंट है कि किसी को भी तंग करने से पहले कोई भी आप उससे पूछेगें शो कॉज नोटिस देना जरूरी है नोटिस के बाद नोटिस की सर्विस बहुत जरूरी है नोटिस देना सफिशियेंट नहीं है जब तक नोटिस उसके हाथ में नहीं जाये जिसको आपने बुलाना है उसके बाद तीसरी बात की सफिशियेंट टाईम दें उसको बोलने का। हर व्यक्ति को अधिकार है कोर्ट की जजमेंट है और तीनों की काम इन्होंने पूरे नहीं कर रखे पब्लिक को तंग करने का सोचा हुआ है उन्होंने ये कानून कहीं भी पालन नहीं कर रहे तो मेरी आपसे दर्खास्त है कि तीनों कमिशनरों को बुलाकर उनके एकाउंटस मंगाये जायें इनकी बैलेंस शीट मंगाई जाये कि पैसा कहां जाता है एक टैस्ट मनी थी एक हजार करोड़ इनके पास ये

डेवलेपमेंट पर लगनी थी जो नहीं लगाई इनके खिलाफ एफआईआर हो इनको यहां बुलाया जाये इनके खिलाफ मुकदमें दर्ज हों। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं उम्मीद करता हूं कि इनको बुलाकर पब्लिक के सामने इनका जो भी इन्होंने पब्लिक को डसा है वो उनके सामने आये। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः प्रवीण देशमुख जी।

श्री प्रवीण कुमारः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय व्यापारी लाख चाहे तो क्या होता है व्यापारी लाख चाहे तो क्या होता है वहीं होता है जो मंजूरे नरेन्द्र मोदी होता है। वो आजकल खुदा की तुलना अपवने आप से कर रहे हैं ना एक बार रात में सोते हैं तो उन्हें सपना आता है कि नोटबंदी नोट बंद हो गये नये नोट बीजेपी वाले के पास पुराने नोट ज्यादा हो गये या खत्म हो गये तो नये नोट ईशू कर देते हैं उसके बाद उन्हें सपना आता है कि जीएसटी लगानी चाहिये, व्यापार को कुछ ना कुछ नया करना चाहिये तो जीएसटी लगा देते हैं उसके बाद नई चीज अब आई सीलिंग लगा देते हैं व्यापारी ने सारे मतलब पूरे देश जग जाहिर है ये तो कि व्यापारियों का जो वोट है वो बीजेपी को जाता है लेकिन आजकल व्यापारियों की दुश्मन बनी पड़ी है बीजेपी उसके बाद लगातार जिस तरीके से अभी मैं कल देख रहा था एक विडियो यू टयूब पर जिसमें कि एक डिफेंस कालोनी में व्यापारी की सीलिंग जब उसकी दुकान की सीलिंग हुई आप देखिये अध्यक्ष महोदय किस तरीके गिड़गिड़ा रहा है वो व्यापारी इन सीलिंग के पुलिस अफसरों के सामने एमसीडी के अफसरों के सामने किस तरीके गिड़गिड़ा रहा है और इस गिड़गिड़ाने के बाद इसने ये भी बोला कि मैंने बीजेपी को वोट किया था और आज के बाद मैं बीजेपी को वोट नहीं करूंगा और ये नौबत कर दी है बीजेपी वालों ने एमसीडी वालों ने

इन दुकानदारों की ये हालत कर दी है। अध्यक्ष महोदय, मैं कल हरदीप पुरी जी का वहां पर एक यू टयूब पर इस संसद में जो सीलिंग के ऊपर बात उठाई है उस ईशू को भी सुन रहा था उसमें हमारे सांसद ने जब इस बात पर बोलने का मौका आया तो हमारे सांसद जी महेश गिरि जो हैं उन्होंने सारी बातें छोड़ के सीलिंग की तो बात ही नहीं करी और ऊपर से दूसरी बात कहते हैं कि दिल्ली में जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिये। दिल्ली में क्या होने दें दिल्ली वालों ने उन्हें जब वोट दे के इसलिये जिताया था कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दें क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि दिल्ली में कोई दिक्कत हो पूर्वी दिल्ली में कोई दिक्कत हो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि डीडीए के साथ एमसीडी के साथ बैठ कर समन्वय बनायें और यहां पर जो भी ईशू हो रहा है उसको सोर्ट आऊट करें लेकिन नहीं कहीं चाहे वो सीलिंग हो चाहे वो कोई सा भी ईशू हो ना वो आजतक दिखते हैं ना वो आज तक मिलते हैं ना उनके पास कोई जाता है ना वो किसी का काम करते हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय, जो इससे पहले मैंने बात उठाई थी आपके सामने कि एक पार्किंग का प्रोजेक्ट है तीन मंजिला पार्किंग का लेकिन वो पार्किंग का प्रोजेक्ट जो है वो 200 करोड़ पर पहुंच गया इस समय उसी तरीके से ये कनवर्जन चार्ज के नाम पर हजार करोड़ रूपये वसूल लिये गये लेकिन काम यहां तक अभी तक कई सारे मार्किटस में चालू भी नहीं हुआ और अध्यक्ष महोदय ये जो पार्किंग की मैं बात कर रहा हूं वो पार्किग में वहां पर बाहर एक पत्थर लगा हुआ है कि ये पार्किग का उदघाटन माननीय महेश गिरि जी द्वारा किया गया है लेकिन वापिस उसी बात पर आना चाहूंगा चाहे वो पार्किग हो, चाहे वो सीलिंग हो चाहे पूरी दिल्ली का कोई सा भी मुददा हो लेकिन दिल्ली के सांसद वोट लेकर बैठ गये बस उन्हें चिन्ता नहीं है लोगों की लोग इस तरीके से लोग यहां पर त्राहि त्राहि हो रहे हैं उन्हें चिन्ता नहीं है कि लोगों

की दुकानें किस तरह से सील हो रही हैं उनको चिन्ता नहीं है कि लोग किस तरीके से सड़कों पर उतरने को आतुर हैं किस तरीके से एमसीडी द्वारा परेशान किया गया किस तरीके से पुलिस द्वारा परेशान किया गया किस तरह डीडीए द्वारा परेशान किये गये। अध्यक्ष महोदय, ये सातों सांसद जो हैं वो पूरी तरीके से ईररिस्पॉनसिबल तरीके से पूरे अपने लगे हुए हैं और अध्यक्ष महोदय, आज वे सीलिंग के जब विषय में जब बात हुई तो मैंने डीसी आफिस में भी मीटिंग करी सुबह सुबह डीसी साहब से मिला मैं और मैंने उनसे बोला क्योंकि मेरे इलाके में भी एक निजामुददीन क्षेत्र है वहां पर एक गेस्ट हाऊस बंद करने का सीलिंग का नोटिस आया है कयाम गेस्ट हाऊस का उससे मैंने बात करी कहता है भईया हमने सारे पैसे भर रखे हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमें पता नहीं वो चेक भी दिखा रहा है वो पेमेंट भी दिखा रहा है लेकिन उसके बावजूद वो कहता है मुझे पता नहीं मेरी दुकान क्यों सील कर रहे हैं बस सीधे उठा कर नोटिस भेज दिया की सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है और यहां पर आपकी दुकान सील होने वाली है बस ये उठा कर नोटिस भेज दिया और अब आप दुकानों के और एमसीडी दफतरों के चक्कर काटते फिरो लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं यहां पर पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से डायरेक्टली और मैंने उस समय डीसी साहब से भी ये बात करी कि इसका जब सीलिंग का इसे पैसे भर दिये और इसका सीलिंग का नोटिस है और किस बिहाफ पर आपने नोटिस दिया है तो उन्होंने मुझे बताया कि ये थोड़े दिन चलेगा बाकी तो खत्म हो जायेगा तो अध्यक्ष महोदय, मैं यहां बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से एमसीडी यहां पर लचर रूप अपना रही है जिस तरीके से मेयरस और जितने काऊंसलर हैं जो कि सत्ता में सत्ताधारी पक्ष है बीजेपी एमसीडी में और उनके सांसद हैं लेकिन जिस तरीके से उनके काम के प्रति उनका रूख है मुझे लगता है बहुत लचर है और जिस तरीके से दिल्ली की जनता

ने वोट देकर एमसीडी में भी जताया सांसद भी बनाया लेकिन उसके बावजूद भी वो जिस तरीके से उनको रियेक्ट करना चाहिये वो नहीं कर रहे उससे भारी रोश है। शुक्रिया ।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद विजेन्द्र गर्ग जी।

श्री विजेन्द्र गर्गः शुक्रिया अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया। इससे पूर्व कि मैं इस मुद्दे पर अपनी बात रखूं, मैं आपके द्वारा जो विधान सभा परिसर की दीवारों पर महापुरूषों के चित्र लगाए गए हैं उसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं क्योंकि इन महापुरूषों के चित्रों से और इनकी जीवनी से हमें सदैव प्रेरणा मिलती है, इसके लिए आपका बहुत–बहुत शुक्रिया। अध्यक्ष महोदय, सीलिंग का मुद्दा दिल्ली में व्यवसाय करने वाले दुकानदारों के परिवारों की रोजी रोटी से जुड़ा है। बीजेपी शासित दिल्ली में तीनों नगर निगम बड़े ही अमानवीय, करूर और अभद्रता के साथ दिल्ली के व्यापारियों के प्रतिष्ठान और उनकी दुकानें सील कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा में मैंने देखा कि कुछ दुकानों से दुकानदारों को अपना कैश और जरूरी सामान तक नहीं निकालने दिया गया, आनन फानन में उनकी दुकानों को सील कर दिया गया। आज व्यापारियों में ये माहौल है, उनको लग रहा है कि हम अपने स्वतंत्र देश भारत में नहीं बल्कि किसी गुलाम मुल्क में रह रहे हैं। इस तरह का भय और अराजकता का वातावरण बीजेपी शासित तीनों नगर निगम ने दिल्ली के अंदर पैदा किया हुआ है।

अध्यक्ष जी, मैं अपनी विधान सभा की दो घटनाएं इस सदन में रखना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडापुर गांव के अंदर एक चाट–खोमचे की दुकान थी। उस दुकान का नाम के.सी.फुडस के नाम से था। वहां पर बीजेपी के विधान सभा का चुनाव लड़े हुए, हारे हुए प्रत्याशी ने और वहां

के निगम पार्षद के आदमियों ने खड़े होकर उस दुकान को सील करवाया। ये इससे बेहद शर्मनाक बात किसी राजनितिक दल के लिए हो नहीं सकती है क्योंकि वो दुकान मालिक उनकी जो डिमांड थी वो उसको पूरा नहीं कर पा रहा था, इसके कारण से बड़े अमानवीय तरीके से उनके कर्मचारियों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार करके उस दुकान को चंद मिनटों के अंदर सील कर दिया गया। उसको समय भी नहीं दिया गया कि वो अपना जरूरी सामान और कैश भी दुकान से बाहर निकाले। इसी प्रकार से अध्यक्ष जी, एक घटना मेरे विधान सभा क्षेत्र करोल बाग, सरस्वती मार्ग पर हुई। एक प्रोपर्टी के अंदर 17 छोटी–छोटी दुकाने हैं जो मुश्किल से पांच बाई आठ फुट की होंगी या दस बाई आठ फुट की होंगी। उन दुकानों को 50 वर्षों से वहां पर वो व्यापारी छोटा–मोटा काम करके अपनी गुजर–बसर कर रहे थे। पहले तो दिल्ली नगर निगम उन दुकानों को सील कर जाता है पॉल्यूशन के नाम पर जबकि वहां पॉल्यूशन का कोई कारोबार नहीं था। कोई आदमी वहां सब्जी बेच रहा था, कोई चने बेच रहा था, कोई वहां पर जूस बेच रहा था, इस प्रकार का काम था लेकिन पॉल्यूशन के नाम पर उन 17 छोटी दुकानों को पहले एमसीडी ने सील किया और अब डीडीए लगातार उनके यहां उन दुकानों को तोड़ने के लिए जा रही है। क्या मैं पूछना चाहता हूं इस केंद्र की सरकार से और नगर निगमों से कोई सील की हुई दुकानों को भी डेमोलिश किया जाता है और मुझे आज का टाइम था डीडीए द्वारा उन दुकानों को डेमोलिश करने का और मुझे लगता है कि वो दुकानें आज डेमोलिश कर दी गई होंगी तो इतने करूर तरीके से व्यापारियों को चोर समझा जा रहा है भाजपा के द्वारा, जो उनके परिवार आज दाने–दाने को मोहताज होने के कगार पर है उनके बच्चों की पढ़ाई छूट रही है लेकिन ये इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। ये एक अपने सत्ता के नशे में चूर होकर के कार्य कर रहे है।

अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा के एक सोशल एक्टिविस्ट और आरटीआई एक्टिविट्स है श्रीमान एस.पी.गुप्ता जी, उन्होंने दिल्ली नगर निगम में एक आरटीआई लगाई कि आपके यहां जो कन्वर्जन चार्ज और पार्किंग का पैसा जमा हुआ, उस पैसे का क्या हुआ? वो पैसा आपने कहां खर्च किया? बड़े अफसोस की बात है 900 पन्नों का जवाब एमसीडी उनको देती है, एक पूरे का पूरा पुलिन्दा पकड़ा दिया जाता है लेकिन उन पन्नों में ये कहीं नहीं लिखा होता कि ये पैसा उन्होंने किस मद में खर्च किया है। उसमें ये लिखा है कि ये पैसा हमने फलाँ–फलाँ जोन को दे दिया है और इस पैसे का कोई हिसाब नहीं है। जो पैसा मार्केट के डवेलेपमेंट के लिए लगना चाहिए, जो पैसा पार्किंग बनाने के लिए लगना चाहिए, जो पैसा वहां शौचालय बनाने के लिए लगना चाहिए वो पैसा इन्होंने खुर्द–वुर्द कर दिया और उस पैसे की एमसीडी ने बैठकर बीजेपी से मिलकर बंदर बांट कर ली उस पैसे की। एक हजार करोड़ रूपये का ये सीधा–सीधा घोटाला है। एक हजार करोड़ रूपये का ये घपला एमसीडी ने किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं जैसा कल हमारे काबिल साथी सौरभ भाई ने ये रखा था, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस जन विरोधी सीलिंग अभियान को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए तीनों निगमों के आयुक्तों को इस सदन में बुलाकर उनसे कन्वर्जन चार्ज और वन टाइम पार्किंग चार्ज के रूप में जमा हुए हजारों करोड़ रूपयों का हिसाब लिया जाए और सीलिंग को रोकने का उचित रास्ता निकाला जाए। अभी हमारे माननीय साथी ओ. पी.शर्मा जी तथ्यों की, नियमों की और शिक्षा की बात कर रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि मानवता से बढ़कर कोई नियम नहीं है अगर किसी की रोजी–रोटी छीनी जा रही है तो हमें नियमों से ऊपर उठकर भी काम करना पड़ेगा और उनको राहत देनी पड़ेगी। मैं इनसे अपील करना चाहता

हूं कि ये आए हमारे साथ यू.डी. मिनिस्टर के पास चले, गृह मंत्री के पास चले और हम उनसे गुजारिश करे, हाथ जोड़कर निवेदन करे कि दिल्ली में जो आप कहर बरपा रहे है, इस कहर को रोक लीजिए, नहीं तो दिल्ली का आम जन सड़कों पर आ जाएगा और आपकी ईंट से ईंट बजा देगा.

अध्यक्ष महोदयः कन्क्लूड करिए विजेन्द्र जी।

श्री विजेन्द्र गर्गः मैं आह्वान करता हूं कि ये बीजेपी के चारों साथी भी हमारे साथ चले। हम यू.डी. मिनिस्टर के पास जाने को तैयार है, हम गृह मंत्री के पास जाने को तैयार है लेकिन इस सीलिंग को हर हालत में रोका जाए ये मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः अजय दत्त जी। संक्षेप में रखिए प्लीज।

श्री अजय दत्तः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने अंततः मुझे बोलने का मौका दिया। मैं कुछ तथ्यों पर बात करना चाहता हूं। 2006 में जब एमसीडी को कहा गया कि आप कन्वर्जन चार्ज लीजिए, उससे आज तक यहां पर बीजेपी के एमसीडी में बीजेपी की सत्ता थी। 1000 करोड़ का कलेक्शन हुआ, 58 करोड़ रूपये मात्र खर्च किए गए और 942 करोड़ का अभी तक कोई अता पता नहीं है। मैं ये बीजेपी की एमसीडी में जो सरकार रही तो डायरेक्ट रिस्पोंसिबिलिटी उस सरकार की बनती है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आपने यह पैसा कहां खर्च किया और क्यों खर्च किया तो मैं अपने वक्तव्य को शुरू करने से पहले एक दो लाइनें कहना चाहूंगा –

''छलकर बीजेपी ने देश की सत्ता छीन ली,

सीलिंग कर दिल्ली के व्यापारियों की नींद छीन ली,

अब और क्या–क्या करना बाकी है,

अब तो बीजेपी शासित एमसीडी ने दिल्ली के लोगों की रोटी,

दिल्ली के व्यापारियों की रोटी छीन ली।''

तो बीजेपी ने एमसीडी में शासन किया। सत्ता उनकी थी। एमसीडी में लोग उनके थे, कार्यभार वो चला रहे थे तो जवाब इन्हें देना पड़ेगा और उसके बाद जब व्यापारी पहले से ही नोटबंदी के कारण त्रस्त है, जीएसटी की इतनी बड़ी मार से वो त्रस्त है। व्यापारी जो अपने काम धंधे से इस देश का गौरव बढ़ाता था, दिल्ली का गौरव बढ़ाता था, सवा सौ लाख करोड़ रूपये का टैक्स दिल्ली से जाता था, उस व्यापारी को आज इन्होंने दर–दर की ठोकर खाने के लिए मजबुर कर दिया और एक डीडीए के एडिशनल डायरेक्टर रहे है पूर्व में आर.जी.गुप्ता जी उन्होंने आज के अखबार में लिखा है, उसमें लिखा है कि डरा कर रखना चाहते हैं दिल्ली के लोगों को। उसमें ये लिखा है कि 1873 से 1956 तक दिल्ली को, पुराने समय में आजादी से पहले की, दिल्ली को एक प्लान तरीके से बनाया जाता था तो आज से पहले की सरकारों ने इसको प्लान नहीं किया जिसकी वजह से आज व्यापारियों को ये देखना पड़ा और ये सरकार पुरानी सरकारों की प्लानिंग का नतीजा भी है और उसके बाद जब लोग स्टैबलिश हो गए उन्होंने अपने धंधे खोल लिए उनकी रोजी–रोटी शुरू हो गई तो लोगों ने उनको बार–बार रोकना चाहा और आज व्यापारियों को पहले कहा गया कि भईया हम तो 89000 पर स्कैवयर मीटर के हिसाब से आपसे कन्वर्जन चार्ज लेंगे। अब उनको बीच में शगुफा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हम 22 हजार पर स्कैवयर यार्ड के हिसाब से आपसे पैसा वसूल करेंगे। अब आप सोचिए अगर किसी व्यापारी के पास 100 स्कैवयर मीटर, 200 स्कैवयर मीटर की दुकान है अगर 200 स्कैवयर मीटर की दुकान है तो उसे 44 लाख रुपए

पे करने हैं और उसका समय बहुत ही कम है। उसके बाद व्यापारियों को डराने की ओर मुहिम चल रही है और ये मुहिम एक्चुअली एक बहुत बड़े करप्शन की साजिश है की पहले व्यापारियों को डराया जाए उनको कहा जाए कि भई आप पे लाखों रुपए का कन्वर्जन चार्जिज है और अगर आप नहीं देते तो आपको रिश्वत देनी पड़ेगी और ये एमसीडी रिश्वत लेने के लिए आप सभी को पता है बहुत अच्छे से मशहूर है। मैं एक छोटा सा किस्सा अपनी विधान सभा का बताता हूं आज से करीबन 6 महीने से मेरे क्षेत्र की आरडब्ल्यूए आ रही है कि हमारा एक रोड़ है उस पर अतिक्रमण हो रखा है एमसीडी के कमिश्नर को, एमसीडी के डीसी को कई बार लिखा काम से कम 10 बार मैं भी उनसे मिला और मैंने कहा कि भई ये अतिक्रमण हटा दो इससे रोड़ की व्यवस्था खराब हो रही है। तो एमसीडी के कमिश्नर ने ये कहा कि मेरे ऊपर, ऊपर से एमसीडी के नेताओं का दबाव है ये उनका ब्यान है मैं आज यहां रिकोर्ड में दर्ज कराना चाहता हूं वो उन छोटे से अतिक्रमण को नहीं हटा पाए और पूरी दिल्ली में आज सीलिंग चल रही है उसको रोकने के लिए उन्होंने कोई पोलिसी नहीं बनाई। तो ये करप्शन की बहुत बड़ी मार से आज पूरी दिल्ली त्रस्त है। मैं ये कहना चाहता हूं जो पैसा इन्होंने लिया क्या उससे मार्किट का कोई डवलपमेंट किया, क्या कहीं कोई टायलेट बनाए, क्या कहीं फुटपाथ बनाए, क्या कहीं कोई सड़क बनाई या सिर्फ बीजेपी ने, बीजेपी की शासित एमसीडी में जो सरकार है उन्होंने लोगों को व्यापारियों को डराने का धंधा बनाया हुआ है और इसीलिए आज पहले ये तलवार बीजेपी के लोग और बीजेपी की एमसीडी में शासित सरकारें व्यापारियों पे लटका रही है और उसके बार करप्शन का पूरा चिट्ठा और पूरी साजिश के साथ व्यापारियों को लूटा जाएगा।

अध्यक्ष महोदयः कन्क्लूड करिए अजय दत्त जी, प्लीज अब।

श्री अजय दत्तः सर मैं आपसे एक–दो तथ्यों पर ओर बात करूंगा मैं लम्बी–चौड़ी बात ना करके। ये कहूंगा की अगर दिल्ली में इस तरीके से चलता रहा तो क्या इस देश का व्यापारी यहां काम कर सकता है और ये दुकाने कितनी बड़ी हैं आप देखिए 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर की दुकानें है और इन दुकानों में छोटे–छोटे व्यापारी है। ये एक सोची–समझी साजिश के तहत बड़े–बड़े उद्योगपतियों को, बड़े–बड़े मॉलों को चलाने की साजिश है, छोटे व्यापारियों को बंद कर दो और बड़े–बड़े मॉलों को चला दो, छोटे लघु उद्योगों को खत्म कर दो और बड़े उद्योगों को बढ़ावा दे दो मुझे इसमें साजिश की बू आ रही है। एक लास्ट बात कहते हुए मैं बात खत्म करूंगा मैं इस मोनिटरिंग कमेटी, हमारी साउथ एमसीडी के सारे विधायक और सारे पार्षद हम लोग एक मोनिटरिंग कमेटी के पास गए, हमने भूरेलाल जी से भी मुलाकात की, जिसकी अध्यक्षता मैं कर रहा था और हमने उनसे 1 घंटा बात की और उनसे रिक्वैस्ट की, कि आप इसको रूकवाइए, उसके बाद हमने एमसीडी के कमिश्नर से भी 4 बार मीटिंग की लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। तो मैं आपसे दरख्वाशत करता हूं कि आप यहां पर एमसीडी के,एसडीएमसी के कमिश्नर को बुलाई उनसे पूछिए की आप जो सड़कों पे अतिक्रमण हो रहे हैं उसको नहीं रोक रहे हैं। आप सीलिंग करवा रहे हैं और लोगों के धंधे बंद करा रहे हैं इसके लिए आप उनसे बात कीजिए, धन्यवाद आपने बोलने का समय दिया।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। मैं अभी जो वक्ता बाकी हैं मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं आज डिप्टी सीएम साहब को भी, मुझे भी जापान का एक डेलीगेशन आया हुआ है उसमें यहां से लगभग 5.30, पौने 6 निकलना है, तो संक्षेप में जो वक्ता बाकी हैं अपनी बात रखेंगे, श्री जगदीप जी।

श्री जगदीप सिंहः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। लेकिन आज मैं 2 मिनट आपसे फालतू जरूर चाहूंगा। बहुत गम्भीर मुद्दा है जी, लोगों की रोजी–रोटी का सवाल है, थोड़ा सा यहां पर जो बात कही जाएगी शायद पूरी दिल्ली की जनता के कान तक पहुंचेगी क्योंकि टीवी तो हम लोगों को दिखाया नहीं गया। बस मैं आपको कुछ चीजों के एग्जाम्पल लेके बताना चाहता हूं कि एक कम्पनी जो होती है वो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइडर होती है, थोड़ी सी कन्सीडरेशन लेती है जिसमें उसको प्रोफिट और उसमें उसकी कॉस्ट लगी होती है, इसी तरीके से हमारी सरकार जो होती है वो भी एक लाइन ऑफ बिजनेश पर चलती, जहां वो पूरे देशवासियों को सर्विस प्रोवाइड करती है विदाउट मेकिंग प्रोफिट, तो ये गवर्नमेन्ट भी जो है एक कम्पनी की तरह सर्विस प्रोवाइडर है। हम लोग उसको चुनके भेजते हैं और वो चुनने से पहले अपनी एक ऐड करते हैं जैसे कम्पनी अपनी ऐड करती है कि ठंडा बोले तो जैसे इस तरीके से तो कम्पनी जिस तरीके से ऐड करती है। सरकार भी अपनी ऐड करती है। जो आज केन्द्र में बैठी हुई सरकार ने अपनी ऐड की थी जिसका जिंगल उन्होंने रखा था अच्छे दिन आएंगे, क्या जिंगल था जी, अच्छे दिन आएंगे। लोगों को ये जिंगल बहुत पसंद आया, जैसे किसी ठंडी बोतल का जिंगल बहुत पसंद आता है इसी तरीके से ये जिंगल उनको बहुत पसंद आया कि वाकयी अच्छे दिन आ जाएंगे। तो सरकार ने वाकई बहुत अच्छे दिन लाने शुरू कर दिए। इतने अच्छे दिन लाने शुरू कर दिए कि आते ही 1जून,2016 को सबसे पहले 100 प्रसैंट एफडीआई कर दिया की बाहर का व्यापारी आके 100 प्रसैंट धंधा यहां पर बैठकर कर सकता है उसको किसी हिन्दुस्तान के व्यापारी, किसी हिन्दुस्तान के पार्टनर को बनाने की जरूरत नहीं, जिसका ये लोग अपोज कर रहे थे जब दूसरी सरकारें थी उसमें बैठकर उसका अपोज कर रहे थे, अपोजिशन में और बहुत बड़ी–बड़ी बातें करते

थे कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी, छोटे व्यापारी मर जाएंगे, फुटकर दुकानदार जो है,उनका पता नहीं क्या हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदयः जगदीप जी ये विषय लगा हुआ है 54 में। हाँ प्लीज।

श्री जगदीप सिंहः मैं आता हूं सर, मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूं, लेकिन लोगों ने उस डिब्बे को ओर खोला शायद अच्छे दिन उसके अंदर होंगे, उस डिब्बे के अंदर से एक ओर चीज निकली 8 नवम्बर, 2016 को उसमें से निकला नोटबंदी का एक खेल। नोटबंदी से ओर अच्छे दिन आ गए लोगों के, जिनके बिजनस थोड़े–बहुत चल रहे थे वो भी ठप्प हो गए, दुकानदार बेचारे फूटफूट के रोने लग गए, जो फुटकर दुकानदार थे और कोन्ट्रैक्टर जिनकी लेबर थी उनके पास लेबर को देने के लिए पैसा नहीं था 500 का नोट पुराना लेने के लिए तैयार नहीं था, इंटो के भट्ठे चला–चला के लोग जो अपनी रोजी–रोटी चलाते थे उनकी इंटो के भट्ठे बंद हो गए। आज पूरे देश भर में मुझे लगा शायद दिल्ली में ये दिक्कत हुई है, लेकिन देश के कुछ ओर प्रांतो में भी जाकर जब बात की गई कि नोट बंदी का असर क्या हुआ है तो वहां पर भी यही जवाब मिला कि हमारे तो भूखे मरने की नौबत आ गई है। सर ये सरकार अपनी कैंपेन चलाती रही उस अच्छे दिन को लेके, एक ओर डब्बे में से एक ओर छोटा सा डब्बा निकला जीएसटी का। अपोजिशन में बैठे थे कहते थे जीएसटी ये कर देगा, वो कर देगा, वो कर देगा, वो कर देगा आज जीएसटी लागू होने के बाद मैं अपनी बात को छोटा करने की कोशिश कर रहा हूं सर कि जीएसटी का सिस्टम कम्प्युटर इन्फ्रास्ट्रक्चर के बगैर नहीं चल सकता। आज रिफंड लेने के लिए मुझे अगर मेरा अंडमान निकोबार से समान आता है तो मुझे वहां से मेल चाहिए होगी कि वो टैक्स वहां जमा हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन आज ये अखबार बता रही है कि जीएसटी का सिस्टम

कंप्युटर इन्फ्रास्ट्रक्चर के बगैर नहीं चल सकता। आज रिफंड लेने के लिए मुझे अगर मेरा अण्डमान निकोबार से सामान आता है तो मुझे वहां से मेल चाहिए होगी कि वो टैक्स वहां जमा हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन आज की अखबार बता रही है कि जीएसटी की पेमेंट जो है वो मैन्युवली करनी शुरू कर दी है। ये टोटली फ्लाप शो हुआ है सरकार का ये अच्छे दिन का खाली डब्बा जो लोगों को थमाना चाह रहे थे वो बिल्कुल खाली डब्बे की तरह निकला। अब इनका केंपेन जब समाप्त होने पे आया है इनको लग रहा है 2019 में ये इनका भी यही हाल होगा जो इनका नोटबंदी में व्यापारियों का हुआ था। आज इन्होंने एक और अच्छी ड्राइव शुरू की है जिसका नाम है सीलिंग। एक थ्रेफ्ट ड्राइव केंपेन शुरू कर दी है कि दिल्ली वालों डर जाओ नहीं तो तुम्हारी दुकानों पे सील लगा देंगे। ये सिर्फ बेकार की बातें हो रही है हर तरीके से सरकार जो है ये ड्रामेबाजी कर रही है। कल विजेन्द्र गुप्ता जी हमारे कल कह रहे थे कि 315 रोड़ो को तो वो करो–315 रोड़ो को तो वो करो ठीक है जी। लेकिन जो 2200 रोड़ जो की हुई है उन पर आज सीलिंग हो रही है विजेन्द्र गुप्ता जी जाकर देखिए मेरे यहां हरिनगर में आकर देखिए। जो रोड़ नोटिफाई की हुई है उन पर भी वो हुई है और भाजपा इतनी देर से बैठी हुई जो है 10 साल से कनवर्जन चार्जिज वसूल नहीं कर पाई क्यों? क्योंकि वो जो अफसर थे वो जाकर अपनी जेबें भरके आ जाते थे और जो पहले साल डर से साढ़े पांच सौ करोड़ रूपया पहले साल इकट्ठा हुआ था उसके बाद धीरे–धीरे साढ़े चार सौ करोड़ रूपया आज एक हजार करोड़ रूपये का किसी एकाउंट में हेड जाकर देख ले। इनके पास वो बही–खाते नहीं है कि वो एक हजार करोड़ रूपये कहां चला गया। वो एक हजार करोड़ रूपये का उन्होंने कनवर्जन चार्जिज के नाम से लिया था, वो पैसा जो इन्होंने पार्किंग के नाम लिया था कितनी पार्किंग बना दी आज। ये एमसीडी में भी रहे हैं कांसलर मुझे

यहां पर बता दे कितनी पार्किंग जिन लोगों ने बना दी ये कनवर्जन चार्जिज ये कहकर लिया गया था कि हम इन्फ्रास्ट्रक्चर इंप्रुव करेंगे ये कर्मशियल मार्किट्स बनायेंगे। वो कहां पर खर्चा किया गया मुझे ये बताया जाए। ये सिर्फ आपका फ्रंट ड्राइव केंपेन है भाजपा का और आप ये सोचिए कि दिल्ली की जनता खामोश बैठी है वो अन्दर ही अन्दर वो ज्वालामुखी उनके जलती जा रही है। 2019 के चुनाव में इतने जोर से फटेगी कि देखना भाजपा का नामोनिशान मिट जाएगा और आखिर में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि सर इस पर हम लोग इनको हल्के ना ले क्योंकि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पर विश्वास किया। चाहे हमें तीनों कमिश्नर को बुलाना पड़े, चाहे यूडी मिनिस्टर से बात करनी पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट में मूव करना पड़े। हमें दिल्ली की जनता को सीलिंग से निजात दिलवा के देनी पड़ेगी क्योंकि उन लोगों ने हमें विश्वास किया है उसके लिए चाहे हमारी जान चली जाए, हमें जेल जाना पड़े हम ये करके छोड़ेंगे। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः संजीव झा जी।

श्री संजीव झाः बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे इस गंभीर विषय पर अपनी बात रखने का मौका दिया। जैसा बाकी हमारे साथियों ने बताया है कि आज दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ा अपराध कोई है तो दिल्ली में व्यापार करना है। कुछ आंकड़े अभी जगदीप भाई ने दिया मैं भी ये समझने की कोशिश कर रहा था कि पहले नोटबंदी से व्यापारी परेशान हुआ, नोटबंदी के बाद फिर जीएसटी से परेशान हुआ और उससे जो बचा सीलिंग की मार में मर गया। जबकि ये माना जाता है पूरे देश में कि व्यापारी वर्ग जो है वो भाजपा के वोटर हुआ करते थे तो अगर ये अपने वोट बैंक का नुकसान क्यों कर रहे हैं। जब मैं इसके तह में गया मुझे लगता है सदन को ये जानना चाहिए और सदन के जरिए व्यापारी

वर्ग को भी पूरे देश को जानना चाहिए कि अध्यक्ष महोदय नोटबंदी में व्यापारी मारा गया, जीएसटी में मारा गया जो बचा–खुचा रहा वो सीलिंग में मारा गया। अब हालांकि चर्चा में लगा हुआ है विषय जब ये सारे व्यापारी मारे गए प्रधानमंत्री जी सारा काम बड़ी योजना से करते हैं तो एफडीआई आ गया। इसका मतलब है कि सीधा–सीधा था कि पहले सारे व्यापारी को मार दो फिर एफडीआई लाओ अदानी, अंबानी है दो–चार और बड़े–बड़े ऐसे नाम सुनने को मिल जाएगा आपको और मैं ये साबित करूंगा आपको जब ये नोटबंदी हुआ था तो नोटबंदी के समय में भई ये बड़े तौर पे कहा गया कि नोटबंदी फिर उपाय क्या–क्या करना चाहिए तो कहा गया कि पेटीएम करो–पेटीएम करो तो कहा पेटीएम कौन है भई। तो पता चला कि पेटीएम कोई 10–20 करोड़ का व्यापारी है जो अचानक नोटबंदी में एक हजार करोड़ का, हजारों करोड़ का हो गया। तो व्यापारी परेशान जनता परेशान फायदा क्योंकि एक आदमी को अचानक रातोंरात वो हजारों करोड़ का मालिक बन गया। उसके बाद मैंने ये देखा दिल्ली में अध्यक्ष महोदय एक अजीबोगरीब स्थिति हुई जब मेट्रो का किराया बढ़ रहा था दिल्ली में हमारी सरकार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो का किराया नहीं बढ़ना चाहिए। दिल्ली के 7 सांसद प्रधानमंत्री जी लेकिन एक भी ना तो बीजेपी किसी कांउसलर, ना सांसद, ना कोई मंत्री ये बोला कि किराया नहीं बढ़ना चाहिए। मैंने सोचा कि आखिर भई सात जिस तरह से हम लोग 67 लोग जीतकर आए थे आपके सात सांसद भाजपा से जीतकर गए थे सांसद क्यों नहीं बोल रहे हैं। भई दिल्ली की जनता ने उनको बड़ी मेजोरिटी से जिताकर भेजा था। क्या उनको जनता का डर नहीं है। फिर लगा कि इसमें कहीं ना कहीं जब मैंने बहुत जांच–पड़ताल करने की कोशिश करी तो एक व्यापारी ने बताया मुझे कि ज्यों ही मेट्रो का किराया बढ़ा अचानक सड़क पर ओला उबेर बढ़ने लगा और ओला उबेर की कमाई दिन दुगुणा रात चौगुणा बढ़

गई। तो मेरा ये कहना है कि कोशिश पूरी की जा रही है अदानी, अंबानी जैसे लोगों को खड़ा किए जाने की अपना व्यापार बढ़ाने की। बात रही कनवर्जन की अध्यक्ष महोदय जब कनवर्जन की बात हम कर रहे हैं हालांकि कल सौरभ भाई ने और बाकी सारे साथियों ने बताया कि कनवर्जन चार्ज लिया क्यों गया था कि भई जहां आपने जिन प्रापर्टिज को कर्मशियल आपने किया तो उसमें जो चाहे पार्किंग की बातें हो या और जो प्रेशर बढ़ा उसके लिए आपने चार्ज लिया। 2007 के बाद 2012 में अचानक इसको नवासी हजार कर दिया गया हालांकि अभी सोमनाथ भाई नहीं है हम उनको धन्यवाद देता हूं उन्होंने डीडीए में लड़–लड़कर 22000 करवाया। लेकिन 22000 ही क्यों भई कल आंकड़ा दिया बाकी सारे साथियों ने 6000 रूपया जब कनवर्जन चार्ज था तो भी एक हजार करोड़ रूपया वसूला गया। इस एक हजार करोड़ का खर्चा कहां गया कोई चीज बढ़ाते तब है जब मान लीजिए आपने जो सुविधा के लिए कहा उस सुविधा में पैसा कम हो रहा है तो आप पैसे बढ़ा दीजिए। लेकिन एक हजार करोड़ का हिसाब–किताब नहीं है 6000 से बढ़ाकर 89000 कर दिया फिर 22000 हुआ तो मुझे तो लगता है कि 22000 तो होना ही नहीं चाहिए। मुझे याद है कि जब एमसीडी का चुनाव हो रहा था तो मनोज तिवारी जी बड़े जोर–जोर से कह रहे थे कि कनवर्जन चार्ज बढ़ाया नहीं जाएगा। नार्थ दिल्ली के कांसलरों ने एक रेजुलेशन पास किया था उन्होंने कहा था कि भई किसी भी स्थिति में कनवर्जन चार्ज बढ़ाया नहीं जाएगा तो मेरा ये कहना है कि आज कौन–सी आफत आ गई। आज हमारे ओमप्रकाश जी कह रहे थे कि समाधान क्या है भई आसान सा समाधान है कि आप कनवर्जन चार्ज माफ कर दो अपने आप सीलिंग बन्द हो जाएगा। सीलिंग क्यों किया जा रहा है दो कारण से किया जा रहा है पहला भई आप कह रहे हैं कि कनवर्जन चार्ज जिन्होंने नहीं जमा किया है उसका सीलिंग होगा। दूसरा था कि आपने अवैध कंस्ट्रक्शन कर लिया तो बढ़ाया

जाएगा। देखिए कई बार उच्च न्यायालय ने भी कहा है उच्चतम न्यायालय ने भी कहा कि भई मान लो व्यापारी ने गलती की, गलती हुई कैसे। अधिकारी क्या कर रहे थे उस समय में तो अगर व्यापारी पे कार्रवाई हो रहा है तो अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अरे जो अवैध कंस्ट्रक्शन हुआ तब अधिकारी सो रहे थे क्या। तो मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए किसी ने अपने कंस्ट्रक्शन सर बढ़ाया भी इसमें अधिकारी की कहीं ना कहीं मिलीभगत थी या अधिकारी कहीं ना कहीं कोई लेन–देन थी तो मेरा ये कहना है कि व्यापारी पर कार्रवाई हो तो अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मेरा ये कहना है अध्यक्ष महोदय कि मैं देख रहा था जब चुनाव केंपेन एमसीडी का चल रहा था तो नई उर्जा नए युवा नए–नए लोगों को लेकर आए। मैंने एक कांउसलर से एक दिन पूछा ऐसे ही हमारे यहां जब मकान बनता है तो बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं पैसे लेने के लिए पहुंच जाते हैं। मैंने उनको पूछा मैंने बोला कि भाई तुम लोगों को डर नहीं लगता अगली बार चुनाव लड़ोगे चुनाव जितोगे या नहीं जितोगे। ऐसे तुम वसूली करते हो अगली बार चुनाव जीत नहीं पाओगे उसने कहा अरे साहब अगली बार टिकट नहीं मिलेगा मुझे चूंकि हर बार नए लोगों को दिया जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि ऑर्गनाइज्ड क्राइम में ऑलरेडी ट्रेण्ड कर दिया गया इन लोगों को कि किस तरह से वसूला जाए। देखिए रोज एक हमारे आज हमारे मार्किट में सीलिंग की जा रही है सुनने में आया है। पिछले एक महीने से चर्चा चल रहा था कि भई सीलिंग किया जाएगा–सीलिंग किया जाएगा। आज सीलिंग करने वाले दो–चार दुकानों पर सीलिंग करके गए। अब उसमें एक बहुत बड़ा वसूल है कि धंधा बन जाता है कि तुम पैसा दे दो तुम्हारा सीलिंग नहीं होगा। तो मेरा ये कहना है अध्यक्ष महोदय इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और जानबूकर किया जा रहा है चाहे केन्द्र सरकार हो और चाहे। 2009 में एमसीडी में स्टेंडिंग काउंसिल में चेयरमैन थे विजेन्द्र

गुप्ता जी इन्होंने कहा था उस समय में की भई कन्वर्जन चार्ज बहुत ज्यादा है और केन्द्र सरकार को चाहिए केन्द्र सरकार को नहीं करना तो कम करना चाहिए तो आज वो कैसे बढ़ गया। एमसीडी में भी आप हैं और केन्द्र में भी आप हैं। आप किसको मूर्ख बना रहे हैं अरे 351 सड़कों की बात कर रहे हैं। आप पहली बात की 351 सड़कों के जैसा अभी जगदीप जी ने बताया। उसके सिवाय जो बाकी मिस लैंड प्रोपर्टीज में जहांय कमर्शल एक्टिविटी हो रही है सीलिंग तो वहां भी हो रही है और रही 351 की हमारे मंत्री जी विस्तार से बताएंगे। मुझे ताज्जुब होता है कि आप अपोजिशन के लीडर हैं क्या अपने मेयर से बात नहीं करते। मुझे अच्छा लगाा कि ओम प्रकाश जी ने ये कहा कि 2015, 16, 17 में लगातार कोर्सपोंडेंस मंत्रालय में होती रही। मंत्रालय ने क्या कहा, कहा कि भई मास्टर प्लान के नॉर्मस के हिसाब से आप अपना प्लान भेजिए उसके बाद हो जाएगा। अभी भी मेरे ख्याल से मंत्री जी विस्तार से बताएंगे उसके बारे में की कुछ दिन पहले तीनों मेयर को बुलाया गया था। तीनों मेयर को ये कहा गया था कि भई आप जो ये भेज रहे हो। जब आपको जानकारी है कि मास्टर प्लान के नॉर्मस के हिसाब से क्यों ऐसा भेज रहे हो। उन्होंने कहा 22 तारीख या कुछ समय लिया है कि 22 तारीख तक का समय लिया गया है हम आपको प्रोपर भेज देंगे जब नोटिफाइ करेंगे। ऐसा नहीं है तो इनको जानकारी नहीं है या फिर ये बातचीत नहीं करते हैं और ये बातचीत करते हैं तो जानबूझकर व्यापारी को भी और दिल्ली की जनता को गुमराह कराना चाह रहे हैं। तो मेरा ये कहना है जो ओम प्रकाश जी कह रहे थे। विजेन्द्र गुप्ता जी एमसीडी में रहे हैं आपसे ये निवेदन है कि देखिए व्यापारियों को गुमराह करना छोड़ दीजिए। हांलाकि, व्यापारी बहुत अच्छे से जानता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं मैं कुछ व्यापारी का कमेंट देख रहा था। कल हमारे साथी मदल लाल जी ने बताया था डिफेंस कालोनी के बारे में। डिफेंस कालोनी के

एक मार्किट एसोसिएशन के मैम्बर जितेन्द्र गुप्ता जी उन्होंने कहा कि ***our market is commercial, does not fall under mix land use. There is no reason for paying conversion charges*** जब कमर्शल ऑलरेडी है तो उनको वहां क्यों सील किया जा रहा है। मैं एक और देखा जगदीश गुप्ता के बारे में देख रहा था वो भी डिफेंस कालोनी एसोसिएशन के मैम्बर हैं वो कह रहे थे कि ***we have filed the petition against the illegal ceiling of the market. We are not obliged to pay any amount as we have already paid while buying the shop.*** जब आपने दुकान खरीदा उसी टाइम उन्होंने ऑलरेडी पे कर दिया तो अब उनका बाद दुकान क्यों सील हो रहा है। इसी तरह तमाम हमने जितने भी व्यापारी है एक मनमोहन सिंह जनरल सैक्रेटरी हैं हॉजखास मार्किट के उन्होंने कहा कि ***the issue of paying twenty thousand rupees per square meter was going for almost two years but DDA then notify, we are ready to pay at this rate alongwith affidavit but should be given atleast thirty days.*** बिना किसी सूचना है, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी प्रायर इंफॉर्मेशन के आप दुकान सील कर रहे हैं और फिर गुमराह कर रहे हैं ये लोग। अभी मैं स्टेंडिंग कमेटी की चेयरमैन और मेयर ये कह रहे हैं कि हम 48 घण्टे का समय दे रहे हैं और जब मॉनिटरिंग कमेटी से पूछा गया उन्होंने कहा नहीं नहीं अब तो टाइम देनी की कोई बात ही नहीं है। तो भई ये तो बता दो कि सच्चाई क्या है। तो मेरा ये कहना है अध्यक्ष महोदय की बीजेपी चाहे विधान सभा में बैठे ये मतलब तीनों चारों सदस्य, एमसीडी के लोग और केन्द्र सरकार सब दिल्ली की जनता को और व्यापारियों को गुमराह कर रहे हैं। मैं जैसा सौरभ भाई ने कल प्रपोजल अपना रखा था। मैं उस प्रपोजल के साथ हूं मुझे लगता है हमें समाधान ढूंढना चाहिए। हांलाकि एक समाधान तो ये हो सकता है कि अगर विजेन्द्र गुप्ता जी हमारे चार सदस्य जो बीजेपी के हैं अगर ये

चाहते हैं कि वास्तव में व्यापारी का कोई नुकसान न हो या इनका कोई किसी तरह का अपना इंट्रेस्ट न हो तो हमारे साथ चले। हम यूडी मिनिस्टर से मिलेंगे, हम डीडीए के वाइस चेयरमैन से मिलेंगे, कन्वर्जन चार्ज हम माफ कराएंगे या और जो भी समाधान हो सकता है वो कह करेंगे। केवल यहां भाषण देने से काम नहीं चलेगा। तो मेरा अध्यक्ष महोदय पहले निवेदन तो ये है कि आप जैसे हमारे बाकी साथियों ने बताया कि बिल्कुल तीनों कमिश्नरों को बुलाया जाए और हिसाब किताब के साथ की कन्वर्जन चार्जिज जो एक हजार करोड़ रुपये थे। उस एक हजार करोड़ रुपये का खर्च कहां है उसका हिसाब किताब क्या है और दूसरा की इस तरह की कार्रवाई को रोकने के और उपाय क्या हो सकते हैं। चूंकि हम इस तरह हाथ पर हाथ धरे रहे बैठे नहीं सकते। दिल्ली की जनता ने हम सबको एक बड़ी मैजोरिटी के साथ विधान सभा में भेजा है तो हम सब लोग व्यापारी चूंकि आज मान लीजिए कि ये व्यापारी का नुकसान नहीं हो रहा है ये एक डेलीगेटिड चैन है। आज नोट बंदी जब हुई व्यापार बंद हुआ तो हजारों लोग बेरोजगार हुए यानी नौकरी नहीं है। इसी तरह से जीएसटी में जो दुकानें जो ट्रांसपोर्टर के नुकसान हुए या बाकि जो व्यापार, व्यापारी को नुकसान हुआ उससे बेरोजगारी बढ़ी। आज अगर सीलिंग हो रही है तो उससे भी बेरोजगारी बढ़ रही है तो भला आप चाहते क्या हैं बड़ी बड़ी बात आपने किया भई 5 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। अरे तुम हजारों करोड़ का रोजगार जनता का खत्म कर दिया, व्यापारी खत्म कर दिया, लोग बेरोजगार हो गए हैं। आप हत्या कर रह हैं तो मेरा ये कहना जनता 2019 में उनको जवाब देगी। लेकिन आज दिल्ली के व्यापारी, दिल्ली के व्यापारियों के हित में जो भी मजबूत कदम हम सबको लेना पड़े, हम सब लें। बिल्कुल कमिश्नर को बुलाया जाए उनसे हिसाब किताब लिया जाए और साथ ही हमारे साथियों से निवेदन है मुझे पता है भाषण देंगे। लेकिन भाषण देने से काम नहीं चलेगा। आज

समाधान बताइएगा और आप जो भी समाधान आप बताइएगा उस समाधान के साथ हम लोग आप सबसे कदम से कदम मिला के खड़े रहेंगे और दिल्ली के व्यापारी को लुटने से बर्बाद होने से बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री विजेन्द्र गुप्ता जी। भई अजय दत्त जी अब नहीं प्लीज। नहीं मैं बैठ जाइए, नहीं मैं कोई परमिशन नहीं दे रहा आप बैठ जाइए। विजेन्द्र गुप्ता जी। मैं किसी बात की कोई परमिशन नहीं दे रहा। अजय जी बैठ जाइए प्लीज बैठिए। मैं अब कोई इजाजत नहीं दे रहा प्लीज बैठिए। विजेन्द्र जी चालू करें। अजय दत्त जी ये सारा माहौल खराब कर रहे हैं बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है अब बैठ जाइए। अब बैठ जाइए प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बैठ जाइए प्लीज, प्लीज बैठ जाइए आप। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं बैठ जाइए। मैं कुछ अब नहीं आप बैठिए अब। बैठ जाइए नीचे। चलिए विजेन्द्र गुप्ता जी। अजय दत्त जी मैं कुछ भी अलाउ नहीं कर रहा आप समझ नहीं रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी दिल्ली के अन्दर लोग सीलिंग से परेशान हैं। दिल्ली में सीलिंग का भय है, लोग घबराए हुए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 3 जनवरी, 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी को सीलिंग के अधिकार से वंचित कर दिया था और जनवरी, 2012 के बाद दिसम्बर, 2012 तक दिसम्बर, 2017 तक दिल्ली में इस प्रकार की कोई सीलिंग नहीं हुई। वास्तविक्ता ये है कि सदन में जितनी चर्चा हो रही है मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि राजनीति से ऊपर उठकर बात करें जिससे लोगों की इस जो तलवार उनके ऊपर लटकी हुई है उससे उनको बचाया जा सके। यहां जितनी चर्चा अभी तक हुई है उसमें किसी एक भी सदस्य ने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि हम मॉनिटरिंग कमेटी के खिलाफ हैं। मॉनिटरिंग कमेटी अमानवीय तरीके से लोगों को खुद जा जा कर सील करवा

रही है। मॉनिटरिंग कमेटी की इस सदन के अन्दर किसी भी प्रकार की कोई भर्त्सना करने की किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। इसका मतलब साफ है कि हम मुद्दे पर नहीं आना चाहते। करिए चर्चा सुप्रीम कोर्ट के रोल की कि क्या सर्वोच्च न्यायालय जो कर रहा है वो मानवीय मूल्यों को, मानवीय आधारों का ध्यान कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को जिस तरह से ले रहा है वहां क्या आपने इस सदन में चर्चा की कि गरीबों की रोटी छिन रही है और रोजगार पहले है, भूखे को रोटी पहले है। शहर की सुन्दरता एक विषय हो सकता है। लेकिन गरीब को काम मिले ये हमारी प्रॉयरिटी पहले है। क्या किसी ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ कहने की हिम्मत की नहीं की क्योंकि मुझे लगता है कि अंग्रेजों की नीति फूट डालो और शासन करों और आम आदमी पार्टी की नीति है कि झूठ बोलो और शासन करों। गुमराह करने का एक जरिया अगर सदन के इस पटल को बनाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से जब हमने कल 351 सड़कों की बात की। सरकार के दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। सरकार को एक पैमाने से सारी बातों को तोलना चाहिए अभी मुझे मालूम है जब 351 सड़कों का जवाब आएगा तो क्या जवाब आएगा और जो सीलिंग हो रही है उस पर क्या जवाब आ रह है। 351 सड़कों का ये प्रपोजल मेरे पास है इसमें सभी सड़कों की सूचीबद्ध इनको दिया गया है इसके ऊपर ये एक हाउस का रेजूलेशन लगा हुआ है जो कमिश्नर ने प्रस्तुत किया था इस लिस्ट के साथ अथोंटिकेटिड है ये, सर्टिफाइड है ये, ये लिस्ट। ये पूरी तरह से अधिकृत लिस्ट है और मास्टर प्लान 2021 आया था 8 फरवरी, 2007 को। 2183 सड़कें और 355 सड़कें जो इससे पहले नोटिफाइ हुई थी वो हुई थी मास्टर प्लान के आने से पहले। इसी तरह कमिश्नर ने सर्वे कराया था। उस सर्वे के आधार पर स्टेंडिंग कमेटी ने उसको अप्रूवल दी थी। कमिश्नर प्रस्ताव लेकर आए थे। स्टेंडिंग कमेटी

ने अप्रूवल दी थी, हाउस ने उस पर मोहर लगाई थी। दिल्ली सरकार ने उसको नोटिफाइ कर दिया था वो सड़के नोटिफिकेशन के बाद वो कमर्शल और मिक्स लैंड यूज में वो यूज इस्तेमाल होने लगी। उनके ऊपर से सीलिंग की तलवार हट गई। कनवर्जन चार्जेज जमा कराने का विषय रहा था। कनवर्जन चार्जेज जमा होना एक विषय है इसके अलावा उन सड़को पर किसी प्रकार की। लेकिन ये 351 सड़कें क्योंकि जब मास्टर प्लान आया था तो मैं पढ़कर बता रहा हूं दो लाईने। एमपीडी 2021 ये शर्त निर्धारित करती है यानी की एमपीडी 2021 ने जो कानून बताया। जो रास्ता बताया उसके अनुसार ये प्रिएम्बल बनाया गया। इसमें लिखा गया एमपीडी 2021 ये शर्त निर्धारित करती है कि इन विनियमों के अन्तर्गत स्ट्रीट की अधिसूचना करने से पहले स्थानीय निकायों से अधिसूचना प्रभावी होने के यथोचित समय के भीतर और विधिवत शिथिलतापूर्वक तथा 90 दिन के बाद नहीं यानी की विदिन 90 डेज फ्रम दि डेट ऑफ दि कमेन्समेन्ट ऑफ दि मास्टर प्लान डेटेड 1 फेब्रूवरी, 2007। सभी स्ट्रीट्स का सर्वेक्षण यदि पहले नहीं किया गया है, निष्पादित करना अपेक्षित होगा। यानी 90 दिन के अन्दर वो तमाम सड़कें जो प्रावधान मास्टर प्लान में दिये गये हैं उनके अनुसार वो उसमें कवर होती है। तो वो पारित की जा सकती है। कमिश्नर 90 दिन के अनुसार ये प्रपोजल लेकरके आये फिर लिखा गया अध्यान 15 के अन्तर्गत मास्टर प्लान 2021 में जो आया। मिक्स यूज विनियमों के सम्बन्ध में अध्यान 15 के अन्तर्गत इस पालिसी में स्ट्रीट्स की अधिसूचना के लिए प्रक्रिया और मापदण्ड निर्धारित हैं। इससे पहले भारत सरकार की अधिसूचना वगैरह–वगैरह। यानी की जो मापदण्ड निर्धारित हैं मास्टर प्लान में एक बात, दूसरा 90 दिन के अन्दर–अन्दर मास्टर प्लान आया 8 फरवरी, 2007 को और स्थाई समिति के अन्दर 7 मई, 2007 यानी कि तीन महीने 90 दिन से ठीक एक दिन पहले दो किश्तों में 4 मई को 307 सड़कें और 7 फरवरी को 44

सड़कों ये दिल्ली सरकार के पास पारित करके भेजा गया। जून के अन्दर हाउस की मुहर लगाकर। अब सवाल ये आता है कि जो इस सरकार के अधिकार क्षेत्र में है वो काम सरकार नहीं कर रही है। सरकार नोटिफिकेशन के लिए प्रस्ताव तैयार करके अभी वो कहेंगे जी वो सुप्रीम कोर्ट का मामला है जी। सुप्रीम कोर्ट तो अभी कहां से बीच में आ गया। सुप्रीम कोर्ट तो बाद में आयेगा तो समझ में आता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहले बीच में कहां से आ गया। सरकार अपनी इच्छाशक्ति तो दिखाये की हम इन 351 सड़कों को नोटिफाई करने जा रहे हैं। ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। हम इससे, इस पर प्रस्ताव तैयार कर रहे है लेकिन सरकार तैयार नहीं कर रही है। नगर निगम के साथ शटल कॉक बना रही है। नगर निगम की वो मेरे पास तमाम चिट्ठियां, समय की सीमायें लेकिन मेरे पास एक–एक चिट्ठी है वो। एक–एक चिट्ठी है। मैं इसमें पढ़कर बता सकता हूं कि इसमें बार–बार नगर निगम की तरफ से लगातार रिक्वेस्ट की जा रही है वहां के महापौर सुभाष आर्या थे वो बार–बार डेलीगेशन लेके गये सरकार के पास।

अध्यक्ष महोदयः जरा इन लेटरों की डेट भी बोलते जाएं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः लेटर्स की?

अध्यक्ष महोदयः हां, डेट बोलतें जाएं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हां बिल्कुल–बिल्कुल। धन्यवाद आपने बोला। देखिए एक प्रस्ताव है 11 मई, 2017 का।

अध्यक्ष महोदयः चलिए, ठीक है, ठीक है बस डेट बोल दीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः बिल्कुल, एक 8.12.2016 का। जिसमे कहा गया कि उन सड़कों को नोटिफाई किया जाए।

अध्यक्ष महोदयः और कोई लेटर इसके अलावा

श्री विजेन्द्र गुप्ताः एक पत्र 25 अप्रैल को मीटिंग रखीं गयी। सेक्रेटरी यू0डी0 के साथ।

अध्यक्ष महोदयः 25 अप्रैल का।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः उसके बाद इसी विषय पर इसको।

अध्यक्ष महोदयः 25 अप्रैल डेट बोलिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः 2016, पोस्टपोन्ड किया गया फिर 22 फरवरी, 2016 को ये साउथ दिल्ली ने ये चिट्ठी लिखी। ये मैं पढ़ देता हूं उसकी लाईनें। ये सब मंत्री जी के पास चिट्ठियां हैं।

अध्यक्ष महोदयः नहीं कोई बात नहीं बस डेट।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं पढ़ देता हूं अच्छा है वो भी नोट करें तारीख और बतायें।

अध्यक्ष महोदयः पढ़ने में समय ज्यादा लगेगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः और बतायें सिलसिलेवार की ये लगातार जो सरकार से ये जो कहा जा रहा है। 13 मई, 2016 ये भी लिखिए आप।

अध्यक्ष महोदयः और कोई लेटर।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः फिर 10 मार्च, 2016 ये तमाम चिट्ठियां। मैं इसमें कुछ इनके कनटेन्ट्स लगभग एक जैसे हैं। इसमें लिखा गया है। लास्ट लाईन पढ़ देता हूं। ***in view of the above*** यानी की दिल्ली गवर्नमेंन्ट से एम0सी0डी0 रिक्वेस्ट कर रही हैः ***you are requested to kindly take up the***

issue early notification three fifty one roads in question. ये 22 फरवरी, 2016 का एक लेटर की लाईन पढ़ रहा हूं। हर लेटर में ऐसा ही है। ये प्रस्ताव है सदन का। 11 मई का पढ़ देता हूं।

अध्यक्ष महोदयः 11 मई, ईयर बोलिए, ईयर।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ईयर, 11 मई, 2017।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः इसमें लिखा गया है चूंकि 351 सड़कों को नोटिफाईड करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा निर्णय बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है फिर भी इन सड़कों को नोटिफाई नहीं किया गया है। सरकार के दोहरे मापदंड क्यों है। आपने साकारात्मक दृष्टिकोण से इन सड़कों को हजारों दुकानदारों को जो ये सदन में जो लोग बैठे हैं उनके क्षेत्र के हैं जहां सीलिंग हो रही है या होगी। उसको बचाने के लिए नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाला। क्यों प्रयास नहीं किये। हम ये जानना चाहते हैं। अगर आप प्रयास करते लेकिन आप तो राजनीति खेल रहे हैं। वो चिड़ी–छक्का खेल रहे हैं आप। फाईल ले जाओं। कल आना। इस पर ये नोट लगाके लाओ। आप अफसर हो गये। आप सरकार है। आप अफसरों की तरह काम क्यों कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, मैं अपनी जानकारी के लिए एक सेकेण्ड। मैं अपनी जानकारी के लिए क्योंकि विषय बहुत गम्भीर है। हमको सालूशन निकालना है। क्या 2017, 2007 नगर निगम ने जब ये पहली बार लिया। क्या उसके बाद से 2016 तक कोई पत्र लिखा दिल्ली सरकार को।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः लगातार इसमें और भी हैं।

अध्यक्ष महोदयः नहीं–नहीं, कोई डेट है तो मुझे बता दीजिए। वो नौ साल क्या नगर निगम सोता रहा।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः 2012 के भी हैं, 2013 के भी। आपके 49 दिन की सरकार के समय के भी हैं।

अध्यक्ष महोदयः वो मुझे डेट बता दें न। अभी इसकी पूरी जांच करेंगे। पूरा बताईए आप।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः पूरा मैं आपको बनाके आपको 20–25 पेज में दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदयः चलिए। ठीक है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अब आगे आईए। तीन साल हो गये सत्ता में आये। दिल्ली की 1656 कालोनियां, आप एक कालोनी। आप बाउन्ड्री वॉल तक डिसाईड नहीं कर पाये। आप बाउन्ड्रीज तक डिसाईड नहीं कर पा रहे हैं। आप कालोनीज को आप कहते हैं हम नियमित करेंगे। कहके सरकार में आ गये। आप नियमित नहीं कर रहे हैं। अगर आपने कालोनी नियमित की होती तो आज इन अनाधिकश्त कालोनियों का जो अनाधिकृत तो मैं नहीं कहूंगा मैं। गरीब लोगों का ये एक तरह का इनके घरौंदें हैं गरीबों के। उनको ये तलवार नहीं लटकती। लेकिन आपने कोई कदम नहीं उठाया। न रोड्स को। जो आपके अधिकार में था। अभी मामला उठा। एल0ए0सीज0 का रेजिडेन्सियल कम कामर्सियल। कामर्सियल कम रेजिडेन्सियल का।

श्री सुखबीर सिंह दलालः अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदयः भाई ऐसे नहीं। प्लीज बैठिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः कामर्सियल कम रेजीडेन्सियल का।

अध्यक्ष महोदयः ये विषय की गम्भीरता को बनाके रखिए। मंत्री जी जवाब देंगे न अब।जो कुछ आपको बताना है बता दीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः प्रश्न क्या है की कल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए शिकायत की गयी सुप्रीम कोर्ट में मानिटरिंग कमेटी के द्वारा की जनाब मानिटरिंग कमेटी ने कहा, जनाब ये जो 2183 और 355 सड़कें जो नगर निगम ने, जो दिल्ली सरकार ने नोटिफाई की थी। नगर निगम ने जिनको सर्वे करके और अप्रूव किया था उनमें 140 सड़कें डि–नोटिफाई होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर मानिटरिंग कमेटी कह रही है और हम इनको बार–बार कह रहें है नगर निगम को इन्होंने डि–नोटिफाई नहीं की है। यानी की जनता के हित में कोर्ट से भी जाकरके भिड़ने का जज्बा सरकार में होना चाहिए। जो दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ यहां पर डिबेट करने से लोगों की रोजी–रोटी नहीं बचेगी। ये आप समझ लीजिए उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। हमने दिल्ली स्पेशन लॉ 2017 जब उसकी मियाद खत्म होने लगी 31 दिसम्बर को तो हम मिले केन्द्रीय मंत्री से और जाकरके हमने कहा कि सरकार ये मियाद खत्म हो जाएगी। आप वेल इन टाईम आप इस पर एक नया मोनाटोरियम जो है निकालिए और तीन साल के लिए इनको प्रोटेक्शन दीजिए। एक मिनट नहीं लगाया गया और एक मिनट में एज इन वेयरीज बेसिस पर, एज इन हवेयरइज बेसिस पर प्रोटेक्शन दे दिया गया और दिल्ली स्पेशल लाँ 2017 बहुमत से सदन में पारित हो गया दोनों सदनों में। हम दिल्ली के जो यू0डी0 मिनिस्ट हैं उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को माना। श्री हरदीप पुरी जी ने और इस बात को समझा। हम उनका आभार प्रकट करते हैं। दूसरा कनवर्जन चार्जेज के मामले में जब डिफेन्स कालोनी में सीलिंग हुई तो 89000 रूपये कांग्रेस के रिजीम में, 89000 रूपये अध्यक्ष जी पर स्कावयर मीटर कनवर्जन चार्जेज जो है वो फिक्स किये गये। हमने अथॉरिटी की मीटिंग में कहा, यह 89 हजार रुपये पर स्क्वेयर मीटर कैसे

सम्भव हो सकता है। करोड़ों रुपया एक–एक उसका कन्वर्जन का बनेगा, इसको कम किया जाए और जैसे ही इस मामले पर ध्यान केन्द्रित हुआ, केन्द्र सरकार ने, यूडी मिनिस्ट्री ने तुरंत उसको 22 हजार 500 कुछ रुपया करके, एक चौथाई करके, ज्यादातर लोगों ने स्वागत किया कि आपने हमें बचाया, 140 मार्किट है ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः 22 हजार उचित है?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः 22 समथिंग है...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः 22 हजार ज्यादा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या 22 हजार उचित है?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः दुकानदारों ने खुद प्रस्ताव दिया है। एसोसिएशन ने लिखकर ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः 6 हजार से 22 हजार यह उचित है क्या?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, एक मिनट, आप सुन लीजिए, बाकी लोग तो बोलने वाले हैं ही। लेकिन इस सदन में एक बार भी समाधान की बात नहीं हो रही, कोई मंत्री से यह पूछने के लिए तैयार नहीं है कि 351 सड़कें आप नोटिफाई क्यों नहीं कर रहे। अनधिकृत कालोनियाँ आप नियमित क्यों नहीं कर रहे।

अध्यक्ष महोदयः अभी उत्तर देंगे इसका।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मॉनिटरिंग कमेटी के खिलाफ क्यों नहीं जाकर खड़े होते। सुप्रीम कोर्ट से नाराजगी क्यों नहीं प्रकट की जा रही। मेरा यही अनुरोध

है कि राजनीति से ऊपर उठकर इस सदन में अगर काम होगा तो निश्चित रूप से लोगों के रास्ते निकलेंगे और कल अगर मंत्री जी हमारे 54 का जवाब देते, तो दिल्ली के लोग उसको एप्रिशिएट करते।

अध्यक्ष महोदयः चलिये धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः लेकिन मंत्री जी चुप बैठे रहे और फिर चले गए बिना जवाब दिए। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः संजीव जी, प्लीज। धन्यवाद, धन्यवाद। माननीय मंत्री श्री गोपाल राय जी। अलका जी, प्लीज, प्लीज। समय की सीमा का ध्यान रखिये, मंत्री जी को बोलने दीजिए। माननीय मंत्री गोपाल राय जी। अब कोई कमेंट्स नहीं प्लीज।

विकास मंत्री (श्री गोपाल राय): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने कहा कि सभी विधायकों ने अपनी–अपनी बात रखी है। माननीय विधायकों को, आम आदमी पार्टी की सरकार को न्यायालय के सामने जाना चाहिए। मॉनिटरिंग कमेटी पर सवाल उठाने चाहिए। 351 की जो फाइल है, उसे पास करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए लेकिन जो भाजपा के निर्देश पर एमसीडी द्वारा सीलिंग हो रही है उस पर नहीं बोलना चाहिए। उस पर मत बोलो और सब कुछ कर लो। कल माननीय विजेन्द्र गुप्ता जी ने ऐसे फाइल सामने उठाई थी तो मैं सोच रहा था कि यह 351 के मुद्दे को उठा रहे हैं या अपना चेहरा छुपा रहे हैं 351 के पीछे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस सीलिंग के मसले पर जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। कल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें जाने के लिए विजेन्द्र जी शुरू से ही कोशिश कर रहे थे कि आप निकालो,

निकालो, निकालो, निकालो। लेकिन लेट हो गया, आपने निकालने में देरी की। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में भी यह प्रश्न उठा है और खास तौर से बेचैन विजेन्द्र गुप्ता जी नहीं है, ओम प्रकाश जी नहीं है और वो एमसीडी के पार्षद भी नहीं है दिल में धुक–धुक सारे सांसदों की हो रही है। इस एमसीडी के बाद लोक सभा का चुनाव आ रहा है अगर यही किया सब ने मिल कर के तो जैसे दिल्ली वालों ने सात के सात मैम्बर आफ पार्लियामेंट भाजपा के बनाये थे, नोटबंदी, जीएसटी और इस सीलिंग का हिसाब–किताब सांसदों के साथ होने जा रहा है इसलिए सारे सांसद बेचैन घूम रहे हैं। सारे सांसद बेचैन घूम रहे हैं। जहाँ तक प्रश्न विजेन्द्र गुप्ता जी ने एक उठाया 351 सड़कों का। दिल्ली के लोगों की बेहतरी के लिए 351 सड़कों का नोटिफिकेशन होना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने मीटिंग की थी 22 तारीख को तीनों नगर निगम के लोगों ने जवाब देने के लिए डेट माँगी है। अगर सब कुछ ठीक–ठाक है, सारे कागज–पत्र तैयार हैं तो 22 तारीख...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, अब यह उचित नहीं है।

विकास मंत्री (श्री गोपाल राय): 22 तारीख की डेट क्यों माँगी गई है

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, ऐसे उचित नहीं है। आप नहीं चाह रहे अब सुनना। आप सुनना नहीं चाह रहे विजेन्द्र जी, प्लीज।

विकास मंत्री (श्री गोपाल राय): जिस समय 351 सड़कों की नोटिफिकेशन की फाइल दिल्ली सरकार के पास आई थी, उस समय कांग्रेस

की सरकार थी। नगर निगम में भाजपा थी। तीन साल हो गए इस सदन के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बने हुए, 351 सड़कों के बारे में कभी चिंता नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूँ विजेन्द्र गुप्ता जी से।

अध्यक्ष महोदयः अब इसमें एक दुरूस्त कर लें एक साल आई एम द गवर्नमेंट की भी सरकार रही है।

विकास मंत्री (श्री गोपाल राय): मैं पूछना चाहता हूँ विजेन्द्र गुप्ता जी से, ये जो 351 सड़कों का अपना चेहरा छुपाने के लिए आप ले रहे हो बहाना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ विजेन्द्र गुप्ता जी, ये जो 351 सड़कें हैं डिफेंस कालोनी में सीलिंग की गई, क्या डिफेंस कालोनी का मार्किट उन 351 सड़कों में आता है। खान मार्किट में सीलिंग की गई क्या 351 के अंदर आती है वो सड़क। साउथ दिल्ली में सीलिंग की गई क्या वो 351 के अंतर्गत आती है, मोती नगर में सीलिंग की गई, क्या वो 351 के अंतर्गत आती है। पूरी दिल्ली के अंदर जिन–जिन सड़कों पर दुकानों की सीलिंग हो रही है वो 351 के अंदर नहीं आती, अध्यक्ष महोदय, झूठ बोल रहे हैं भाजपा के लोग। मैं यही कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि 351 सड़कों का मसला है, मैं चैलेंज देकर कहना चाहता हूं भाजपा के लोगों से 22 तारीख को कागज पूरा करके दो, 23 तारीख को सरकार उसका नोटिफिकेशन करने को तैयार बैठी है अगर है तो करके दिखाओ। आगे जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, यह ठीक नहीं है।

विकास मंत्री (श्री गोपाल राय): अपने नगर निगम को और कमिश्नर को 22 तारीख को भेजना कागज लेकर के। 22 तारीख को ले आना।

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, देखिये, किसी को मैंने डिस्टर्ब नहीं करने दिया। अब वो बोल रहे हैं, उनको सुनिये। आप भी तो मंत्री को बोल रहे हैं उत्तर दीजिए। फिर तो माहौल ठीक नहीं रह सकता, सदन का।

विकास मंत्री (श्री गोपाल राय): इस फाइल को अपने चेहरे के सामने लगा लेंगे, तब भी चेहरा नहीं छुपने वाला। इसलिए मैं जो कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि यह जो सीलिंग का पूरा षडयंत्र चल रहा है, इस सीलिंग के षडयंत्र में दो प्रश्न उठ रहे हैं। 351 सड़कों का, आज जो सीलिंग हुई है और हो रही है, उससे कोई लेना–देना नहीं है नंबर एक। नंबर दो बात, यह बात सब के सामने आ चुकी, आरटीआई से आ चुकी, सब को पता है कि जो कन्वर्जन चार्ज आज तक लिए गए उस कन्वर्जन चार्ज का क्या हुआ। आज सब की जुबान पर बैठ रहा है, कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं, कोई मेयर बोलने को तैयार नहीं है कि एक हजार से ज्यादा जो वसूली हुई, वो घोटाला हुआ है या उस पर किस मामले में खर्च हुआ है कोई जवाब देने को तैयार नहीं। तीसरी बात, कि अगर यह बात पूरी मार्किट में बोली जा रही है कि कन्वर्जन चार्ज जमा कर दो, सीलिंग नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने कहा, केन्द्र सरकार कितनी महान है 22 हजार रुपये कर दिया कन्वर्जन चार्ज, 90 हजार से घटा करके 22 हजार कर दिया। केन्द्र सरकार कितनी महान है। मैं इस सदन के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि अगर आज समाधान की बात कोई करता है, सीलिंग रोकने की बात करता है तो सिर्फ एक रास्ता है सुप्रीम कोर्ट के, उसके बहाने सीलिंग को जायज नहीं ठहराया जा सकता। एक ही रास्ता है सीलिंग को बंद करने का, पहले कन्वर्जन चार्ज का हिसाब दो और नहीं तो जो उसने टैक्स लगाए हैं कन्वर्जन चार्ज लगा है उसको माफ किया जाए और सारे दुकानदारों को राहत दिया जाए। जब तक इसका हिसाब–किताब सामने नहीं आ जाता है और इसके माध्यम से न तो कोर्ट

उसमें हस्तक्षेप करेगी, न तो मॉनिटरिंग कमेटी को हस्तक्षेप करने की जरूरत है। आज जब तक कन्वर्जन चार्ज का हिसाब नहीं हो जाता है। सारे कन्वर्जन चार्ज को माफ किया जाए और इस सीलिंग की जो लटकती हुई तलवार है उससे दिल्ली के व्यापारियों को मुक्त कराया जाए यही समाधान का रास्ता है और मुझे लगता है ठंडे मन से अगर भाजपा के साथी भी सोचेंगे तो उनके लिए भी ये फायदेमंद है दिल्ली व्यापारियों के लिए फायदेमंद है दिल्ली के लिए फायदेमंद है। अध्यक्ष महोदय मैं ये ही निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की तरफ से ये केन्द्र सरकार को जाना चाहिए कि जिस तरह से आपने घटाकर के 22 हजार किया है उस 22 हजार को घटाकर के जीरो किया जाए। केन्द्र सरकार अपनी कमेटी बना ले और जांच कराए कि एमसीडी में जो कन्वर्जन चार्ज आया वो कहां गया अगर सही पाया जाता है तो आप फैसला करिये अगर गलत पाया जाता है जिन्होंने गलती की है उनको जेल भी जाने की जरूरत है और ये कन्वर्जन चार्ज माफ करके तुरंत सीलिंग को रोकने की जरूरत है ये ही मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री सत्येन्द्र जैन जी।

श्री सत्येन्द्र जैन (शहरी विकास मंत्री): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी नेता प्रतिपक्ष ने कुछ जानकारी दी मेरे लिए भी बड़ी जानकारी थी कि अगर ये चाहें तो इन समस्याओं से निदान दिलवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भई केन्द्र सरकार के पास गए उन्होंने तुरंत स्पेशल प्रोवीजन में कहने से तुरंत उसको ..... से हटा दिया और अनाथराइज कंस्ट्रशन पर दिक्कत खत्म हो गई। 90 हजार रुपये रेट थे वो गए और उन्होंने तुरंत 22 हजार कर दिये तो इसका मतलब अगर ये चाहें तो ये तुरंत कुछ भी करा सकते हैं, चाहें तो परन्तु सीलिंग चाहेंगे तब। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाउंगा

उन्हीं की मीटिंग की एक बात है लगता है इन्हीं के वो रहे होंगे। इनकी मीटिंग में थे कोई एक मुर्गी पकड़कर लाए वो नेता जी। मुर्गी लाकर न उसका पंख उखाड़ा दूसरा उखाड़ा उखाड़ते रहे उखाड़ते रहे सारे पंख उखाड़ लिए एक पंख नहीं बचा लहूलुहान हो गई मुर्गी तो उसके बाद एक हाथ में थोड़े से दाने रखे इन्होंने और उसके आगे डाले अब वो मुर्गी उसके पीछे पीछे थोड़े से दाने और डाले फिर पीछे पीछे थोड़े से दाने और डाले फिर पीछे वो अपना बेचारा कहते हैं पंख भूल गई मुझे लगता है वो मुर्गी जो है इनके लिए व्यापारी है। इन्होंने व्यापारियों को मुर्गी बना लिया है। कहते हैं जी एक बार एक नेता जी से पूछ लिया किसी से मैंने, मैंने कहा भई ये व्यापारी हैं सभी का विचार है। हमारा भी यह विचार था भई देखो इस पार्टी को बीजेपी पार्टी को सबसे बड़ा समर्थन दिया व्यापारियों ने। आज से नही ंहम तो जब पैदा नहीं हुए थे तब से दिया। हमारी एसोसिएशन कहते हैं हमें क्यों नहीं दिया हम तो पैदा भी नहीं हुए थे हमारी तो पार्टी बने ही अभी पांच साल हुए हैं। जिस पार्टी को खड़ा किया व्यापारियों ने 50 साल, 60 साल, 70 साल से वोट दिया है कहते हैं उसके पीछे क्यों पड़ गये। एक बार तालकटोरा स्टेडियम के अंदर व्यापारियों का एक फंग्शन था बहुत बड़ा उनके जो सबसे बड़े नेता थे उनसे मैंने पूछ लिया सेल्स के ऊपर ही मैंने सरजी ये ऐसा क्यो हो रहा है कि आपने जिस पार्टी की सरकार बनाई आपही के पीछे पड़ गये। उन्होंने कहा कि जैन साहब देखो ऐसा है जब बिल्डिंग बनती है न उसके सामने जो स्टरिंग लगाते हैं जिसे पैड कहते हैं तो बिल्डिंग बनाने के समय पर वो सबसे जरूरी होती है। सबसे प्रिय होती है कि पैड लगा दो जी। व्यापारी वो पैड है बिल्डिंग बन गई अब बिल्डिंग बनने के बाद सबसे बुरी क्या लगती है वो पैड लगती है। कहता है अब हमारी जरूरत नहीं रही उनको। कहता है अब तो हमें मिट्टी में मिलाएंगे और उसी के लिए लगे हुए हैं। एक बार किसी से

डिस्कशन हुआ बीजेपी के महानुभाव से मैंने कहा भई ये कर क्या रहे हो तुम लोग। लगभग डेढ़ दो साल पुरानी बात है जब तक नोटबंदी भी नहीं हुई थी। मैंने कहा भई तुम इन व्यापारियों के पीछे ऐसे पड़ गये क्या कारण है। वो बोले कि देखो जैन साहब ऐसा है कोई आदमी महीने का पांच लाख रुपया कमाता हो और हमारी पांच साल सरकार रहे दस लाख कमाने लगे हमारा कोई अहसान है उसके ऊपर कोई अहसान नहीं होता। कहते हैं मैंने अपनी हिम्मत से ये पैसे कमाये। मेरे अपने व्यापार से पैसे कमाये हैं। मैंने कामधंधे से पैसे कमाये। अब दूसरे तरीके से समझाता हूं उसने कहा मैंने कहा कैसे। के भई व्यापारी क्या करता है पैसे कमाने के बाद पांच सात साल में कोई मकान खरीदेगा। दस साल में कोई मकान खरीदेगा। मान लो एक मकान की कीमत पांच करोड़ रुपये है और पांच साल में वो दस करोड़ हो गई कोई अहसान नहीं हुआ। कहते हैं ये काम करो जिसकी पांच लाख रुपये महीना कमाई है न उसका सत्यानाश कर दो उसका। सारी कमाई बंद कर दो उसे लाले पड़ जाएं। पचास हजार रुपया महीना भी न कमा पाये। घर की रोटी भी न चले उसकी। मकान जो पांच करोड़ का था वो एक करोड़ पर ले आओ अगर दोबारा से वो पांच पर पहुंच गया तो कहेंगे कि अच्छे दिन आ गये अच्छे दिन आ गये। जो बेचारा पहले पांच लाख कमाता था एक लाख पर ले आओ दोबारा दो तीन पर आ जाएगा तो कहेगा कि अरे राम अच्छे दिन आ गए वाह वाह वाह। इन्होंने क्या किया सबसे पहले व्यापारियों के खिलाफ सबसे पहले करी नोटबंदी। अब नोटबंदी के अंदर सबको पता है क्या कारण था। जिस बैंक के अंदर पैसे आप जमा कराने जाते हो शाम को पहले दिन पता होता है कि कल इतने पैसे इक्ट्ठे हो गये जी। हर रोज बताते थे महीना भर तक बताते रहे अचानक क्या हुआ अरे यार ये तो पैसे बताते जा रहे हैं ये तो सारे जमा हो गये अभी तो एक महीना बाकी है। डेढ़ साल होने को हो रहा है सवा साल

होने को हो गया बाकी पैसे गिने ही नहीं गये इनसे। हुआ क्या इन बीजेपी वालों ने चार लाख करोड़ के नकली नोट जमा करा दिये। जितने पैसे थे उससे ज्यादा तो जमा करा दिये अब कह रहे हैं गिनती कर रहे हैं। कहते हैं डिमोनिटराइजेशन करी और किसी भी दिल्ली के व्यापारी से पूछ लो पहले दिन से ही इन्होंने रेट निकाल दिया था के जी 45 परसेंट दे दो 40 परसेंट दे दो हम बदल रहे हैं और सारे बीजेपी वाले बदल रहे थे और सारे के सारे ये धंधा कर रहे थे दलाली करने में लगे हुए थे। जो जीएसटी का विरोध करते थे विरोध करते करते सरकार बनाई और बनते ही जीएसटी लागू कर दिया। जीएसटी को लागू कर दिया बिना किसी तैयारी क`अब उनसे पूछो भई तैयारी तो कर लेते, कहते हैं तैयारी क्या होती है। के देखो हवाई जहाज उड़ाना पड़ता है तो पहले रनवे बनाते हैं रनवे के ऊपर पूरी सरफेसिंग करते हैं पांच पांच किलोमीटर लंबे रनवे होते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं दो किलोमीटर का ही सही। हवाईजहाज ही तो उड़ाना है। तो ये इनको पता ही नहीं था कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए रनवे की लंबाई पांच किलोमीटर चाहिए दो किलोमीटर में उड़ा दिया और हवाई जहाज आसमान में तो उड़ा नहीं यही जमीन में रगड़े खा रहा है अभी तक। अरे भई तैयारी कर लेते थोड़ी सी कुछ पढ़े लिखे लोगों से सलाह ले लेते। जीएसटी पर रोज कानून बदल देते हैं। उसके बाद लेकर आये एफडीआई। हमें भी याद है रोज पुतले जलाते थे एफडीआई के इनमें से भी कुछ नेता बैठे हैं यहां पर। अगर इस देश में एफडीआई आ गए तो आग लगा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। देश गुलाम हो जाएगा। व्यापार खत्म हो जाएगा। कहते हैं अगर 51 परसेंट एफडीआई आ गई तो देश गुलाम हो जाएगा तो इसके लिए क्या करें कहते हैं हम सौ परसेंट लेकर आएंगे ताकि गुलामी से बच सकें। अब पूछा गया भई सौ परसेंट एफडीआई आई अब क्या होगा कहते हैं सिंगली ब्रांड है सर, सिंगली ब्रांड। वो क्या होता है। कहते हैं

मल्टीपल ब्रांड नहीं अलाउ किया हमनें सिंगल ब्रांड अलाउ किया। मैंने कहा ये कैसे हुआ। कहते हैं जी न एक ही ब्रांड के अलाउड करेंगे। मैंने कहा अच्छा। अगर एक गली में दस दुकान खुल गई तो दस ब्रांड हो गये। कहते हैं उसका हम क्या कर सकते हैं भई। तो मल्टीपल ब्रांड का इन्होंने रास्ता निकाला एक माल में दस दुकानें खोल लो तो मल्टीपल ब्रांड हो गई। अरे दुनियां का कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो यहां नहीं मिलेगा और सबसे बड़ी बात इस दीवाली पर देखियेगा 6 महीने इन्होंने केम्पेन चलाया 3 महीने केम्पेन चलाया कि चाइना का माल मत खरीदना जी और चलाना कब चालू करा जब इनके सारे के सारे जो इनके साथी हैं जिन्होंने हजारों करोड़ों का माल चाइना से इम्पोर्ट कर लिया। जब पटरी वालों को बेच दिया उसके बाद कहते हैं कि माल मत खरीदो जी। तुम्हारा तो माल बिक गया अब कहते हैं उसी चाइना का माल यही बीजेपी की सरकार एफडीआई इन रिटेल के नाम से उनके शोरूम से डायरेक्ट बिकेगा हिन्दुस्तान के अंदर आप देखते रहियेगा। अभी मेरे पास एक व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल आया था। उन्होंने मुझे बताया एक प्रिय सन है इनकी सरकार का। केन्द्र सरकार कहती है बार बार हर चीज 2022 हम खुद देखते हैं भई 2019 में तो इलेक्शन होने हैं तुम 2022 की बात करते हो। कहते हैं 2022 की बात इसलिए कर रहे हैं अगर 2019 में सबकुछ कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा क्या मतलब। कहते हैं जो इस देश के अंदर हमने न 2022 तक आधे व्यापार बंद करने हैं। मैंने कहा ये क्या मतलब। कहते हैं बेकार के काम करने में लगे हुए हैं। एक ही तरह का काम। एक दुकान में जाओ सड़क के ऊपर सौ दुकानें हैं उनमें एक ही तरह का माल बिक रहा है। क्या जरूरत है मैं समझा नहीं जी। कहते हैं हिन्दुस्तान युनिलीवर कंपनी इतनी बड़ी कंपनी साबुन बनाती है सारे वही साबुन बेच रहे हैं अलग अलग दुकानों की जरूरत क्या है एक ही बेच लेगा न और मैंने कहा बाकी कहां जाएंगे कहते हैं

उसके यहां नौकरी करेंगे। तो अब इन्होंने ये निश्चय किया हुआ है कि 2022 तक हिन्दुस्तान के आधे व्यापार जिसमें इंडस्ट्री भी शामिल है। जिसके अंदर दुकानें भी शामिल हैं उनको बंद करके दिखाएंगे और ये सारा इस सदन के सामने मैं पूरे होशहवाश में कह रहा हूं आप लिखकर रख लीजिएगा कम से कम आधे व्यापार बंद होने वाले हैं। अब ये कहते हैं के उसके बंद करने का फायदा क्या होगा। बंद करने का फायदा होगा हिन्दुस्तान को बनाएगें ये अफ्रीका, जैसे घाना है, कांगो है, कैमरून है, इथेापिया है, जिरिया, लीबिया। कारण है इसका राजनीतिक कारण है। इसकी सोच को मैं सलाम करता हूं। ये कहते हैं या तो बड़े–बड़े लोग होने चाहिए या बिल्कुल गरीब लोग होने चाहिए। कहते हैं अगर बडे लोग होगे तो इनके साथ पार्टियां करेंगे इनके साथ बैठेंगें इनके साथी है इनके दरबारी है इनके। और गरीब को तो मैने जो मुर्गी वाली कहानी सुनाई बाद में दिखाएगें जी देखो रोटी तो मिल गई दाना तो मिल गया, जिंदा तो हो ये क्या कम है। इनको बिल्कुल पसंद नहीं है ये पढ़े लिखे लोग। कहते हैं जी मिडिल क्लास ने बडा स्पोर्ट किया था 2014 में पर बडे भरोसे के लायक नहीं है। कहते है जो पढ़े हुए लोग है ना जी ये किसी के नही हैं। पढ़े लिखे आदमी में तो पता नहीं कल को क्या जागृति आ जाए। कहते हमें नहीं चाहिए ये फालतू के लोग। मेरा एक मित्र है एक बडी कम्पनी में एक करोड का पैकेज मिलता है अभी थोडे दिन पहले आया था। मुझे अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आया। बडा परेशान। मैने कहा कि भई क्यूं परेशान है तुझे तो एक करोड रूपये साल के मिलते हैं इससे ज्यादा क्या लेगा। कहता जैन पता नहीं किस दिन निकाल दें। मैने कहा क्यूं। कहता है बिजनेस का माहौल बड़ा खराब है। मैने कहा ऐसा क्या हो गया। कहता है पिछले तीन चार साल के अंदर देश के अंदर बिजनेस का माहौल बचा ही नहीं है। और किस दिन नौकरी से निकाल दें किसी को पता नहीं है। तो ये बीजेपी

ऐसा क्यूं कर रही है। जिस संस्थान ने जिन लोगों ने इनको बनाया जिन लोगों ने 70 साल से 60 से इनको सपोर्ट किया उनको ये बर्बाद करने में क्यूं लगे हुए हैं। इसके पीछे भी इनकी रणनीति है। ये कहते है कि जी हिन्दुस्तान में कितने व्यापारी हैं। बडे–बड़े सरमायेदारों को छोड दीजिए। वो व्यापारी नहीं है वो इनके पार्टनर्स हैं। नहीं इनके पार्टनर है। नाम दे ही रहे है पीछे। जो भी कह लीजिए व्यापार के पार्टनर, सत्ता के पार्टनर सब चीजों के पार्टनर हैं वो। इसका कारण बताया मुझे। सर मैने बोल दिया ना उस दिन फंक्शन में आपने क्या बोला था। आप सुन नहीं पाओगे उठकर भाग जाओगे।

अध्यक्ष महोदयः जैन साहब उनसे मत बोलिए। प्लीज।

शहरी विकास मंत्रीः अभी मैंने कुछ कहा नहीं है ऐसे ही बता रहा हूं। नही ंतो नाम लेना पड जाएगा। सर जी दूंगा

अध्यक्ष महोदयः जवाब गोपाल जी ने दे दिया। गोपाल जी ने जवाब दे दिया है पूरा।

शहरी विकास मंत्रीः हाँ सुन लीजिए। इसके अंदर उनकी बताई गई बात कि ऐसी क्या चीज है कि व्यापारियों के पीछे क्यूं पडे हैं। कहते हैं हम व्यापारियों के पीछे नहीं पडे हैं हम किसानों के भी पीछे पडे हैं। मैने कहा क्या मतलब। कहते हैं हमारी सरकार बनने के बाद देखो कितने किसानों ने आत्महत्या की। आज तक कभी किसी ने नहीं की उससे ज्यादा हमने करा के दिखा दी। और अब हम व्यापारियों की भी आत्महत्या करके दिखाएंगे। ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। सबके लिए हम बराबर है। अब कैसे हुआ इनकी बताता हूं थ्योरी क्या है। कहते है सारे देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा पांच प्रतिशत व्यापारी हैं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः जैन साहब आप कन्टीन्यू करिए। प्लीज।

शहरी विकास मंत्रीः चलो बीच में पहले इनका एक सुना देता हूं। अभी प्रवीण देशमुख जी ने इस बात पर दोबारा आता हूं सुनने का माद्दा नहीं है थोडा सा बीच–बीच में सुना देता हूं। अभी बताया कि इनके क्षेत्र में एक पार्किंग बन रही है। जिसके अदर 104 करोड रूपये लग चुके हैं। अब उसका एस्टीमेट बढाकर 200 करोड रूपये कर दिया गया है। मैने प्रवीण जी को बुलाया मुझे विश्वास नहीं था कि ये पार्किंग 200 करोड की कैसे बन सकती है। मैंने कहा कितने कारों की पार्किंग बन रही है भई। कहते है जी 350 कारें। यानि एक कार की पार्किंग 70 लाख रूपये। तो एमसीडी के तो ये कारनामे हैं। सत्तर लाख की किसी के पास कार है इस सदन के अंदर। नहीं सदन में जो लोग बैठे हुए है उनके पास तो नहीं है। एक हैं जो बाहर है उनके पास हो सकती है। तो सत्तर लाख रूपये की पार्किंग बनाते हैं और आठ साल हो गए है बनती नहीं है इनसे। ये इनको तो जो भी बोलूंगा सुनना मुश्किल है। इन लोगों ने कहा कि दो करोड़ रोजगार हर साल देंगे। दो करोड रोजगार तो दिये नहीं। करोड़ों लोगों को रूला जरूर दिया। हर आदमी को रूला दिया। सर जी आपका टाइम हो गया आप जाओ ना।

अध्यक्ष महोदयः आप करिए सत्येन्द्र जी कन्कलूड करिए प्लीज। जैन साहब कन्कलूड करिए प्लीज।

... (व्यवधान)

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसे मैने अभी बताया कि पहले तो ये लेकर आए नोटबंदी उसके बाद जीएसटी उसके बाद ले आए एफडीआई इन रिटेल। और जो वो कहते है ना शव को उठाने के लिए

चार की जरूरत पडती है और चौथी चीज ले आए सीलिंग। कि भई चारों पूरे होने चाहिए सारी सीलिंग करके इनको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए इनको बर्बाद कर दिया जाए। किसी लायक छोडा ना जाए। और मेरे कई साथियों ने बताया कि सीलिंग का मकसद क्या है। सीलिंग का मकसद है पैसे इकट्ठे करना। अभी बताया था हमारे साथी ने कि लिस्ट में से पचास कर रहे हैं और पचास बिना लिस्ट के कर दी सीलिंग। और उनसे लाखों रूपये लेकर खोल दी। लिस्ट में तो थी नहीं सीलिंग करी कौन। अभी शिवचरण जी न बताया किस्सा कि दो दुकानें सील कर दी, 28 दिन तक खोली नहीं। पचास लाख रूपये ले लिए। तो इनका मकसद है पैसे इकट्ठे करना और कुछ नहीं है। ये कहते हैं जी पैसे इकट्ठे कर लो जब इलैक्शन आएगा तब की तब देखी जाएगी। इनको तो सबकुछ इलैक्शन ही दिखाई देता है। अगर मैं बोल रहा हूं तो वो भी इलैक्शन दिख रहा है। इनको तो इलैक्शन के अलावा कुछ दिखता नहीं है। मेरे एक मित्र हैं अभी आए दो दिन पहले। कहते है बीजेपी की तारीफ करनी पड़ेगी। मैने कहा किस बात की। कहता है बडे फोक्सड हैं। मैने कहा किस जिस के फोक्सड हैं। कहते हैं जी इलैक्शन के। कहते है उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। बस इलैक्शन से लेना देना है। कहते है जी बस इलैक्शन और इलैक्शन के बाद इलैक्शन उसके बाद इलैक्शन। बाकी काम से कोई लेना देना नहीं है। कहते है काम करना नहीं। जनता को कहते हैं ज्ञान देना है और बाकी सब कुछ ऐसे चलता रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि सड़कों की सीलिंग दिल्ली सरकार अगर 351 रोडों को नोटिफाई कर देती तो नहीं होती। आदरणीय मंत्री जी अभी बताया कि जितनी भी जगह सीलिंग चल रही है उसमें 351 रोड है ही

नहीं। पहली बात, दूसरी बात ये सारी सडके 2007 के अंदर लिस्ट बनाकर दी गई थी। तब भी एमसीडी के अंदर बीजेपी थी और सबसे बडी बात चलो बीजेपी हो कांग्रेस से इनकी ना बनी हो। या बनी हो जो भी हो कारण हो सकते है। 2014 में 14 फरवरी 2014 से लेकर 14 फरवरी 2015 तक एक साल तक दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था। इनकी अपनी सरकार थी। समझ से बाहर है तब इन्होंने नोटिफाई क्यों नहीं की। ऐसा क्या कारण था इन्होंने नोटिफाई नहीं की इन्होंने। जब एमसीडी के इलैक्शन आ रहे थे तब तो कभी मुद्दा नहीं उठाया इन्होंने। और जितने भी पत्रों के नम्बर दिये हैं इन्होंने डेट दी है वो सारे के सारे उसके बाद के हैं जो मिटिंग हमने बुलवाई। हमने इनसे कहा कि सारे कागज तो पूरे कर दो। मास्टर प्लान के हिसाब से सारे पेपर तो दे दो। जो पत्र अभी विजेन्द्र जी आपको दिखा रहे थे वही पत्र मेरे पास लेकर आए थे।उसमें क्या लिखा जाता है कि जी आप इनको नोटिफाई कर दो। नोटिफाई तो किसी कानून में ही होगी। उस कानून के हिसाब से जवाब तो देना पडेगा। नोटिफिकेशन ऐसे तो है नहीं कि जी आप बिना किसी कानून को माने कर दीजिएगा। मैने कहा जी ठीक है मैं कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बैठे है आप परसों तक मुझे सारी चीजें दे दीजिए। कहते हैं अभी दे देते हैं। मैने कहा आप बैठ जाइए। दो–तीन घंटो बैठ जाओ दो तीन घंटों में मुझे अभी बनाकर दे दो। सारे ऑफिसर थे। वो कहते हैं कि हम परसों दे देंगे। हमने कहा मास्टर प्लान के हिसाब से जवाब देना है। जो भी चीजें है सारी इकट्ठी करके दे दीजिए आप एक बारी में। फिर उन्होने कहा चार दिन दे दीजिएगा। मैने कहा ठीक है चार दिन ले लीजिएगा। फिर कहते है एक हफ्ता दे दीजिएगा। मैने कहा एक हफ्ता ले लीजिएगा। नहीं नहीं कहा दस दिन दे दीजिएगा। तो 22 तारीख की डेट 22 जनवरी की डेट तीनों मेयर ने

खुद मेरे आफिस में बैठकर खुद कहा है कि हमें 22 तारीख की डेट दी जाए कि ताकि हम जवाब दे सके। अभी तक इनका कोई जवाब नहीं आया है। इनको पांच–पांच पत्र लिखित में भेजे गए हैं। उसके बावजूद उन्होने कोई जवाब नहीं दिया है। सिर्फ ये लिखकर दे देते हैं इसको नोटिफाई कर दिया जाए। और जहां तक ये कहते हैं कोर्ट का बीच में दखल नहीं होना चाहिए। ये भी ये खुद बताकर गए है मिटिंग के अंदर कि कोर्ट के केस भी चल रहे हैं। इन्होंने ही बताया है तो इसका मतलब इनको सब पता है। और ये राजनीति के अंदर लेकर आ रहे हैं। जो 351 रोड इसमें कोई ईश्यू नहीं है। परन्तु मुझे बडे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो धमकी विजेन्द्र गुप्ता जी अभी देकर गए हैं। जिसको मैं सभी साथियों को अवगत कराना चाहता हूं। उन्होंने एक नई बात उठाई है कि जो 1700 अन–आथोराईज्ड कालोनिज़ हैं वो धमीकी देके गए हैं उसमें भी सीलिंग चालू करायेंगें। ध्यान देना चाहिए उनकी बात का ये लोग पहले इशारे के अंदर विधानसभा के अंदर बोलते हैं बाद में वोही काम होता है। आज वो बोल के गये हैं और मुझे बड़ा दुख है कि अगर ऐसी धमकी दे रहे हैं अगर दिल्ली के अंदर उन्होंने अन–आथोराईज्ड कालोनिज़ के अंदर सीलिंग करी तो इनकी ईंट से ईंट बजा देंगें छोड़ेगें नहीं इनको। अगर इन्होंने अन–आथोराईज्ड कालोनिज़ की तरफ आंख उठाकर देखा तो इनकी हम छोड़ेंगें नहीं और इन लोगों को क्योंकि इन्होंने खुद बताया है कि चाहेंगें तो सीलिंग बंद भी करा सकते हैं केन्द्र सरकार के पास जायें आज ही बंद करा सकते हैं इनकी पावर है। अगर केन्द्र सरकार इनके कहने से सब काम करती है तो अभी भी जाके करा सकते हैं दो घंटें के अंदर करा सकते हैं। धन्यवाद, जयहिंद, जय मां।

अध्यक्ष महोदयः बहुत–बहुत धन्यवाद । माननीय सदस्यों द्वारा अल्पकालिक चर्चा के दौरान सदन में व्यक्त की गई भावनाओं पर विचार करते हुए कंवर्जन चार्जिज की वसूली, इसके उपयोग तथा अन्य संबंधित विषयों की जांच करने और इस संबंध में रिपोर्ट देने के लिए मैं मामला सुश्री भावना गौड़ के सभापत्तिव वाली दिल्ली नगर निगमों के विशेष समिति को सौंपता हूं । मैं दिल्ली नगर निगम के आयुक्तों और अन्य सभी अधिकारियों को समिति द्वारा बुलाये जाने पर उपस्थित होने और साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा सत्यता बताने का निर्देश भी देता हूं। समिति इस मामले के संबंध में अपनी रिपोर्ट अगले सत्र की पहली बैठक में प्रस्तुत करेगी। उम्मीद है सदन इससे सहमत है। सुश्री राखी बिड़ला, श्री सौरभ भारद्वाज पर्सनल संदर्भ समिति का विशेष प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुंत करेंगें।

सुश्री राखी बिड़लाः धन्यवाद अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से प्रश्न एंव संदर्भ समिति का विशेष प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करती हूं। धन्यवाद।[1]

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, क्वैश्चन एंड रैफरेंस कमेटी के अंदर एक प्रश्न था।

अध्यक्ष महोदयः हो गया हो गया वो कल ले लेंगे अब समय हो गया है ये 55 का जो नोटिस मिला हुआ है शिवचरण जी का, अलकाजी का, सौमदत्त जी का इसको कल लेंगें। मैं आज थोड़ा एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही है सदन में, माननीय राज्यसभा के सदस्य चुने गए तीन सदस्य दिल्ली के विधायकों का दायित्व था उनको चुनने का, उनको चुना गया, निर्विरोध चुना गया। आज जिस ढ़ंग से कपिल मिश्रा ने एक राज्यसभा के

---

1. ***www.delhiassembly.nic.in*** पर उपलब्ध।

सदस्य को यहां सदन में वेल में आकर अपमानित करने का प्रयास किया और जो दिल्ली के व्यापारी वर्ग से दिल्ली के नहीं, पूरे भारत के व्यापारी वर्ग से जुड़े अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए, मुझे आश्चर्य तो इस पर हुआ के विजेन्द्र जी भी व्यापारी हैं, मैं भी व्यापारी हूं, हममें से बहुत व्यापारी हैं उसमें कपिल मिश्रा की उस घटना में आपने साथ दिया।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः एक सैंकेंट मैं बहुत क्लीयर बोल रहा हूं, ठीक है पोलिटिक्स नहीं कर रहा। आज सदन में, आज सदन में दिल्ली पुलिस कर्मियों के विरूद्व पूरी तरह आधारहीन और अभद्र आरोप लगा है। उन्होंने कहा कि कपिल मिश्रा को दिल्ली पुलिस कर्मियों द्वारा उस समय पीटा गया जब उसको सदन के वेल से मेरे निर्देशानुसार बाहर निकाला जा रहा था। श्री विजेन्द्र गुप्ता द्वारा एक ऐसी घटना की गलत व्याख्या की गई जो पूरे सदन की नज़रों के सामने हुई है। इससे नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा में कोई बढ़ोतरी नहीं है। मैं ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान की कड़ी निंदा करता हूं। दिल्ली पुलिस कर्मियों की अत्यधिक सराहना करता हूं कि जो ऐसे उत्तेजनापूर्ण माहौल में भी कठिन दायित्वों को पूरा करते रहे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय जीः अब सदन की कार्यवाही 17 जनवरी, 2018 को अपराहन 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बहुत–बहुत धन्यवाद।

(अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही 17 जनवरी, 2018 को अपराहन 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्सs, 2266/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।